लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला
Fourth Series

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
04-1-84
Parliament Library

खंड 4, 1967 / 1889 (शक)
Volume (IV), 1967/1889 (Saka)

[6 जून से 19 जून, 1967 / 16 ज्येष्ठ से 30 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]
[June 6 to June 19, 1967/ Jyaistha 16 to Jyaistha 30, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)
(Volume (IV) Contains Nos. 11 to 20)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

2663

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 1 मंगलवार, 6 जून, 1967/16 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No 1–Tuesday, June 6 1967/Jyaistha 16, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ RAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
301 मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference ..	1356-1358
302 कार्बनिक खाद	Organic Manure	1358-1371

प्र. सू. प्रश्न S. N. Q.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.		
308 बम्बई के गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Bombay Dock Workers	1371-1372
309 मरमागोआ बन्दरगाह	Marmagoa Port	1372
310 बन्दरगाहों में अनाज को उतारना चढ़ाना	Handling of Foodgrains at Ports	1372-1373
311 भारत को खाद्य दान	Food Donations to India ..	1373-1374
312 मध्य प्रदेश में अकाल	Famine in Madhya Pradesh ..	1374-1375
313 बड़ी संख्या में लोगों का गांवों से नगरों में चले जाना	Exodus of Population from villages to cities	1375-1376
314 बिहार के मुख्य मंत्री की सोवियत संघ से अपील	Bihar C. M,s Appeal to USSR	1376
315 चीनी के भावों में समानता	Uniformity in Rates of Sugar	1376
316 भारतीय खाद्य निगम	Food corporation of India ..	1377
317 कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना	Second Ship building Yard at Cochin	1377
318 चीनी उद्योग का लागत ढांचा	Cost Structure of Sugar Industry	1377-1378
319 बस दुर्घटना यात्रियों को प्रतिकर	Compensation to Bus Accident Victims	1378
320 गेहूं नीति सम्बन्धी कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन	Report of Agricultural Prices Commission on Wheat Policy	1378-1379
321 भूमि अधिग्रहण विधियों के अध्ययन के लिए समिति	Committee to Study Land Requisition Laws	1379
322 खाद्य पदार्थों को चोरी छिपे चीन ले जाना	Smuggling of Foodstuffs to China	1379
323 वाईकाउन्ट विमान	Viscounts .. .. — ..	1379-1380
325 माल भाड़ा दरें	Freight Rates	1380
326 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई	Supply of Milk by DMS ..	1381-1382
327 पटसन, धान तथा मोटे अनाज के समर्थन मूल्य	Support Prices for Jute, paddy and Coarse Grains	1382

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता. प्र. संख्या/U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
328	पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange earnings from Tourist..	1382-1383
329	हवाई अड्डों पर प्लेटफार्म टिकट	Platform Tickets at Airports ..	1383
330	बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों से प्रव्रजन	Migration from Drought affected areas of Bihar and U. P.	1383-1384
अता. प्र. संख्या/U. Q. Nos.			
1493	दक्षिण बिहार में नल कूपों का लगाया जाना	Installation of Tube wells in South Bihar	1384-1385
1494	हरियाना के लिये चीनी का कोटा	Sugar Quota for Haryana ..	1385
1495	ट्रैक्टरों के पुर्जों के आयात पर प्रतिबन्ध	Ban on Import of Spare Parts of Tractors	1385-1386
1496	देश में नल कूप	Tube wells in the Country ..	1386-1387
1497	पर्यटकों के लिये विमान चार्टर करना	Tourist Charter	1387
1498	हरियाना में खाद्यान्न के मूल्य	Price of Foodgrains in Haryana	1387-1388
1499	खाद्यान्न की आवश्यकता	Foodgrains requirement ..	1388
1500	जहाज तथा उनका टन भार	Ships and their tonnage ..	1388
1501	भारतीय खाद्य निगम	Food corporation of India ..	1388-1389
1502	फसल ऋण योजना	Crop credit scheme	1389
1503	दिल्ली में सड़क पर फीस की उगाही	Collection of Road Tax fees in Delhi	1390
1504	पश्चिम बंगाल को मछली की सप्लाई	Fish Supply to West Bengal ...	1390
1505	पटना में गंगा नदी पर पुल	Bridge at Patna over River Ganga	1390
1506	चावल का आयात	Import of Rice	1391
1507	विधि शिक्षा सम्बन्धी परिषद्	Legal Education Council ..	1391
1508	खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार	Buffer Stock of Foodgrains ..	1391
1509	बिहार में सहायता कार्यों के लिये अमरीका का उपहार	US Gift for Bihar Relief ..	1391-1392
1510	बिहार को चीनी की सप्लाई	Sugar Supply to Bihar ..	1392-1393
1511	अमरीकी में भारतीय वैज्ञानिक	Indian Scientists in USA ..	1393
1512	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मछली उद्योग का विकास	Development of Fishing Industry in Fourth Plan	1393-1394
1513	कोयम्बटूर अट्टापड़ी–मन्नारकड आदिम जातीय क्षेत्र	Coimbatore Attappadi Mannarkad Tribal Area	1394
1514	खाद्य तेलों के मूल्य	Prices of Edible Oils	1394-1395
1515	बिहार के चीनी के कोटे में कटौती	Cut in sugar quota of Bihar ..	1396
1516	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi ..	1396 1397
1517	सुपर बाजार, नई दिल्ली में माल पड़ताल (स्टाक टेकिंग)	Stock taking in Super Bazar, New Delhi	1397

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1518	सुपर बाजार, नई दिल्ली में क्रय अधिकारी	Purchase officers in supper bazar New Delhi	1398
1519	मध्य प्रदेश में बन पर आधारित उद्योग	Forest Based Industries in Madhya Pradesh	1398
1520	देशी गेहूँ का स्टाक	Indigenous Wheat Stock	1398-1399
1521	किसानों को ऋण	Loan to Farmers	1399
1522	कुमारकाम वेलचूहर सड़क	Kumarakam Velchoor Road ..	1399-1400
1523	सघन कृषि जिला कार्यक्रम	Intensive Agriculture District Programme	1400
1524	चीनी मिलों को राज सहायता	Subsidy to sugar Mills	1400
1525	पारादीप पत्तन	Paradeep Port	1401
1526	कोणार्क (उड़ीसा) में पर्यटन की सुविधाएं	Tourist Facilities in Konarak (Orissa)	1401
1527	सूखा निरोधक अध्ययन बोर्ड	Drought Prevention Studies Board..	1401-1402
1528	पश्चिम बंगाल में वन शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centre for Forest Instructors in West Bengal ..	1402
1529	मैरीन टैक्नोलाजीकल डिप्लोमा कोर्स	Marine Technological Diploma Course..	1402-1403
1530	राजस्थान में आयातित खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Imported Foodgrains to Rajasthan	1403
1531	पर्यटनों तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय के सचिव तथा महानिदेशक, पर्यटन	Secy. Ministry of Tourism & C. A. and Director General Tourism	1403-1404
1532	एयर इन्डिया के कर्मचारियों के लिये मकान बनाना	Construction of Houses for Air India Employees	1404
1533	वनरोपण योजना	Afforestation Schemes	1404-1405
1534	अकाल संहिता	Famine Code	1405
1535	कृषि विकास के लिये पश्चिम जर्मनी से सहायता	Aid from West Germany for Agricultural Development ..	1405-1406
1536	बीज फार्म	Seed Farms	1406
1537	विमान दुर्घटनाएं	Air Accidents	1406
1538	सुपर बाजार नई दिल्ली में सस्ती कीमत वाली वस्तुएं	Low priced consumer goods in Super Bazar, New Delhi ..	1406-1407
1539	दिल्ली परिवहन का पुनर्गठन	Re-organisation of Delhi Transport Undertaking	1407-1408
1540	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से वाईकाउंट विमानों का हटाया जाना	Replacement of IAC Viscounts	1408
1541	रबी की फसलों के मूल्य	Prices for Rabi Crops	1408-1409
1542	गन्ने का मूल्य	Sugarcane Price	1409
1543	कृषि अनुसंधान केन्द्र	Agricultural Research Centres	1409-1410

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd		
1544	गिर के बब्बर शेर	Gir Lions	1410
1545	गिरनार में रज्जु पथ	Ropeway at Girnar	1410–1411
1546	मूल अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Judgement of Supreme Court on Fundamental Rights ..	1411
1547	रूसी ट्रैक्टरों के ऊंचे मूल्य	High Prices of Russian Tractors	1412
1548	राजस्थान में बाजरा तथा ज्वार की किस्मों का विकास	Development of Bajra and Jawar Varieties in Rajasthan.. ..	1412
1549	सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर	Central Arid zone Research Institute Jodhpur	1412–1413
1550	पर्यटक केन्द्रों के बारे में वृत्त चित्र	Documentary Film of Places of Tourist Interest	1413
1551	दिल्ली में चीनी की बोरियों का पकड़ा जाना	Seizure of Sugar Bags in Delhi	1413–1414
1552	मुख्य/गौण मार्गों पर इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा वाइकाउंट विमानों का हटाया जाना	Replacement of IAC Viscount Aircraft on major/Secondary routes	1414
1553	मध्य प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के पद का समाप्त किया जाना	Abolition of Post of Block Development Officers in Madhya Pradesh	1414–1415
1554	विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists..	1415
1555	रूस के कृषि विशेषज्ञ	Soviet Agricultural Experts ..	1415–1416
1556	गोवध पर प्रतिबन्ध	Ban on Cow Slaughter ..	1416
1557	उड़ीसा द्वारा केन्द्र को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Centre by Orissa	1416–1417
1558	उड़ीसा में पर्यटन विकास निगम के कार्यकलाप	Activities of Tourist Development Corporation in Orissa	1417
1559	उड़ीसा में कृषि विकास योजना	Agricultural Development Schemes in Orissa..	1417–1418
1560	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट	Paradeep port Trust	1418
1561	काली मिर्च का मूल्य	Price of Pepper	1418
1562	राज्यों को प्रति व्यक्ति चीनी की सप्लाई	Per Capita Supply of Sugar to States	1418–1419
1563	हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन	Food Production in Himachal Pradesh	1419
1564	विदेशी पर्यटकों के लिए चार्टर उड़ान	Charter Flights for Foreign Tourists	1419–1420
1565	वर्षा की सम्भावनाएं	Rain Prospects	1420
1566	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों से जीपों का वापस लिया जाना	Withdrawal of Jeeps from NES Blocks	1420–1421
1567	पश्चिम बंगाल में कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of certain commodities in West Bengal ..	1421
1568	कृषि ऋण निगम	Credit Agricultural Corporations	1421–1422

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1569	केरल के छोटे पत्तनों का विकास	Development of Minor Ports in Kerala	1422
1570	चीनी के कारखानों द्वारा किसानों को देय धन	Dues to Farmers from Sugar Factories	1422–1423
1571	इम्फाल के लिए फाकर फ्रैंडशिप विमान सेवा	Fokker Friendship service to Imphal	1423
1572	'नेहरू लोक'	"Nehru Lokas"	1423–1424
1573	गायों पर प्रतिजीवाणु पदार्थों का प्रयोग	Use of Anti biotics on Cows	1424
1574	कनाडा सरकार द्वारा दिये गये दुग्ध पाउडर का मार्ग में गुम हो जाना	Loss of Milk Powder supplied by Canadian Govt. in transit ..	1424–1425
1575	चीनी का निर्यात	Export of sugar..	1425
1576	उड़ीसा में उद्यान विज्ञान का विकास	Development of horticulture in Orissa	1425
1577	उड़ीसा में गन्ने की खेती	Sugarcane cultivation in Orissa	1426
1578	उड़ीसा को पशु पालन के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Orissa for Animal	1426-1427
1579	राज्यों में भण्डागार	Warehouses in States	1427–1428
1580	उड़ीसा में कृषि अनुसन्धान परियोजनाएं	Agriculture Research Projects in Orissa	1428
1581	"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के लिये उड़ीसा को अनुदान	Grant to Orissa for "Grow More Food" Campaign ..	1428–1429
1582	भारत पर्यटन विकास निगम	India Tourism Development Corporation	1429
1583	फलों के बागों की भूमि	Area under fruit crops	1430
1584	लक्कदीव में धान की खेती	Paddy cultivation in Laccadives	1430
1585	राजस्थान को चीनी तथा गेहूँ की सप्लाई	Wheat and sugar supply to Rajasthan	1430–1431
1586	कृषि प्रधान शिक्षा	Agriculture oriented Education	1431
1587	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	Hindustan Shipyard ...	1431–1432
1588	केन्द्रीय सड़क बोर्ड	Central Road Board	1432
1589	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	1432
1590	प्राथमिक क्रय विक्रय समितियां	Primary Marketing Societies ..	1432–1433
1591	जापान से चावल मिल मशीनों का आयात	Import of Rice Mill Machinery from Japan	1433
1592	बिहार की सहायता के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आयात निधि से सहायता	UNICEF Aid for Bihar Relief	1433–1434
1593	उड़ीसा के असका में कोआपरेटिव शूगर मिल्स	Cooperative sugar Mills at Aska in Orissa	1434
1594	रूसी ट्रैक्टरों का आयात	Import of Russian Tractors ..	1434–1435

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1595	ट्रैक्टरों की आवश्यकता	Requirement of Tractors ...	1435–1436
1596	दिल्ली शिवपुरी नेशनल पार्क विमान सेवा	Delhi Shivpuri National Park Air Service	1436
1598	फसलों को क्षति	Damage to Crops .. –	1436
1599	संकर तिलहन का उत्पादन	Growth of Hybrid Oilseeds ...	1437
1600	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिये मकान	Housing Accommodarton for IAC Employees	1438
1601	कृषि संस्थायें	Agricultural Institutes ...	1438
1602	बिहार को उपहार में दिया गया खराब दुग्ध पाउडर	Damage of gift milk powder Supplied to Bihar...	1438–1439
1603	आसाम में भारतीय खाद्य निगम का कार्य	Functioning of Food Corporatation of India in Assam ..	1439
1604	स्वीडन द्वारा उर्वरक का दान	Donation of fertilizers by Sweden	1439–1440
1605	भारतीय नौवहन निगम	Shipping Corporation of India	1440
1606	एपीजे शिपिंग लाइन्स	Apejay Shipping lines ..	1440–1441
1607	पी. एल. 480 के अन्तर्गत अनाज की सप्लाई	Food Supply under PL 480 ..	1441
1608	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	1441–1442
1609	अण्डमान के मुख्य वन संरक्षक द्वारा की गई खरीद	Purchases made by Chief Conservator of Forests Andaman	1442
1610	अण्डमान की इमारती लकड़ी की जहाज से ढुलाई	Shipment of Andaman Timber	1442
1611	अण्डमान की इमारती लकड़ी (टिम्बर)	Andaman Timber .. –	1443
1612	बर्मा से चावल	Rice from Burma	1443
1613	अविकसित क्षेत्रों में चीनी मिलें	Sugar mills in undeveloped Areas	1443–1444
1614	मद्रास को दिये गये खाद्यान्न के लिए राज-सहायता	Subsidy on Food Supplied to Madras..	1444
1615	चीनी उद्योग विकास परिषद्	Development council of Sugar industry	1444-1445
1616	आगरा बम्बई राजपथ पर मोटल	Motels on Agra Bombay Highway	1445
1617	जमुना के पार दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के डिपो	DMS milk Depots beyond Jamuna..	1445
1618	कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों की उपरि सीमा	Ceiling on Prices of Agricultural Commodities	1446
1619	टूरिस्ट बसें	Tourist Buses	1446
1620	पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	Development of Hill Areas	1446

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1621	सरकारी क्षेत्र में होटलों का निर्माण	Construction of Hotels in Public Sector..	1446–1447
1622	मनीपुर को खाद्यान्न की सहायता	Food Subsidy to Manipur ..	1447
1623	बिहार में सहकारी समितियों द्वारा लिया गया ऋण	Loan taken by Cooperative Societies in Bihar	1447–1448
1624	बिहार में झीलों का विकास	Development of lakes in Bihar	1448
1625	पशुओं को टीके लगाने की दवा	Vaccine for Cattle ..	1448–1449
1626	विमान चालक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये विमान चलाने के घंटों की शर्त	Flying hours repuired for Pilot Licence	1449
1627	मध्य प्रदेश में आर्थिक और अन्तर्राज्यिक महत्व की सड़कें	Roads of Economic and Inter State Importance in Madhya Pradesh	1450
1628	मध्य प्रदेश में सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना	Declaration of Roads as National Highuays in Madhya Pardesh	1450
1629	आम चुनावों पर खर्च	Expenditure on General Elections	1450–1451
1630	पर्यटक होटल	Tourist Hotels	1451–1452
631	मुजफ्फरपुर भोवाड़ा विमान सेवा	Muzaffarpur Bhowara Air Service	1452
1631	मध्य प्रदेश में फ्लाइंग क्लब	Fiying Clubs in Madhya Pradesh	1452–1453
1632	खजुराहो में चन्द्रा होटल	Chandra Hotel at Khajuraho ..	1453
1633	कृषि शिक्षा	Agricultural Education ..	1454
1635	तृतीय श्रेणी के गेहूं का आयात	Import of III Grade Wheat ..	1454
1636	चने की दाल के अत्यधिक मूल्य	Exorbitant Prices of gram dal	1454–1455
1637	खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains	1455
1638	उड़ीसा में सूखे की स्थिति	Drought conditions in Orissa	1455–1456
1639	मिर्जापुर में गंगा पर पुल	Bridge over Ganga at Mirzapur	1456
	राज्य सभा के एक सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार के बारे में	Re. Motion of Privilege against a Member of Rajya Sabha ..	1457
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1457–1459
	ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Call Attention Notices (Query)..	1459–1460
	सामान्य आय-व्ययक 1967–68 सामान्य चर्चा जारी	General Budget	1460–1470
	श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	

अता. प्र. संख्या/ U. S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTION—Contd		
श्री राणे	Shri Rane	
श्री प. राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	
श्री पें वेंकटासुब्बय्या	Shri P. Venkatasubbaiah	
श्री श्री अ. डांगे	Shri S. A. Dange	
पश्चिमी एशिया की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Stat-ment Re. Development in West Asia	1470–1478
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार 6 जून, 1967/ 16 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

Tuesday, June 6, 1967/Jyaistha 16, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रश्न संख्या ३०१ के बारे में

RE : Q. 301

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी।

Shri A. B. Vajpayee : Sir, before putting the question I want to raise a point of order. This question was earlier set for some other day and it was addressed to the Prime Minister. But on that day it was transferred for today and now I see that the Food Minister is to answer this question and not the Prime Minister. In view of this I want to know whether it is for the Food Minister to decide as to what persons are to be invited to the Chief Ministers Conference and what not. This should be decided by the Prime Minister and not by the Food Minister.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : माननीय सदस्य की भावनाओं का उचित आदर करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में इस स्थिति को स्पष्ट करने जा रहा था। सम्मेलन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा बुलाया गया था और शायद यही कारण था कि इसे हमारे मंत्रालय को भेजा गया।

Shri Madhu Limaye : Sir, this is not entirely true, what I notice is that the Prime Minister does not want to reply to our questions. What is the use of having such a dumb doll as the Prime Minister........**(Interruptions)**.

Some hon. Members : It is wrong.

Shri Madhu Limaye : She never gives the reply which she should. Simply shouting is of no avail. Make her learn how to speak........**(Interruption)**.

Shri Randhir Singh : It is absolutely wrong.

Shri Manubhai Patel : Shri Madhu Limaye should withdraw his words "dumb doll" in respect of the Prime Minister.

Shri Madhu Limaye : Can the spoken words be withdraw ? Truth is always bitter.

कुछ माननीय सदस्य उठे ।

अध्यक्ष महोदय : जबकि मैं बोल रहा हूं तो आप सब कृपया बैठ जायें । प्रश्न अभी आरम्भ नहीं हुआ है । आज की कार्यवाही व्यवस्था के प्रश्न से आरम्भ हुई है । वे चाहते हैं कि प्रधान मंत्री उत्तर दें । इस बात को दूसरे तरीके से नर्मी से भी कहा जा सकता था । यद्यपि यह असंसदीय नहीं है, फिर भी इस सभा में प्रयोग के लिये यह कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है । कोई भी व्यक्ति गूंगी गुड़िया नहीं है । यह उचित नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : Though there is a little bite in what say, yet the truth of it is unquestionable.........**(Interruption).** Don't try to be over faithful.

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

+

***301. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री प० गु० सईद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री भारत सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री शशि रंजन :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था,

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद को इस सम्मेलन में क्यों नहीं बुलाया गया था जब कि नागालैंड और मनीपुर जैसे छोटे राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस में बुलाया गया था, और

(ग) इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० एरिंग): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भूतकाल में अपनायी गयी प्रथा के अनुरूप, अप्रैल, 1967 में हुये सम्मेलन में भाग लेने के लिये संघ शासित प्रदेश दिल्ली का कोई प्रतिनिधि आमन्त्रित नहीं किया गया था । अतः दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद को आमन्त्रित नहीं किया गया था । कोई भेद-भाव नहीं किया गया ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, may I know who represented Delhi in this Conference and if the Chief Executive Councillor of Delhi was not invited, whether the Lt. Governor of Delhi was invited ?

खाद्य, **कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : श्रीमान्, जहां तक इस सम्मेलन का सम्बन्ध है दिल्ली प्रशासनिक क्षेत्र को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था क्योंकि यह विचार किया गया था कि जिन विषयों पर चर्चा की जानी थी वे दिल्ली प्रशासन के कार्य क्षेत्र में नहीं आते थे चूंकि दिल्ली के खाद्य की व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी केन्द्र ने अपने पर ले ली है। उस समय यह विचार था। विवाद में पड़ने की बजाये मैं कह देना चाहता हूं कि इस बीच एक नया परिपत्र जारी किया गया है कि यदि भविष्य में इस प्रकार के सम्मेलन बुलाये गये तो दिल्ली प्रशासन के उप राज्यपाल को बुलाया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question is whether the Lt. Governor will represent Delhi or the Chief Executive Councillor, who is elected by popular vote and in whose hands is the administration of Delhi.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : निमन्त्रण दोनों को दिया जाना चाहिये; ऐसा परिपत्र में है।

एक माननीय सदस्य : दोनों को ?

Shri N.S. Sharma : When Nagaland and Manipur were represented why Delhi was neglected in this manner ? As the Minister has said that this will not happen in future, is he prepared to tender his apology for the past mistake ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने निवेदन किया अब तक ऐसी प्रथा नहीं थी। नवम्बर में मुख्य मंत्रियों का जो पिछला सम्मेलन हुआ था उसमें भी दिल्ली प्रशासनिक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इसलिये मुख्य उत्तर में यह कहा गया है कि कोई भेद भाव नहीं किया गया है।

श्री श्रीचन्द गोयल : इस सम्मेलन में संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था, क्योंकि चंडीगढ़ भी इतना ही अच्छा संघ राज्य क्षेत्र है जितना कि नागालैंड या अन्य ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : केन्द्रीय शासित सभी क्षेत्रों का ख्याल गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाता है और मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य को इसकी चिंता करनी चाहिये क्योंकि उनके हित पूर्णतया रक्षित और सुरक्षित हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह बात तो फिर सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिये कही जा सकती है। एक संघ राज्य क्षेत्र और दूसरे संघ राज्य क्षेत्र में भेद भाव क्यों किया गया। गृह मंत्रालय नागालैंड और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के हितों की भी तो रक्षा कर सकती है (**व्यवधान**)।

Shri Siddheshwar Prasad : May I know what was the practice hitherto regarding the representation of union territories in such Conferences ? Were representatives from Manipur and Tripura invited to such Conferences in the past, if so, what are their names ?

If there was no definite policy in this regard, has any amendment been made recently in this policy ?

श्री शिन्दे : उन्हें जब भी बुलाया जाता है वे सम्मेलन मे आते हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister stated that previously there was not the practice to invite a representative of Delhi. The hon. Minister must be knowing that there was no Metropolitan Council in the past. The Metropolitan Council which is of recent origin is constituted by the elected representatives. In view of the fact that Jana Sangh commands majority in Delhi Metropolitan Council, may I know whether the Chief Executive Councillor of Delhi will be invited to all future Conferences irrespective of their subjects of discussion ?

श्री शिन्दे : मैं परिपत्र की एक प्रति सभापटल पर रखने को तैयार हूँ । इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : उस परिपत्र को पढ़िये ।

अध्यक्ष महोदय : इसको सभा पटल पर रखा जा सकता है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री जगजीवनराम) : मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि जहाँ भी संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों को निमन्त्रित किया जायेगा वहाँ, दिल्ली के प्रतिनिधि को भी बुलाया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh : Whether it is a fact that the former Chief Executive Councillor of Delhi, who belonged to Congress Party, was always invited to such Conferences and since there is no Congress Chief Executive Councillor now, this discrimination has been made ? Will the hon. Minister explain it ?

Shri Jagjivan Ram : This is not wholly correct.

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : क्या मुख्य कार्यकारी पार्षद का स्थान मुख्य मन्त्री के बराबर होता है ।

श्री जगजीवनराम : निश्चय ही यह मुख्य मन्त्री के समान नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : If that is not equal to the status of a Chief Minister, then what it is equal to ?

Shri Jagjivan Ram : It is equal to the Chief Executive Councillor.

श्री शिन्दे : मैंने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है । फिर भी परिपत्र को सभापटल पर रखना उचित होगा । श्रीमान् मैं इसको सभापटल पर रखता हूँ । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—525/67**]

कार्बनिक खाद

***302, श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में गोबर तथा मलमूत्र से वाणिज्यिक स्तर पर कार्बनिक खाद तैयार करने की सम्भावना का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एरिंग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हमारे देश में कम्पॉस्ट खाद, गोबर, मल मूत्र और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से हाथों द्वारा बनाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान स्वयं ही गोबर और अन्य अवशिष्ट पदार्थों से अपने खेतों के लिये खाद तैयार करते हैं। वाणिज्यिक पैमाने पर कम्पॉस्ट खाद तैयार करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर उपलब्ध नहीं होगा। गोबर से तैयार करने वाले संयत्रों से प्राप्त पतला गोबर भी कम्पॉस्ट खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक स्तर पर गैस संपन्न बड़ी संख्या में स्थापित करने की सम्भावना सीमित है। मलमूत्र और अन्य नगरीय उपशिष्ट पदार्थों से स्थानीय निकायों द्वारा कृषकों की बिक्री के लिये कम्पॉस्ट खाद तैयार की जाती है। वाणिज्यिक आधार पर कम्पॉस्ट खाद का उत्पादन, स्थानीय निकायों द्वारा उनके मलमूत्र और अन्य शहरी अपशिष्ट पदार्थों के निपटान सम्बन्धी कार्यक्रम के भाग के रूप में किया जाता है।

कुछ देशों में शहरी अपशिष्टों से कम्पॉस्ट खाद तैयार करने के लिये विभिन्न प्रकार के यान्त्रिक कम्पास्ट संयन्त्र स्थापित किये गये हैं भारत की परिस्थितियों में इन संयन्त्रों की अर्थ व्यवस्था और उपयुक्तता का अध्ययन किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : राजनीतिक षडयंत्र का यह दूसरा बड़ा उदाहरण है। हमारे देश में संसाधन है परन्तु हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित "स्थानीय खाद संसाधनों का विकास" को देखें तो उसमें लिखा है कि केवल बड़े शहरों से ही मानवीय मलमूत्र के प्रयोग द्वारा हम लगभग 8 करोड़ टन कार्बनिक खाद बनाई जा सकती है। यदि सारे देश के लिये विकास की योजना हो और यदि हम उसका उचित उपयोग करें और अपने आपको अमरीकी पूंजीपतियों के हाथों न बेचें, तो हम

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। आप सारी स्थिति को बता रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रश्न पूछता हूं। क्या तृतीय योजना के दौरान राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों और नगरों में कूड़ा खाद के उत्पादन के लिये स्थानीय खाद संसाधनों के बड़े और अच्छे उपयोग के लिये योजनाओं को सहायता देने के लिये कोई विशिष्ट तरीका निहित है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : पहली और दूसरी योजना के दौरान ग्रामीण कूड़ा खाद के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्र द्वारा राज्यों को कर्मचारियों पर किये गये व्यय तथा प्रशिक्षण व्यय का 50 प्रतिशत भाग दिया जाता था। जहां तक तृतीय योजना का सम्बन्ध है शहरी क्षेत्रों में कूड़ा खाद के लिये उपबन्ध किया गया था और हमने पर्याप्त सहायता दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं को बड़े पैमाने पर चलाने के लिये राज्य सरकारों को अनुदान दिये गये हैं और 1964-65 और 1965-66 के दौरान मंत्रालय द्वारा राज्य योजना की राशि के अतिरिक्त 2.8 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई थी। जबकि राज्य द्वारा पिछले तीन वर्षों में केवल 1.96 करोड़ रु० ही खर्च किया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितने कुड़ा खाद विकास अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला ? क्या आपने मानवीय मलमूत्र को प्रयोग करने और अन्य कार्बनिक खादों की जापानी पद्धति का अध्ययन किया है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह राज्य सरकारों की सीधी जिम्मेदारी है । हमारा काम केवल समन्वय करने और परिणामों को देखने का है । मैं सभा को जानकारी दे दूं कि तृतीय योजना के अन्त तक केवल 190 लाख टन ग्रामीण कूड़ा खाद·······

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न यह है कि कितने कूड़ा खाद विकास अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और उसका क्या परिणाम निकला और क्या आपने जापानी पद्धति का गहराअध्ययन किया है। आप प्रश्न को टाल रहे हैं क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया है ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हमने राज्य सरकारों को बता दिया है कि वे उन्हें राज्य स्तर पर कूड़ा खाद विकास अधिकारी नियुक्त करने चाहिये और निचले स्तर पर भी इस विषय से सम्बन्धित व्यक्ति नियुक्त करने चाहिये । जहां तक जापानी पद्धति का सम्बन्ध है, न केवल जापान ही अपितु अमरीका, ब्रिटेन और पश्चिम यूरोप के कई देशों ने इस दिशा में कुछ प्रगति की है । इस समस्या की जांच करने के लिये योजना आयोग ने हाल ही में एक समिति स्थापित की थी । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय भी शहरों में यांत्रिक कम्पोस्ट योजना और मलमूत्र शोधन योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

Shri Buta Singh : The hon. Minister just now stated that during the last five years Rs. 2 crore has been spent on those schemes. May I know what portion of it has been spent in rural areas ?

Shri Jagivan Ram : This should be directed to the State Government.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह राज्य सरकारों के लिये है ।

श्री समर गुहा : उर्वरक की बड़ी आवश्यकता और मांग और नाइट्रोजन और फोस्फोरस खाद का पर्याप्त मात्रा में उपबन्ध करने के लिये निधियों की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार ने कृषकों को गोबर, मलमूत्र आदि से कम्पोस्ट खाद तैयार करने का प्रशिक्षण देने के लिये उचित उपाय क्यों नहीं किये ? क्या सरकार ईंधन के रूप में गोबर का प्रयोग बन्द करेगी और खाद बनाना सिखाने के लिये योजना तैयार करेगी ? क्या सरकार पशुओं की हड्डियों के निर्यात पर रोक लगायेगी और हड्डियों से सुपर फास्फोट तैयार करने के लिये एक संयंत्र स्थापित करेगी......

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री किसी भी एक प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री जगजीवन राम : उनके पास प्रश्नों की एक सूची है और सभी प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है। कृषि मुख्य रूप से राज्य का विषय है। हम उनको कम्पोस्ट बनाने के लिये, कार्बनिक खाद के प्रयोग के लिये, मलमूत्र के उपयोग के लिये और गोबर इस्तेमाल करने के लिये तरीका बता सकते हैं। योजनाओं की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकारों को ही कार्यवाही करनी होगी। हम निश्चय ही राज्य सरकारों को कार्बनिक खाद को अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करने की आवश्यकता के बारे में दोबारा बता देंगे। हमने ऐसा किया है। ज्यों ही मैं आया मैंने परिपत्र जारी कराये कि हमें कार्बनिक खाद को, वह चाहे किसी रूप में उपलब्ध हो, नष्ट नहीं करना चाहिये।

श्री याज्ञिक : कम्पोस्ट खाद के उत्पादन के बारे में सरकार ने अब तक जो भी आंकड़े दिये हैं क्या उनमें देहातों में तैयार की गई कम्पोस्ट खाद भी शामिल है ? हम जानते हैं कि शहरों में इस किस्म की खाद कुछ मात्रा में बनाई जाती है। ग्रामों में यह खाद किस मात्रा में तैयार की गई और कृषकों द्वारा अपने खेतों में प्रयोग की गई ?

श्री जगजीवन राम : ग्रामीण क्षेत्रों की कम्पोस्ट खाद के आंकड़े दे दिये गये हैं। कम्पोस्ट बनाने के लिये यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। परन्तु साथ ही माननीय सदस्यों को समाज में प्रचलित प्रथाओं को नहीं भूलना चाहिये। इस देश के बहुत से लोग पाखाने को छूना पसन्द नहीं करते। यहां पर समाज के एक अंग को ही पाखाना उठाने का काम लादा गया है और दूसरे लोग इसको छूना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे पहले समाज से इस बुराई को दूर करने के लिये लोगों में शिक्षा का प्रचार करें।

Shri G. S. Mishra : There is not prejudice. The peasants do make use of the night soil.

Shri Jagjivan Ram : That is very good.

श्री तेनेट्टि विश्वानाथन : सभ्यता की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, क्या कम्पोस्ट योजना में लगा हुआ पैसा बेकार नहीं जायेगा क्योंकि मलमूत्र के निपटान के अच्छे तरीके भी हैं और सभ्यता की प्रगति के साथ साथ इसका मूल्य गिरता जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : सभ्यता की प्रगति में एक ऐसा समय आ सकता है जबकि पाखाना उठाने वाले को कुछ देना नहीं पड़ेगा अपितु जिसका पाखाना है उसे पाखाना उठाने वाले को भुगतान करना होगा।

श्री अंबा जागन : क्या सरकार कम्पोस्ट खाद के संयंत्रों के लिये जरूरी मशीनें आयात करने के लिए आवश्यक धन मंजूर करेगी अथवा व्यय का कोई भाग देगी या क्या सरकार विदेशी मुद्रा के लिये आवश्यक शर्तों को पूरा करेगी ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहाँ तक कम्पोस्ट खाद के प्रयोग का संबंध है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र अनुदान के रूप में 20 प्रतिशत और ऋण के रूप में 30 प्रतिशत सहायता

देगा। जहाँ तक विदेशी मुद्रा के भाग का सम्बन्ध है, भारत की कुछ फर्मो ने हमें बताया है कि भारत में मशीनों द्वारा कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिये आधुनिक संयंत्रों का निर्माण करना उनके लिए संभव है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न संख्या 303 से 307 तक लेते हैं जो सब के सब एक ही विषय पर हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न संख्या 306 को पृथक से ले लिया जाये क्योंकि इसका सम्बन्ध उन 40,000 श्रमिकों से है जिन्हें ले ऑफ कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा।

Shri Mohan Swarup : It is a fact that the states were to be given 5 .25 Lakh ton sugar per month, but this quota has been reduced t› 1.87 Lakh ton ? It is also a fact that due to this there is great paucity of sugar in states and this was keenly felt when recently there was season for marriages ? Does Government think to reduce it further and if so what is the reason therefor ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : हमने स्थिति का स्पष्टीकरण कुछ उत्तरों में कर दिया है तथा हम आगे कोटा को कम करने का कोई विचार नहीं रखते।

पहले कमी मार्च के मास में की गई क्योंकि उस से पूर्व देश में प्रति मास 2,52,000 टन दिया जाता था। उसके पश्चात इसे कम करके 1,87,000 टन किया तथा फिर मई में उत्पादन को ध्यान में रखते हुए यह कम करके 1,57,000 टन कर दिया गया।

Shri Mohan Swarup : What is the reason for reduction and whether Government realise the difficulty of the people on this account ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमें लोगों की कठिनाई का ध्यान है परन्तु उत्पादन कम हो गया था और वह केवल 35 लाख टन था। इस वर्ष तो उत्पादन केवल 21.8 लाख टन ही है जिसका कारण चीनी के कारखानों को गन्ने का न मिलना तथा गन्ना सूखा के कारण कम पैदा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : अभी पांच प्रश्न बाकी हैं। यदि मैं प्रत्येक में तीन सदस्य भी बुलाऊं तो 15 नाम बोलने होंगे। मैं बिना किसी भेद भाव के केवल पहले तीन नाम ही बुलाऊंगा।

Shri M. A. Khan : On a point of order I think it is not proper to call to put supplementaries only those who have tabled questions. Will it be considered to call those also whose names are not there ?

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यदि सदस्य महोदय का नाम किसी प्रश्न पर हो और मैं किसी अन्य सदस्य को बुलाऊं तो वह बुरा मानेंगे। कल उनकी भी बारी आ सकती है।

श्री प० गोपालन : कुछ स्थानों पर चीनी की कमी को खांडसारी के प्रयोग से दूर किया जाता है। केरल में थोड़ा सा ही गुड़ बनाया जाता है। क्या सरकार ध्यान रखेगी कि केरल में खांडसारी बनाने की अनुमति न दे तथा केरल को चीनी भी कोटा से अधिक दी जावे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि हम कोटा भी बढ़ा दें तो भी हमारे पास देने को चीनी नहीं है। खांडसारी के नियन्त्रण के बारे में हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं।

श्री एस० एम० जोशी : क्या केरल को खांडसारी देंगे ?

श्री नम्बियार : केरल में सब चीजों की कमी है। उन्हें खांडसारी ही दे दो ।

श्री नायनार : वह तो 12,00 टन से घटा कर 5,000 टन कर दी गई है।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह सारे देश में बराबर अनुपात में कम की गई है।

श्री मनु भाई पटेल : केवल केरल में ही कमी नहीं की बल्कि 2,000 टन से घटा कर केवल 3,000 टन कर दी है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister inform the reduction made in the sugar quota of Delhi for the second time during the last month and whether keeping in view the special needs of Delhi will it be restored and arrangements will be made to procure more Khandsari for Delhi ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : दिल्ली को विशेष स्थान देते हुए उसका कोटा कम नहीं किया। दिल्ली का कोटा गत मार्च से 6,000 टन प्रतिमास चला आ रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : देश में चीनी का अधिकतम उत्पादन 31 लाख टन था जो कि कम होकर 21 लाख टन रह गया हैं। मन्त्री महोदय का कहना है कि यह सूखा के कारण है। क्या कम उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार यह विचार करेगी कि देश की आन्तरिक खपत में यदि कमी आती है तो चीनी का निर्यात नहीं करेगी।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह पहले ही घोषणा कर दी गई है कि अब चीनी का निर्यात नहीं होगा। जो पहले निर्यात हुआ था वह राष्ट्र मंडल चीनी समझौता तथा अमरीका चीनी अधिनियम के अन्तर्गत किये गये समझौतों के अनुसार था। अब हम बिल्कुल निर्यात नहीं कर रहे हैं।

Shri R. S. Vidyarthi : The price of sugar cane was increased in the ratio of increase in the price of sugar and hence the sugar-cane growers were not getting due price for their produce.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अभी हाल ही में चीनी के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वह तो मौसम के आरंभ में थी और वह भी कुछ क्षेत्रों के बारे में। चीनी का मूल्य चीनी जांच

आयोग तथा प्रशुल्क आयोग द्वारा दी गई अनुसूचियों के आधार पर किया जाता है। इसके लिए एक सूत्र बना रखा है।

श्री विश्वनाथ राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी तथा खांडसारी और गुड़ में अस्वस्थ मुकाबला हो रहा है, सरकार इस मुकाबले को बन्द क्यों नहीं करती ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह समस्या लगातार सामने आती है। उद्योग के एक भाग पर नियन्त्रण है तथा दूसरे पर नियन्त्रण नहीं है। हमने यह प्रश्न चीनी जांच आयोग के पास भी भेजा और उसने परामर्श दिया कि खांडसारी पर नियन्त्रण लगाना उचित नहीं है क्योंकि बहुत संख्या में लोग खांडसारी का प्रयोग करते हैं। फिर भी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Shri Bibhuti Mishra : In reply to my question No. 305 the Minister said that Government was considering the question of raising the price of gur, Khandsari and sugar-cane. Now it is the month of June and if price of these is announced, there can be increase in the production of sugar-cane. What is the Government's view about increase in the price of sugar-cane keeping in view that prices of all other commodities have gone up ?

The Minister for food and agriculture (Shri Jagjivan Ram) : As I had announced in the House there is delay in it. So far as the price of sugar-cane is concerned, it will be revised upward. It will be decided soon.

Shri K. N. Tiwary : What is the present production of sugar in the country ? This year the production was about 21 Lakh ton. Keeping in view the decrease in the acreage of sugar cultivation, what is the Government's estimate of production for the year 1967-68 and how will the Government fulfil its demand in the country ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गत दो वर्षों में गन्ने को प्रति एकड़ बोने में कमी हुई है और वह कमी उत्तर प्रदेश में 14 प्रतिशत के लगभग, बिहार में 15 प्रतिशत के लगभग तथा पंजाब में 17 प्रतिशत हुई है। सूखा के कारण आगे भी स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही और इस प्रकार यह कमी अनुमान के अनुसार 10-15 प्रतिशत कम होगी। अधिक उत्पादन के लिए सरकार कुछ कदम उठाने का विचार कर रही है जैसे मूल्य का बढ़ाना, नियन्त्रण करना तथा उत्पादकों और कारखाने वालों को प्रोत्साहन देना। यह सुझाव इस मामले में रुचि रखने वालों ने दिये हैं।

Shri Manibhai J. Patel : Whether there is a scheme for those states where there is lesser production of sugar to increase their production in their own states to meet their own demands ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अगले 5 वर्षों के लिए हमने गन्ने के विकास के लिए 15 करोड़ रु० सुरक्षित रख दिया है। परन्तु अन्त में यह राज्य सरकारों का कार्य है। मध्य प्रदेश में मिलों के लिए गन्ना नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या गत दो वर्षों में चीनी के उत्पादन में कमी हुई है तथा अगले वर्ष के लिए भी बहुत अच्छा उत्पादन की सम्भावना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अगले दो-तीन वर्षों के लिए चीनी के उत्पादन के बारे में कोई योजना है तथा आन्तरिक खपत के लिए क्या योजना है ? क्या सरकार चीनी के निर्यात को बन्द करने का प्रस्ताव रखती है।

श्री जगजीवन राम : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

Shri Ram Kishan : Whether apart from U. P. due to shortage of sugar-cane produce, the workers have been rendered unemployed ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने राज्य सरकारों से कहा है कि इस बारे में सूचना दें परन्तु उन्होंने यह अभी नहीं दी है। इसके कारण कारखानों में बेकारी हुई है। परन्तु चीनी के कारखानों में आधे कर्मचारी आधे समय तक बेकार रहते हैं। ठीक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : हमारे देश में चीनी में मिठास का अंश कम है। इसकी तुलना दूसरे देशों से किस प्रकार है तथा इसे सुधारने के लिए गत दस पन्द्रह वर्षों में क्या किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सूचना छापी हुई है फिर भी हमारे देश के कुछ कारखानों की चीनी की तुलना कारवाई तथा पश्चिमी देशों से की जा सकती है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या चीनी के कुछ कारखानों के बन्द होने से तथा उत्तर प्रदेश में गन्ने से खांडसारी और गुड़ बनाने के कारण क्या सरकार चीनी के मूल्य को 3 रु० अधिक करने का विचार रखती है ?

श्री जगजीवन राम : उत्तर प्रदेश सरकार ने तथा चीनी के कारखाने दारों ने हमें कुछ परामर्श दिया है तथा हम इस भाव को बढ़ाने का विचार रखते हैं और इसकी घोषणा शीघ्र ही की जायेगी।

Shri George Fernandes : Will the Minister state the number of factories which has now been permitted to produce cube-sugar, the quantity of cube-sugar which they are producing annually and whether government have controlled their sale prices or they are sold in the black-market ? As there is paucity of sugar, government intend to put some restrictions on the manufacture of cube-sugar ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसके बारे में मुझे नोटिस चाहिए परन्तु इतना मैं कह दूं कि क्यूब-चीनी बनाने की अनुमति केवल दो या तीन कारखानों को ही दी है तथा चीनी एक नियन्त्रित वस्तु है।

Shri Mrityunjay Prasad : If you raise the price of sugar-cane now it will have no effect on its cultivation for the year 1967-68 as crops for the same have already been sown. Therefore I suggest to increase the price of sugar-cane to keep in view the production of the year 1968-69 so that you may not have to reconsider it.

Shri Jagjiwan Ram : Only the time will show it but I think the price of sugar-cane which we intend to raise will be applicable for the next year.

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गन्ने का भाव बढ़ाया जा रहा है क्या सरकार सदन को आश्वासन देगी कि चीनी का भाव न बढ़ायेगी क्योंकि काले बाजार में चीनी का भाव 200 प्रतिशत अधिक हो गया है ?

श्री जगजीवन राम : सदस्य महोदय को पता है कि चीनी का भाव गन्ने के भाव पर आधारित है और यदि गन्ने का भाव बढ़ेगा तो चीनी का भाव भी बढ़ेगा ।

Shri Manubhai Patel : Keeping in view the dwindling productions of sugar in the country have government thought of manufacturing sugar by things other than sugar-cane and whether government intend to manufacture sugar from palm trees and will it encourage its production ?

Shri Jagjiwan Ram : I have been told that the palm gur is not economical.

Shri Ram Sewak Yadav : The price of sugar rises as the price of sugar-cane is raised. I want the price of sugar-cane to be raised but not of the sugar. Will the Minister while fixing the price of sugar-cane and sugar will take into consideration the cost of production, Profit and government duties on the sugar production so that the consumer is not burdened. As you also prepared to follow the old maximum which was in use before 1950 that the price of sugar will be as many rupees pre mound as is the price of sugar-cane per mound in annas ?

Shri Jagjiwan Ram : When such question crop up we send them to the Tariff Commission and the experts there decide the question having regard to price of raw material. I think this is an old question and we should send it to the Tariff Commission.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी का कोटा कम कर देने से कुछ चाय तथा काफी के रैस्टोरेंन्टों ने अपने समय घटा दिये हैं, क्या सरकार चाय तथा काफी पीने वालों की सहायता के लिए विशेष पग उठायेगी ? हमें संसद भवन में भी चीनी की चाय नहीं मिलती ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं नहीं समझता कि चाय तथा काफी पीने को प्रोत्साहित किया जाये परन्तु इतनी कमी नहीं हुई है कि लोगों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो । इस वर्ष भी हमारे पास चीनी का उत्पादन 21.8 लाख टन तथा पीछे से बची चीनी 9.5 लाख टन होने से, हमारे पास 30 लाख टन के लगभग चीनी है । संसद भवन की चाय के बारे में मैं विचार करूंगा ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : चीनी के मिलों की कितनी क्षमता चीनी बनाने में लगती है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमारे देश में अधिष्ठापित क्षमता 34 लाख टन है परन्तु हम 10–15 प्रतिशत क्षमता से अधिक चीनी का उत्पादन कर सकते हैं । इस वर्ष क्षमता तो 34 लाख टन की थी परन्तु हमने 22 लाख टन उत्पादन किया और इस प्रकार 40 प्रतिशत की कमी हुई ।

श्री बाबूराव पटेल : क्या यह सच है कि 1½ करोड़ रुपये की चीनी हरीनगर चीनी मिलों में बन्द पड़ी है और सरकार मिल मालिकों को रुपया पेशगी नहीं दे रही और

इस कारण वे गन्ना उत्पादकों को रुपया नहीं दे रहे तथा न ही सरकार मिल मालिकों को चीनी बेचने की अनुमति दे रही है ? क्या सरकार ऐसे ना समझदारी के तरीके अपना कर बनावटी कमी उत्पन्न नहीं कर रही ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमारा काम चीनी मिलों को धन देना नहीं। यह कार्य मिल वाले अपने बैंकों से करते हैं। मुझे पता नहीं कि हरीनगर चीनी कारखाने ने अपने दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए क्यों किसी बैंक से व्यवस्था नहीं की। चीनी के देने के बारे में हम चीनी तीन चार मास में उत्पादन करते हैं और उसका प्रयोग 12 मास तक करते रहते हैं और इस प्रकार मांगों को पूरा करने के हेतु चीनी के देने को नियन्त्रित किया है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग ने सरकार को एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें चीनी के मूल्य की सिफारिश की गई है ? यदि हां तो यह प्रतिवेदन कब दिया गया था तथा यह संसद को क्यों नहीं पेश किया ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम प्रायः चीनी तथा अन्य कृषि वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते समय कृषि मूल्य आयोग से परामर्श लेते हैं परन्तु अब तक यह पद्धति नहीं रही है कि आयोग के प्रतिवेदन संसद को पेश किये जायें। यदि सदस्य महोदय चाहती हैं तो मैं उन्हें एक प्रति भेज दूंगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या मंत्री बतायेंगे कि चीनी के भाव में उत्पादन शुल्क और अन्य सरकारी उपकरों का कितना अंश है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उत्पादन शुल्क का अंश लगभग 28.6 प्रतिशत है तथा गन्ने की खरीद का कर 4.1 प्रतिशत। यदि सदस्य महोदय को और सूचना चाहिए तो चीनी के भाव में 43.8 प्रतिशत गन्ने का मूल्य तथा गन्ने पर अधिक व्यय 2 प्रतिशत और 21.5 प्रतिशत उस पर चीनी बनाने का खर्च आता है।

Shri Tulsidas Jadhav : The Minister said that sugar-cane production was low due to drought. I must inform you that it was produced more but as adequate price of sugar-cane is not given the sugar-cane is used for manufacture of gur and khandsari. In view of this why does not government raise the price of sugar ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसका मैं कुछ उत्तर दे चुका हूं। गुड़ तथा खांडसारी के मूल्य बढ़े हैं तथा काफी गन्ना उसमें प्रयोग किया गया। इसका मूल्यों से मिलाना उचित नहीं क्योंकि इससे चीनी के भाव बहुत बढ़ जायेंगे और उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें संतुलित ढंग से सोचना होगा।

श्री विश्वनाथन : यद्यपि उचित मूल्य की दुकानों तथा सहकारी संस्थाओं की दुकानों पर चीनी की कमी है और काले बाजार में यह आसानी से मिल जाती है। सरकार ने चीनी को काले बाजार में जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि वह काले बाजार में जो चोरी से चीनी जाती है उसकी रोकथाम करें।

श्री म० ला० सोंधी : क्या आप इस पर विचार करेंगे कि हम गाज़ा में मरे पांच भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट के लिए खड़े हो जायें ?

अध्यक्ष महोदय : यहां ऐसी पद्धति नहीं है। प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देंगी।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी के कर्मचारी

+

अ० सू० प्र० 7. श्री श्रीरेश्वर कलिता :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री जि० मो० विश्वास :
श्री जनार्दनन :
श्री अविचन :
श्री क० मि मधुकर :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा एक नई कम्पनी प्रायोजित किये जाने के परिणाम-स्वरूप, रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड के लगभग तीन हजार कर्मचारियों की छंटनी की जाने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी के प्रबन्ध ने 3 मई, 1967 को अपना व्यापार बन्द कर दिया। इस कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की 391 और 394 धाराओं के अन्तर्गत अपने और अपने लेनदारों और भागीदारों के बीच प्रबन्ध करने की एक योजना के अनुमोदनार्थ 13 दिसंबर, 1966 को कलकत्ता की उच्च अदालत में एक याचिका दी। कलकत्ता की उच्च अदालत द्वारा 3–5–66 को अनुमोदित प्रबन्ध योजना की एक व्यवस्था यह थी कि कम्पनी अपना कामकाज बन्द कर देगी।

22 फरवरी, 1967 को भारत सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी के उन्हीं कर्मचारियों को अपने यहां काम पर लगायेगा जो उचित शर्तों पर उसके काम के उपयुक्त और आवश्यक समझे जाएंगे। निगम ने असम और कलकत्ता क्षेत्र दोनों ही जगह काम शुरू कर दिया है। रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी के लगभग 7500 कर्मचारियों में से लगभग 5000 के केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन

निगम द्वारा काम पर ले लिये जाने की आशा है और केवल 2500 के लगभग कर्मचारी जरूरत से अधिक होंगे । जो कर्मचारी नयी कम्पनी की जरूरत से बेशी होंगे उन्हें क्षति-पूर्ति दी जायेगी और उनके अन्य देय चुकाये जायेंगे ।

उन कर्मचारियों की कठिनाइयां और कम करने के लिए जो नयी कम्पनी में रोजगार के लिये उपयुक्त और आवश्यक नहीं समझे जायेंगे कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में और श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालयों, कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति स्थापित की जायेगी जो रोजगार के अवसर बढ़ाने के ऐसे संभव उपायों की परीक्षा करेगी तथा सुझाव देगी जिन्हें तुरन्त लागू किया जा सके और जिसमें राजवागान गोदी और कलकत्ता पत्तन भी शामिल हैं । जो कर्मचारी जरूरत से वेशी होंगे उनकी योग्यता में ढील देने के प्रश्न पर भी यह समिति विचार करेगी जिससे वे सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में रोजगार पर लगाये जा सकें । यह समिति इन वेशी घोषित कर्मचारियों का सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में जिन्हें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता हो,मिलते-जुलते पेशों या अन्य पेशों पर रोजगार में लगाने में सहायता करने के लिये उनको फिर से प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी बनायेगी ।

पाकिस्तान से होकर नदी मार्ग के बन्द होने को तथा इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि भारत-पाक युद्ध में रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी के कुछ जहाज रोक लिये गये थे, निगम का काम सीमित पैमाने पर होगा, जिसके फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में कमी होगी। अतः इन परिस्थितियों में कुछ छंटनी करना अपरिहार्य होगा ।

श्री धीरेश्वर कलिता: सरकार ने स्वयं ऐसा निर्णय क्यों कर लिया है कि केवल 5000 कर्मचारी नई कम्पनी में लिये जायेंगे और शेष 2500 व्यक्तियों को फालतू घोषित कर दिया है ?

डा. वी. के. आर. वी. राव : नई कंपनी को इस वर्ष फरवरी में पंजीकृत किया गया था और अभी तक इस बात पर विस्तार से विचार किया जा रहा है कि रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी के कितने लोगों को नई कम्पनी में काम पर लगाया जा सकता है । चूँकि पाकिस्तान ने आसाम को जाने वाला नदी का रास्ता बन्द कर दिया है और पाकिस्तान ने उक्त कम्पनी के कुछ जहाज भारत--पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पकड़ लिये थे इसलिये नई कम्पनी के पास बहुत थोड़ा काम है ।

श्री धीरेश्वर कलिता : क्या काम के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है ?

डा. वी. के. आर. वी. राव: मैं माननीय सदस्य का तात्पर्य नहीं समझ पाया हूं ।

श्री धीरेश्वर कलिता : क्या सरकार इस बात पर नये सिरे से विचार करेगी कि सब 7500 कर्मचारियों को काम पर लगाया जाये, क्योंकि आसाम में यातायात की सुविधाएं बढ़ने वाली हैं और कलकत्ता के राजाबाग में जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम बढ़ रहा है ?

डा. वी. के. ग्रार. वी. राव : सरकार इन सब बातों पर विचार कर चुकी है और कम्पनी के निदेशक-मंडल ने यह निर्णय किया है कि फिलहाल 5000 से अधिक व्यक्तियों को काम पर लगाना सम्भव नहीं है । शेष लोगों को काम दिलाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि कितने व्यक्तियों और किस किस को नई कम्पनी में काम पर लगाया जाये, इस बात का अनुमान पुरानी कम्पनी के चेयरमैन ने लगाया है । यदि हाँ, तो यह अनुमान नई कम्पनी के अधिकारी द्वारा क्यों नहीं लगाया गया ?

डा. वी. के. ग्रार. वी. राव : शायद माननीय सदस्य को मालूम होगा कि नई कम्पनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों वे ही हैं जो पुरानी कम्पनी में चेयरमैन और डायरेक्टर थे । ऐसा इसलिये किया गया है ताकि नई कम्पनी अपना काम जल्दी से जल्दी शुरू कर सके । और उन लोगों को, जिनकी सेवाएँ पुरानी कम्पनी के बन्द होने के कारण समाप्त कर दी गई है, यथा शीघ्र काम मिल सके ।

एक सदस्य ने कार्य-विश्लेषण की बात भी कही है । जहाँ तक इसका सम्बन्ध है, हमें यह मालूम है कि बंदरगाह में कितना काम है, आसाम की नदी यातायात सेवा का कितना काम है या नावों का कितना काम है । राजाबाग के गोदी बाड़े (डाकयार्ड) या भांडागारण के काम को अधिकाधिक बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं । फिर भी सरकार ने एक समिति की स्थापना की है जो फालतू लोगों को रोजगार दिलाने, उनकी योग्यताओं में छूट देने और उनको दूसरी प्र ार के प्रशिक्षण देने की सम्भावनाओं का अध्ययन करेगी ।

श्री हेम बरुग्रा : क्या यह सच है कि रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड ने, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी, अपनी सभी आस्तियां लंदन भेज दी हैं, जहाँ वह अब भी काम कर रही है ? क्या लंदन स्थित कम्पनी का एक शिष्टमंडल नई दिल्ली आया था और सम्बन्धित मंत्रियों से मिला था जिन्होंने उसे यह आश्वासन दिया था कि पुरानी कम्पनी के सभी कर्मचारियों को नई कम्पनी में काम दिया जायेगा ।

डा. वी. के. ग्रार. वी. राव : मुझे इस प्रकार के निष्कर्षों या आश्वासनों का पता नहीं है ।

श्री स्वैल : मंत्री महोदय ने छंटनी करने का यह कारण बताया था कि पाकिस्तान द्वारा नदी का रास्ता बन्द किये जाने से काम कम हो गया है । समाचारपत्रों में यह समाचार छपा था कि पाकिस्तान ने पूर्वी भारत की नदियों को संयुक्त रूप से उपयोग करने का भारत को सुझाव दिया है । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान नदियों के रास्तों को देर-सबेर खोल देगा । फिर सरकार कर्मचारियों की छंटनी के लिये इतनी जल्दी क्यों कर रही है ?

डा. वी. के. ग्रार. वी. राव : मुझे मालूम नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा सुझाव भारत को भेजा है । परन्तु मैं इस बारे में पूछताछ करके माननीय सदस्य को बता सकता हूँ ।

श्री स. मो. बनर्जी : जो समिति नियुक्त की गई है, क्या वह समिति काम कर रही है और उसमें श्रमिक संघ को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया है ?

डा. वी. के. आर. वी. राव : यह समिति कार्य कर रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने फालतू कर्मचारियों और उनकी योग्यता आदि का एक विस्तृत विवरण तैयार किया है जो उक्त समिति को दे दिया गया है। आसाम सरकार को भी इस बात से अवगत कराया जा रहा है जिसमें आसाम सरकार भी ऐसे कर्मचारियों को रोजगार देने के मामले में सहायता कर सके, क्योंकि उनमें लगभग एक हजार कर्मचारी आसाम के रहने वाले हैं। जहाँ तक समिति के साथ श्रमिकों के प्रतिनिधि को जोड़ने का सम्बन्ध है इस बारे में मैं विचार करूँगा।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : जो कर्मचारी बर्खास्त किये गये हैं उनको कम्पनी ने क्या मुआवजा दिया है ? क्या सरकार यह देखेगी कि सब भूतपूर्व कर्मचारियों को समान आधार पर मुआवजा दिया जाये ?

डा. वी.के. आर. वी. राव : नई कम्पनी नियमों के अनुसार उन्हें प्रतिकर दे रही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन, मेरे विचार से, सेवा के प्रत्येक वर्ष पर 15 दिन के वेतन के हिसाब से प्रतिकर दिया जाता है।

श्री हेम बरुआ : आपने उन्हें बेरोजगार बना दिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Strike by Bombay Dock Workers

***308. Shri Hukam Chand Kachwal :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Dr. Ranen Sen :
Shri Dhireshwar Kalita :
Shri Madhu Limaye :
Shri S. M. Banerjee :
Shri George Fernandes :
Shri Indrajit Gupta :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that dock workers of the Bombay Port Trust went on token strike on the 11th April, 1967 to press their demands ;

(b) if so, what were their demands ; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) (a) to (c) About 3,000 employees of the Docks Department comprising mainly the employees assigned to clerical and supervisory duties in the sheds and warehouses, about 150 employees in watch and ward and sanitary sections of the docks and about 290 employees of the departmental canteens run by the Labour Department of the Bombay Port Trust went on a day's token strike from 00.30 hours to 24.00 hours on the 11th April, 1967. The grievance was that some of the demands which were included in a charter submitted in 1965 by the Union had remained unimplemented or unsettled. These demands related mainly to the creation of higher posts in various categories by way of promotional opportunities for shed staff, filling of certain vacancies, rectification of anomalies in pay fixation, replacement of existing furniture in sheds and warehouses, rotation of staff in canteens, grant of risk allowance for handling cash, provision of uniforms etc. The demands have been discussed between the port authorities and the Union concerned and in regard to several

items a settlement has already been reached. The few remaining demands are under discussion. A departmental procedure for discussing such demands from time to time has also been agreed to.

मरमागोश्रा बन्दरगाह

* 309. **श्री सेक्वीरा :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मरमागोआ बन्दरगाह में खनिज अयस्क को शीघ्रता से चढ़ाने की सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य व्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य विकास योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) जी हां, प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) सुविधा की प्राक्कलित लागत 24.20 करोड़ रुपये है । इसमें ये बातें होंगी :—

(1) कच्चे लोहे का एक घाट होगा, जिसमें प्रारंभ में 60,000 डी० डब्लू० टी० तक के और अन्ततः 1,00,000 डी० डब्लू टी० के पोत आ जा सकेंगे;

(2) एक यांत्रिक धातु धरने उठाने का संयंत्र जिसमें 6000 टन प्रति घंटा की दर की क्षमता होगी और;

(3) रेल से लाई हुई और बजरे द्वारा लाई हुई वस्तुएं उतारने के लिए आवश्यक सुविधायें होंगी ।

(ग) इसमें मौजूदा माल घाटों का आधुनिकीकरण है और 3.06 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत से वार्षिक पी० ओ० एल के चार लाख टन को धरने उठाने के लिये एक खनिज तेल जेट्टी के निर्माण का प्रस्ताव है ।

बन्दरगाहों में अनाज को उतारना-चढ़ाना ।

* 310. **डा० रानेन सेन :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की बहुत सी बन्दरगाहों में अनाज को बड़े पैमाने पर उतारने-चढ़ाने की सुविधायें नहीं हैं तथा प्रत्येक वर्ष हजारों टन अनाज नष्ट हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो बन्दरगाहों में अनाज नष्ट होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :—(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत को खाद्य दान

* 311. श्री प० गोपालन : श्री मं० रं कृष्ण :
श्री नायनायर : श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री उमानाथ : श्री रा० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री चं० चु० देसाई :
श्री भारत सिंह : श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रामसिंह आयरवाल : श्री बाबू राव पटेल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों की बहुत सी स्वयंसेवी संस्थायें भारत के खाद्य दान के कार्य में भाग ले रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं, उन्होंने 1964–65, 1965–66 और 1966-67 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तथा खाद्य पदार्थों का दान दिया तथा उनका मूल्य क्या था;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थाओं से सहायता के लिए प्रार्थना की थी;

(घ) क्या उन पर कोई विदेशी मुद्रा व्यय हुई और यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) दान की इन वस्तुओं का किस प्रकार प्रयोग किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह सच है कि कुछेक स्वैच्छिक संगठनों ने भारत में कमी सम्बन्धी सहायता के लिये खाद्य पदार्थ आदि दान के रूप में दिये हैं ।

(ख) भारत सरकार को 1965–66 और 1966–67 के वर्षों में सूखे से उत्पन्न संकट का मुकाबला करने के लिये विदेशों से विभिन्न स्वैच्छिक तथा गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त खाद्यान्नों के दानों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 526/67]

1964–65 में स्वैच्छिक एजेंसियों से यदि कोई खाद्यान्नों का दान प्राप्त हुआ था उसके ब्यौरे तुरन्त उपलब्ध नहीं है । इस विवरण में विदेशी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भारत में संगठनों या व्यक्तिगतों को दिया गया खाद्यान्नों का दान शामिल नहीं है ।

(ग) जी नहीं । तथापि, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और महानिदेशक खाद्य तथा कृषि संगठन ने 11 फरवरी, 1966 को विश्व समाज के नाम भारत में अन्न संकट को दूर करने के लिए सहायता देने की एक संयुक्त अपील जारी की थी ।

(घ) इटली से प्राप्त चावल के एक प्रेषण के बारे में दिये गये जहाज के कुछ विलम्ब शुल्क को छोड़कर इन उपहारों पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं हुई है ।

(ङ) उपभोक्ताओं को सामान्य मार्गों से वितरण करने के लिये गेहूँ/गेहूँ का आटा तथा चावल के उपहारों को केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों में मिला दिया गया था। इस प्रकार वितरित उपहारों का मूल्य "कमी सहायता तथा ग्रामीण विकास निधि" जिसका सृजन किया जारहा है, में जमा किया जाएगा। देश के कमी से प्रभावित क्षेत्रों में दुग्ध चूर्ण और विटामिन की गोलियां मुफ्त बांटी गयी थीं।

मध्य प्रदेश में अकाल

* 312. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री आत्म दास :**
श्री बाबूराव पटेल : **श्रीमती अगमदास गुरू मिनिमाता :**
श्री गा० शं० मित्र : **श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री मनोहर लाल सोंधी :**
श्री नाथूराम अहिरवार : **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य के 43 जिलों में से 38 जिले इस वर्ष सरकारी तौर पर सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये गये हैं, जबकि पिछले वर्ष 27 जिले सूखा प्रभावित घोषित किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि 12 जिलों में स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक हो गई है;

(ग) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कौन-कौन से सहायता कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं; और

(घ) वहां की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य को कितना खाद्यान्न दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस वर्ष राज्य के 38 जिले सूखे से प्रभावित हुये हैं। इनमें 12 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुये हैं। स्थिति को नियन्त्रण में रखने के लिए सहायता कार्य किये जा रहे हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा सूखे से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) सहायता कार्य जैसा कि सड़कें, सिंचाई कार्य, वनों में कार्य आदि आरम्भ कर दिये गये हैं। नवीनतम समाचारों के अनुसार 5818 कार्यों पर 8,63,737 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।

(2) बूढ़े तथा अधिक कमजोर लोगों को जो सख्त शारीरिक काम नहीं कर सकते तथा अन्य सहायता के पात्र व्यक्तियों को प्रतिमास प्रति व्यक्ति आठ किलोग्राम के हिसाब से अनाज सहायता के रूप में दिया जाता है। नवीनतम समाचारों के अनुसार 35,009 व्यक्तियों को मुफ्त सहायता दी जाती है।

(3) जहां कहीं आवश्यक है पीने के पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए चालू कुओं को गहरा करने, नये कुए खोदने, नाले बनाने तथा टैंकरो तथा बैलगाड़ी से पानी को पहुंचाने के कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं।

(4) मुफ्त अथवा रियायती दरों पर चारे को पहुँचाने के प्रबन्ध भी किये गये हैं।

इन सहायता कार्यों के अतिरिक्त 'केयर', यूनिसेफ तथा अन्य स्वेच्छी संगठनों से प्राप्त खाद्यान्न के साथ मुफ्त खाना खिलाने के केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है।

उपहार में मिले 3000 टन गेहूँ, 300 टन दूध पाउडर तथा 11 टन शुष्क रायसिन राज्य को मुफ्त वितरण के लिये दी गई है।

(घ) भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को आयातित गेहूँ तथा मीलो की निम्नलिखित मात्रा आवंटित की गई है:—

मार्च, 1967	—	35, 000 टन
अप्रैल, 1967	—	31, 000 ,,
मई, 1967	—	30, 500 ,,
जून, 1967	—	31, 000 ,,

बड़ी संख्या में लोगों का गांवों से नगरों में चले जाना

*313 श्रीमती निर्लेप कौर
श्री बैरो :
श्री स्वैल
श्री कोलाई बरुआ :
श्री किकर सिंह
श्री डा० कर्णी सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग लगातार ग्रामों से नगरों में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिये सरकार गांवों का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) से (ग) अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ग्रामों से नगरों को जा रहे हैं। तथापि कुछ ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों में जाना एक सामान्य सामाजिक व आर्थिक प्रक्रिया है ; यह एक ओर तो यह दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र में जीविका के पर्याप्त साधनों का अभाव है तथा दूसरी ओर कस्बों तथा नगरों में अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा हो रहे हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने, उन्हें बनाए रखने तथा उनके विस्तार के लिए काम किया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से ये हैं—सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत अब सारा देश लाया जा चुका है, बड़े पैमाने के कृषि कार्यक्रम, जिनमें सघन तथा विशेष योजनाएं भी शामिल हैं, रोजगार उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण जन-शक्ति कार्यक्रम, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी तथा आंशिक रोजगार की स्थिति बहुत विकट है, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने के कार्यक्रम तथा ग्रामोद्योगों आदि का विकास।

बिहार के मुख्य मंत्री की सोवियत संघ से अपील

***314. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री आत्मदास :
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल :
श्री य० अ० प्रसाद
श्री न०कु० सांघी :
श्री बेदव्रत बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस बयान की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने सोवियत संघ से अनुरोध किया है कि बिहार की बड़े पैमाने पर सहायता की जाये;

(ख) क्या बिहार सरकार ने अनाज की सप्लाई के लिये विदेशों से सीधा सम्पर्क स्थापित किया है; और

(ग) क्या यह सम्पर्क केन्द्रीय सरकार की जानकारी में स्थापित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) इस सम्बन्ध में सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Uniformity in Rates of Sugar

315. Shri Onkar Singh :
Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of **Food and agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 70 on the 28th March, 1967 and state:

(a) whether any decision has since been taken in regard to the proposal to bring uniformity in the rates of sugar;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No Sir

(b) Does not arise.

(c) The matter is still under consideration.

भारतीय खाद्य निगम

*316. श्री ईश्वर रेड्डी : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये : श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस का क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) निगम की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) खाद्य निगम के कार्यचालन की ऐसी कोई औपचारिक समीक्षा नहीं की गई है लेकिन सरकार खाद्य निगम के कार्यकलापों पर निरन्तर ध्यान रखती है।

कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना

*317. श्री आदिचन : श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री एस्थोस : श्री वासुदेवन नायर :
श्री अब्राहम : श्री नायवर :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करने के संबन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) मेसर्स मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पेश की गई परियोजना रिपोर्ट और हमारे तकनीकी विशेषज्ञों की उस पर की गयी टिप्पणियों की परीक्षा पूरी हो गयी। इस संबंध में अगली कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

अब तक 92.64 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

चीनी उद्योग का लागत ढांचा

*318. श्री विभूति मिश्र : श्री धीरेन्द्रनाथ :
श्री क० ना० तिवारी : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री काशीनाथ पाण्डे : श्री प्र० के० देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीनी उद्योग के लागत ढाँचे के बारे में नई जांच का आदेश देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हाँ। इस सम्बन्ध में चीनी उद्योग से प्राप्त एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

Compensation To Bus Accident Victims

*319. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that compensation is paid to passengers involved in rail accidents;

(b) whether it is also a fact that no compensation is paid to the passengers involved in bus accidents;

(c) if so, the reasons therefor, and

(d) The action taken to pay adequate compensation to passengers involved in bus accidents ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes.

(b) to (d) There are provisions in chapter VIII of the Motor Vehicles Act, 1939, dealing with compulsory insurance of Moter Vehicles against third party risks, to ensure payment of compensation to victims of road accidents, or their legal heirs, where a decree is passed in their favour by a court of competent jurisdiction or where compensation is awarded by a Motor Accidents Claims Tribunal.

गेहूँ नीति सम्बन्धी कृषि मूल्य आयोग का प्रतिवेदन

*320. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदा नन्द :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग ने 1967-68 की फसल के लिए गेहूं सम्बन्धी नीति के बारे में अपने प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 527/67]**

(ख) और (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 528/67]

Committee to Study Land Requisition Laws

*321. **Shri Sidheshwar Prasad**
Shri Ram Kishan Gupta :
Shri Randhir Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to constitute a committee of the representatives of the Centre and States to consider the land requisition laws;

(b) if so, the terms of reference of the Committee; and

(c) the names of the members of the Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib. Shinde) : (a) Yes, Sir, The Hon. Member is perhaps referring the proposal of setting up of committee on Land Acquisition Act 1894.

(b) and (c) The matter is under consideration.

खाद्य पदार्थों को चोरी-छिपे ले जाना

* 322. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सिक्किम और दार्जिलिंग सीमाओं से अनाज, तेल, चीनी, नमक तथा अन्य खाद्य पदार्थों की चोरी छिपे चीन अधिकृत तिब्बत में ले जाने के मामलों में वृद्धि हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीनी एजेन्टों की सांठगांठ से भारतीय व्यवसायियों ने इन पहाड़ी क्षेत्रों में चोर बाजारी के कुछ केन्द्र स्थापित किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने चोर बाजारी करने वालों को पकड़ने, उन्हें शिक्षाप्रद दण्ड देने तथा इस प्रकार चोरी-छिपे माल ले जाने की वारदातों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। जहां तक सरकार को मालूम है यह सच नहीं है।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वाईकाउन्ट विमान

* 323. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966-67 में वाईकाउन्ट विमान चलाने के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को एक करोड़ और ग्यारह लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 1965-66 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा वाइकाउंट विमानों के परिचालन में 111.61 लाख रुपये का घाटा हुआ। मुख्य मार्गों (ट्रंक रूट्स) पर कारवेल विमानों का परिचालन प्रारंभ करने के कारण, वाइकाउंट विमानों को अधिकतर अल्पदूरी वाले क्षेत्रीय मार्गों पर परिवर्तित कर देना पड़ा। क्षेत्रीय मार्गों पर कम लदान होने के कारण आय में कमी हुई। यह और परिचालन-व्यय में वृद्धि, दोनों मिलाकर मुख्यतया इस घाटे के लिये उत्तरदायी हैं।

माल भाड़ा दरें

*325. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री रामकिशन गुप्त :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी जहाज-मालिकों के सम्मेलन में माल भाड़े की दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप भारत का आयात खर्च कितना बढ़ जाने की संभावना है; और

(ग) सरकारी स्तर पर तथा व्यापारिक स्तर पर हमारे व्यापार सन्तुलन पर होने वाले संभावित कुप्रभाव को रोकने के लिये, यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारत-यू.एस ए व्यापार करने वाली तीन निम्न कान्फ्रेंसों ने प्रत्येक के सामने सूचित तिथियों से अपने भाड़े की दर बढ़ाने का अभिप्राय घोषित किया है :

(१) वेस्टकास्ट आफ इंडिया और पाकिस्तान। यू एस ए कान्फ्रेंस	1-7.67
(२) ईस्ट कोस्ट आफ इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान। यू एस ए कान्फ्रेंस	11-7.67
(३) इंडिया, पाकिस्तान, सीलोन एण्ड बर्मा आउट बर्ड फ्रन्ट कान्फ्रेंस	1-7.67

प्रारंभिक प्राक्कलनों से सूचित होता है कि यदि प्रस्तावित दरें स्वीकार की गईं तो हमारे आयात बिल में 875000 डालर की वृद्धि होगी। सरकार द्वारा तथा विभिन्न व्यापार संगठनों द्वारा संबद्ध सम्मेलनों से विरोध प्रकट किया गया है। कान्फ्रेंसों के साथ इस मामले में बात-चीत की जा रही है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई

* 326. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री रा० ना० माइती :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री ग्र० कु० किस्कु :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना की दूध की सप्लाई कम हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार दूध के भाव बढ़ाने का है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के हजारों लोगों ने दिल्ली दुग्ध योजना से प्रार्थना की है कि उन्हें दूध दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांग पूरी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) कार्ड/टोकन वालों को दूध सप्लाई किया जा रहा है। दूध की कमी के कारण काउन्टर-बिक्री रोक दी गई थी ।

(ख) इस पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(1) दूध सप्लाई करने वालों के साथ फर्म के अनुबन्ध हुए जिसके अनुसार यदि विभिन्न मौसमों में दूध की स्वीकृत मात्रा को सप्लाई न हुई तो 5 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से जुर्माना होगा ।

(2) दूध सप्लाई करने वालों के कमीशन का दर जनवरी, 1967 से बढ़ा दिया गया है ।

(3) योजना का उपलब्धि क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। करनाल से लगभग 20 मील दूर हरियाणा में दूध की विभागीय उपलब्धि के लिए एक नया उपलब्धि क्षेत्र ले लिया गया है ।

(4) परिवहन को सरल बनाने तथा दूध एकत्रित करने के लिए 20 दूध गाड़ियां, 10 टैंकर तथा 5 जीप खरीद ली गई हैं ।

(5) दिल्ली दुग्ध योजना के मिल्क शैड के लिए एक सघन पशु विकास कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है ; इस कार्यक्रम के फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्रों में दूध उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना है ।

(6) दिल्ली प्रशासन द्वारा 17–5–67 से खोआ, रबड़ी, पनीर तथा दुग्ध पदार्थों के आयात, निर्माण तथा बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिससे योजना को दूध की सप्लाई कायम रखने में सहायता मिली है ।

पटसन धान, तथा मोटे अनाज के समर्थन मूल्य

***327. श्री मधु लिमये :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री काशीनाथ पाण्डे :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पटसन, धान और मोटे अनाज के नये समर्थन मूल्य घोषित किये हैं;

(ख) क्या ये मूल्य किसानों की उत्पादन लागत को ध्यान में रख कर निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों के खाद्य उत्पादन तथा वसूली अभियानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) न्यूनतम साहाय्य मूल्य जोकि गत वर्ष के मूल्यों की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर निर्धारित किये गये हैं, का खाद्य उत्पादन तथा अधिप्राप्ति अभियान पर अनुकूल असर पड़ने की आशा है ।

पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय

*** 328. श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री अ० कु० किस्कू :
श्री श्रीधरन :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आने वाले पर्यटकों से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय में कमी हो गई है;

(ख) क्या इस कमी का कारण रुपये का अवमूल्यन है; और

(ग) पर्यटन से आय बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डॉ० कर्णसिंह) : (क) और (ख) 1966 में और इससे आगे की अवधि में पर्यटकों से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय पर अवमूल्यन का यथार्थतः क्या प्रभाव पड़ा है। इसे किसी भी हद तक सही-सही बताना संभव नहीं है।

(ग) पर्यटन से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिए पर्यटन के आधारभूत उपादानों (इन्फ्रा-स्ट्क्चर) के विनिर्माण में तेजी लाने का विचार है। इसमें होटल आवास तथा परिवहन सुविधाओं का बढ़ाना, हवाई अड्डे की सुविधाओं में सुधार और यूरोप से चार्टर विमानों से आने वाले पर्यटकों को अधिक बड़ी संख्या में आकर्षित करने के लिए पर्यटक बिहार-स्थलों (रिजार्टेस) का विकास सम्मिलित है। विदेशों में प्रचार के प्रयत्नों को भी गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों रूपों से बढ़ाया जा रहा है।

हवाई अड्डों पर प्लेटफार्म टिकट

***329. श्री कृष्णमूर्ति :** **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री ना० स्व० शर्मा : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री शारदा नन्द : **श्री रामसिंह आयरवाल :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हवाई अड्डों पर प्लेटफार्म टिकट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी व्यवस्था क्यों की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डॉ० कर्णसिंह) : (क) से (ग) : जी, हां। पालम में यदि संभव हुआ तो पहली अगस्त, 1967 से परीक्षण के तौर पर एक योजना आरंभ करने का विचार है जिसके अनुसार हवाई अड्डे के देशीय (डोमेस्टिक) लौंजों में प्रवेश करने पर प्रति व्यक्ति 0.50 पैसे का एक मामूली शुल्क लिया जायेगा। इसका उद्देश्य मुलाकातियों, सैर करने वालों और अन्य व्यक्तियों के वर्तमान भारी आयात को, जिसके कि कारण यात्रियों के लिये सीमित मात्रा में उपलब्ध सुविधाओं पर बड़ा बोझ पड़ता है, कम करना है।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों से प्रव्रजन।

*** 330. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री मनीभाई जे० पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग प्रव्रजन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इसका भी पता है कि बहुत से प्रव्रजित व्यक्ति अपने परिवारों को छोड़कर भाग रहे हैं; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि इस प्रकार छोड़े गए परिवारों को कोई कठिनाई न हो ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : भारत सरकार को बिहार और उत्तर प्रदेश के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर लोगों के दूसरे स्थानों पर जाने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। दोनों राज्य सरकारों से वास्तविकता बताने के लिये कहा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति के कारण लोगों का कोई प्रव्रजन नहीं हुआ है। बिहार सरकार से सूचना प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Installation of Tube-Wells in South Bihar

1493. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether any work regarding the installation of exploratory tube-wells in the South Bihar areas, particularly in Patna and Gaya, has been carried out;

(b) if so, details thereof;

(e) if not, the reason for neglecting these areas; and

(d) the number of experimental tube-wells installed in various States during last one year ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) : (b) The Exploratory Tube-wells Organisation in the course of groundwater exploration drilled 6 exploratory bores in Gaya district, of which 2 proved successful. Subsequently, the Organisation drilled 106 production tubewells in the districts of Gaya, Patna and Shahabad as detailed below :—

District	No, of bores drilled	No. of bores proved successful
1. Gaya	76	61
2. Shahabad	20	19
3. Patna	10	10
Total.	106	90

(c) Does not arise, as besides exploration carried out in Gaya district, the Organisation is engaged in the construction of production tubewells in the drought affected areas of Shahabad and Gaya under which scientific data, similar to exlporation for the assessment of ground water potentiality of the region, may become available.

(d) During the last one year the Organisation has been engaged in the drilling of production tubewells mostly in the scarcity areas of Rajasthan, Gujarat and drought

affected areas of U. P. and Bihar. The details of production tubewells drilled by the Organisation during 1966-67 are as given below :

	State	Total number of bores drilled	Number of successful bores
1.	Bihar	78	66
2.	Delhi	8	8
3.	Gujarat	20	19
4.	Maharashtra	6	6
5.	Rajasthan	42	26
6.	U. P.	35	33
	Total -	189	158

हरियाना के लिये चीनी का कोटा

1494. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 से अप्रैल, 1967 तक हरियाना राज्य को चीनी का कितना कोटा दिया गया है, और

(ख) उपरोक्त अवधि में हरियाना ने कितनी चीनी मांगी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क)	जनवरी, 1967	—	5000	मीटर टन
	फरवरी, 1967	—	5000	,,
	मार्च, 1967	—	3600	,,
	अप्रैल, 1967	—	3600	,,

(ख) जनवरी और फरवरी में 6560 मीटरी टन प्रति मास और मार्च और अप्रैल, 1967 में 5000 मीटरी टन प्रति मास ।

ट्रैक्टरों के पुर्जों के आयात पर प्रतिबन्ध

1495. श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उचित तथा अत्यावश्यक मामलों में भी लाइसेंस देने में अनावश्यक विलम्ब किये जाने तथा पुर्जों के आयात पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाने के कारण सैंकड़ों ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ ट्रैक्टर फालतू पुर्जों आदि के अभाव के कारण बेकार पड़े हैं। फालतू पुर्जों के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) पुर्जों की आयात सम्बन्धी नीति निम्न प्रकार से उदार कर दी गई है :–

(1) एस्टेब्लिशड आयातकर्ता को बैस्ट ईयर के आयातों का 40 प्रतिशत तक कोटा लाइसैन्स की अनुमति है ।

(2) ट्रैक्टर पुर्जों की विशेष आवश्यकताओं के लिए ट्रैक्टर मालिकों की प्रार्थना पर विचार किया जाता है यदि उनकी आवश्यकताएं एस्टेब्लिशड आयातकर्ताओं से पूरी नहीं होती।

(3) आयातकर्त्ताओं को तदर्थ लाइसैन्स भी जारी किए जाते हैं।

(I) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इन शिकायतों को दूर करने के लिए कृषि निदेशालय में "सैल्ज" स्थापित करें।

(Ii) राज्य सरकारों द्वारा वर्कशाप सम्बन्धी सुविधाएं देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

देश में नलकूप

1496. श्री बाबूराव पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने नलकूप काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) एक नलकूप लगाने पर कितनी लागत आती है;

(ग) क्या कारण है कि नलकूपों का उपयोग नहीं किया जाता है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में नलकूप लगाने के लिए कितनी राशि नियत की गई है;

(ङ) विदेशी सहयोग से कितने नलकूप लगाये गये हैं; और

(च) कितने नलकूपों का पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है तथा उसके लिए शुल्क की दरें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क), (ङ) और (च) : राज्य सरकारों से जानकारी मांगी जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) नलकूप की खुदाई का व्यय उसके आकार, गहराई तथा उसकी खुदाई के स्थान पर निर्भर करता है। गैर सरकारी नलकूपों के लिए यह व्यय 5000 रुपए से 15000 रुपए प्रति नलकूप तक होता है जिसमें ड्रिलिंग, विकास, नलों व पम्प सैटों का व्यय भी शामिल है।

राजकीय नलकूपों पर आने वाला व्यय औसतन 1.00 लाख रुपए प्रति नलकूप है जिसमें ड्रिलिंग, विकास, पम्प हाऊस, पम्प, वायरिंग, नलकूप जल ट्रान्समिशन तथा बिजली की व्यवस्था शामिल है ।

(ग) नलकूपों के काम में न लाने का मुख्य कारण नलकूप के स्थान पर बिजली का न होना तथा उचित फीडर चैनलों व पम्प सैटों का उपलब्ध न होना है ।

(घ) मौजूदा तरीके के अनुसार राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता "लघु सिंचाई के मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत दी जाती है न कि इस शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली नलकूप आदि अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग रूप से । फिर भी योजना आयोग के सलाहकारों द्वारा विभिन्न राज्यों का दौरा करने के पश्चात ही 1967–68 के लिए लघु सिंचाई कार्यक्रमों के आकार के विषय में अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

पर्यटकों के लिये विमान चार्टर करना ।

1497 श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को 50 अवसरों पर पर्यटकों के लिये विमान चार्टर करना अस्वीकार करना पड़ा जिससे लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) पिछले दो महीनों में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने पर्यटकों के लिए एक भी अवसर पर विमान चार्टर करना अस्वीकार नहीं किया ।

हरियाना में खाद्यान्न के मूल्य

1498. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई फसल आने के बावजूद हरियाना राज्य में खाद्यानों के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नई फसल के आने से, मार्च और अप्रैल, 1967 में हरियाना राज्य में गेहूं और चने के बाजार भावों में गिरावट आयी है । केवल मई, 1967 के महीने में इन खाद्यान्नों के भावों में इस महीने की 18 तारीख तक बढ़ोतरी का रुख रहा लेकिन इसके बाद इन भावों में गिरावट की प्रवृति आयी है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

खाद्यान्न की आवश्यकता

1499. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की खाद्यान्न की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) कितने प्रतिशत लोगों को खाद्यान्न की आवश्यकता होती है ;

(ग) देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की दैनिक आवश्यकता कितनी है; और

(घ) क्या यह आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रीय मानक से अधिक है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) प्रत्येक मनुष्य की खाद्यान्नों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है,इस सम्बन्ध में कोई अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित नहीं है । प्रत्येक देश में खाद्यान्नों की खपत भिन्न-भिन्न है ।

(ख) भारत में प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न चाहिये ।

(ग) भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की दैनिक आवश्यकता भी समान नहीं है । मनुष्य की खाद्यान्नों की आवश्यकता उसकी आय, भोजन सम्बन्धी आदत, क्या वह व्यक्ति ग्रामीण अथवा कस्बा या शहर आदि में रहता है, पर निर्भर करती है ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मानक तथा भारतीय मानक के न होने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि भारतीय मानक अन्तर्राष्ट्रीय मानक से अधिक है ।

जहाज तथा उनका टन भार

1500. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को भारत में किस किस श्रेणी के कितने जहाज थे तथा उनकी टन भार क्षमता कितनी थी,

(ख) विभिन्न नौवहन समवायों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक समवाय के पास अथवा उनके नियंत्रणाधीन जहाजों की संख्या और टन भार क्षमता कितनी है; और

(ग) उन भागों तथा देशों के नाम क्या है जहाँ ये जहाज जाते हैं और उनका समवाय-वार व्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी०के०आर०वी०राव) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाले तीन विवरण संलग्न हैं । [**पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 529/67**]

भारतीय खाद्य निगम ।

1501.**श्री बाबूराव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने, जब से यह बना है तब से अब तक कितने अनाज की वसूली और वितरण किया है; और

(ख) देश की विषय खाद्य स्थिति सुलझाने में भारतीय खाद्य निगम ने क्या सहयोग दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने अपने अस्तित्व में आने से 30–4–1967 तक लगभग 26.5 लाख मीटरी टन खाद्यान्न खरीदे हैं। निगम विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की खरीददारी का काम या तो राज्य सरकारों की ओर से या अन्य राज्यों को निर्यात करने के लिये करता है। इस अवधि में निगम द्वारा वितरित की गई खाद्यान्नों की मात्रा के ब्यौरे अभी प्राप्त होने हैं।

(ख) खाद्य निगम की स्थापना खाद्यान्नों की खरीददारी और वितरण करने के लिये सरकारी क्षेत्र की एक एजेन्सी के रूप में कार्य करने के लिये की गयी है जो कि देश की खाद्य समस्या हल करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों में केवल एक उपाय है।

Crop Credit Scheme

1502. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether crop loans scheme has been implemented in all the States of the country; and

(b) if so, the names of those States and since when it has been implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community, Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) : and (b) : A statement is appended.

Progress in implementation of Crop Loan System

1. Andhra Pradesh	Implemented from Kharif 1966.
2. Assam	Beginning has been made in IADP and HVP areas.
3. Bihar	Beginning has been made in IADP and HVP areas. The scheme is to work throughout the State from Kharif 1967.
4. Gujarat	Crop loan system in operation for a long time.
5. Jammu & Kashmir	Beginning has been made in IADP and HVP areas.
6. Kerala	Implemented from Rabi 1966.
7. Madras	Crop loan system in a modified form is in operation.
8. Madhya Pradesh	Implemented from Kharif 1966 in certain districts and in other districts from Rabi 1966.
9. Mysore	Introduced from Kharif 1966 in some districts.
10. Maharashtra	Crop loan system in operation for a long time.
11. Orissa	Introduced partially in selected districts in Kharif 1966 and being implemented throughout the State from Kharif 1967.
12. Punjab & Haryana	The scheme in a modified form introduced from Kharif 1966.
13. Rajasthan	Introduced from Kharif 1966.
14. Uttar pradesh	Implemented from Kharif 1966 in HVP areas and being introduced in other areas from Kharif 1667.
15. West Bengal	Partially implemented in 2 districts form Kharif 1966 and being extended to the entire State from Kharif 1967.
16. Nagaland	No decision, yet to introduce the system.

दिल्ली में सड़क कर फीस की उगाही

1503. **श्री डी० एन० देव** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गाड़ियों के मालिकों को दिल्ली के डाकखाने में सड़क कर जमा करने की सुविधा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कब तक अमल किये जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में पंजीकृत की हुई समस्त मोटर गाड़ियों पर, डाकघरों के द्वारा कर वसूल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

(ख) चूंकि प्रशासनिक तथा अन्य कई बातें तय की जाती हैं । अतः अभी यह कहना संभव नहीं है कि वह कब से चालू किया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल को मछली की सप्लाई

1504. **डा० रानेन सेन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित भारतीय मत्स्य निगम ने दिसम्बर 1965 से दिसम्बर 1966 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल को कितनी मछली सप्लाई की थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : दिसम्बर, 1965 से दिसम्बर, 1966 तक की अवधि में केन्द्रीय मत्स्य निगम ने पश्चिम बंगाल को 8,19,047 किलोग्राम मछली सप्लाई की थी ।

Bridge at Patna over River Ganga

1505. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) when the proposal to construct a bridge at Patna over the river Ganges was made and the cost of the bridge estimated at that time;

(b) the number of times the construction of the proposed bridge was considered during the first three Five Year Plans;

(c) whether it is a fact that every time when the proposal was considered, the estimated cost of the bridge was assessed higher; and

(d) the estimated cost of the bridge assessed now ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (d) The proposed bridge falls on a State Road. The Government of Bihar are, therefore, primarily concerned with all matters pertaining to this project. The scheme for the construction of this bridge has been under investigation and study by the engineers of the State since 1940. They have, however, not been able to finalise any scheme so far because it is dependent upon the selection of a suitable site, which is still under investigation. Recently, the State Government intimated that the bridge might cost about Rs. 25 crores. Prior to this, no estimates of cost were received from the State Government.

Import of Rice

1506. Shri Valmiki Choudhary :
Shri Kashi Nath Pandey :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to import rice from abroad during 1967-68; and

(b) if so, the amount of foreign exchange earmarked for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The amount of free foreign exchange likely to be required is about Rs. 50 crores.

Legal Education Council

1507. Shri Ramchandra Veerappa : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether the jurists and legal experts have suggested that a separate Legal Education Council should be set up to improve the standard of legal education and to bring about uniformity in the syllabus; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) (a) No such suggestion has come to the notice of the Government.

(b) Does not arise.

खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार

1508. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के पास खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें इस समय कितना खाद्यान्न जमा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : भारत सरकार के पास 21 मई, 1967 को खाद्यान्नों का कुल स्टाक 3,56,000 मीटरी टन से थोड़ा ज्यादा था।

बिहार में सहायता कार्यों के लिए अमरीका का उपहार

1509. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री अजगल खां :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सहायता कार्यों के लिये अमरीका की सरकार ने भारत को कोई विशेष उपहार भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने भारत सरकार को सूचित किया है वे बिहार में "केयर" तथा अन्य कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संगठित किए गये आपात फीडिंग कार्यक्रमों के लिये विभिन्न वस्तुएं भेज रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य सरकार बिहार में जनसंख्या के जरूरतमन्द वर्गों में मुफ्त बांटने के लिये 72,000 मीटरी टन बालाहार (अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य) बनाने के लिए एक प्रायोजना में सहयोग दे रही है। इसके लिए उन्होंने लगभग 50,000 मीटरी टन कार्नमील और लगभग 9,000 मीटरी टन सलाद तेल मुफ्त सप्लाई करना है। बालाहार तैयार करने के लिये देश में से लगभग 17,850 मीटरी टन मूंगफली के आटे की व्यवस्था की जाएगी और संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने इस प्रायोजना में इस्तेमाल करने के लिए मूंगफली के आटे के मूल्य के बराबर मूल्य की माइलो अथवा अन्य खाद्यान्न देना मान लिया है।

संयुक्त राज्य सरकार ने बिहार में पीने का पानी कार्यक्रम के लिए रिगो को चलाने के लिए 25,000 डालर के फालतू पुर्जे मुफ्त सप्लाई किये हैं। उन्होंने 26 पेडोजेट इंजक्टर और कुछ मात्रा में चेचक के टीके भी दिये हैं।

Sugar Supply to Bihar

1510. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the monthly quota of sugar supplied to Bihar State from January, 1966 to April, 1967;

(b) the quantity of sugar demanded by Bihar State during the above period; and

(c) the quantity of sugar proposed to be supplied monthly for May, June and July, 1967 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a)	January, 1966 to March, 1966	14,025 tonnes per month
	April, 1966 to February, 1967	14,918 ,, ,, ,,
	March, 1967	11,000 ,,
	April, 1967	12,000 ,,

(b) The Government of Bihar wanted that its monthly quota be continued at 14,918 tonnes.

(c) As in case of other States the monthly sugar quota of Bihar has been reduced. The quota will be 9,192 tonnes from May onwards. However, as suggested by Bihar Government, the monthly allotments have been phased out within the total quantity earmarked for Bihar upto October. Figures for allotments from May to July are as under.

May, 1967	12,000 tonnes
June, 1967	8,230 ,,
July, 1967	7,230 ,,

अमरीका में भारतीय वैज्ञानिक

1511. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि अनुसन्धान के क्षेत्र में अमरीका में अब कुल कितने भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे है;

(ख) वे वहां कितने समय से हैं और क्या उन्हें भारत वापस लाने के लिए कोई प्रयास किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उन वैज्ञानिकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नेशनल रिजिस्टर ऑफ साइंटिफिक परसोनल के आंकड़ों के अनुसार 1-1-67 को अमरीका में कृषि अनुसन्धान के क्षेत्र में 29 ऐसे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जिन्हें कृषि में डाक्ट्रेट की डिग्री प्राप्त है।

(ख) वे औसतन 3 वर्ष तक बाहर रहेंगे। उनमें से 26 को वैज्ञानिकों के पूल में स्थान पेश किये गये हैं। एक व्यक्ति इस पूल में दिलचस्पी नहीं रखता। अन्य व्यक्तियों के मामले पूल के विचाराधीन हैं।

(ग) 11 व्यक्तियों ने पूल की पेशकश स्वीकार कर ली है। एक व्यक्ति देश में आया, यहां कुछ समय पूल अधिकारी के रूप में काम किया और वापस चला गया। अन्य व्यक्तियों से उत्तरों की प्रतीक्षा है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मछली उद्योग का विकास

1512. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री जनार्दनन :
श्री अविचन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मछली उद्योग का आधुनिक आधारों पर विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ। एक प्रारूप योजना तैयार की गई है।

(ख) योजना में समुद्रीय तथा अन्तर्देशीय मात्स्यकी शामिल है। समुद्रीय मात्स्यकी के विकास सम्बन्धी योजनाएं मुख्यतया फिशिंग बोटों के यंत्रीकरण से, बड़े फिशिंग टालर्स चलाने के और आइस प्लाण्ट, शीत भण्डारों एव प्रोसैसिंग प्लान्टों की स्थापना से सम्बन्धित हैं। इस योजना में फिशिंग बन्दरगाहों और प्रशीक्षित सड़क एवं रेल परिवहन जैसी अनुषंगी सुविधायें भी आतां हैं। यंत्रीकृत नावों, प्रक्रिया तथा अन्य सम्बन्धित विषयों के बारे में अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। समुद्रीय मछली उद्योग के विकास के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलु गहरे समुद्र की मछलियों को खोजना है। अन्तर्देशीय मत्स्यकी योजनाओं में मछलियों के लिए जल क्षेत्रों का सुधार, फिश सीड का उत्पादन तथा वितरण, विशिष्ट तकनीकों द्वारा मछली प्रजनन और रिजंवायर फिशिंग का विकास शामिल है। अन्तर्देशीय मत्स्यकी में अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है।

(ग) योजना की अनुमानित लागत 113 करोड़ रुपये है। उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए खर्च में संशोधन किया जा सकता है।

कोयम्बटूर अट्टापड़ी-मन्नकरकड़ आदिम जातीय क्षेत्र

1513. श्री अ० क० गोपालन : **श्री नायनार :**
श्री राममूर्ति : **श्री उमानाथ :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी घाट रोड में कोयम्बटूर-अट्टापड़ी-मन्नारकड आदिम जातीय क्षेत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) और (ख) : केरल सरकार ने अत्तापदी और चिन्नथादागम होते हुए मन्नारकड–कोयम्बटूर सड़क के के० एम० 0/0 से 52/1 अनुभाग तक सुधार प्रस्तावित किया है। यह अंशतः केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य आरक्षित) से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया जायेगा। इस सम्बन्ध में हम केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य आरक्षित) से कार्य के प्रतिमान आधार पर अनुमोदन की दृष्टि से राज्य सरकार से और अधिक सूचना संकलित कर रहे हैं।

खाद्य तेलों के मूल्य

1514. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के मूल्य बराबर बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जनवरी 1965 से मई 1967 तक की अवधि के बारे में खाने के तेलों के विषय

में सांख्यिकीय सलाहकार द्वारा दिये गये थोक मूल्यों के सूचकांक (जिनमें 1952-53=100 माना गया है) नीचे दिये जाते हैं। इनसे प्रतीत होता है कि सूचकांक 254 तथा 325 के मध्य रहे हैं और अन्तिम सप्ताह अर्थात् 13 मई 1967 के लिए सूचकांक 318 था।

खाने वाले तेलों के थोक मूल्यों का सूचांक अंक

(1952-53—100)

1966			
	जनवरी		253.9
	फरवरी		249.1
	मार्च		258.0
	अप्रैल		275.7
	मई		301.5
	जून		306.7
	जुलाई		309.3
	अगस्त		325.4
	सितम्बर		303.3
	अक्तूबर		294.4
	नवम्बर		283.7
	दिसम्बर		294.1
1967			
	जनवरी		312.3
	फरवरी		324.1
	मार्च		316.6
	अप्रैल	1	307.0
		8	311.2
		15	316.5
		22	316.0
		29	319.4
	मई	6	318.4
		13	318.1

(ख) खाने के तेलों के मूल्यों में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि 1965-66 तथा 1966-67 में तिलहनों व तेलों की कम सप्लाई हुई है।

(ग) मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं: तेल के बीजों व तेलों के लिए बैंकों द्वारा अग्रिम धन देने पर प्रतिबन्ध लगाना, मण्डियों में तेल के लेन-देन को नियन्त्रित करना, निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना, तेलों के आयात को बढ़ाना तथा औद्योगिक कामों के लिए खाने के तेलों के प्रयोग को हतोत्साहित करना। देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

बिहार के चीनी के कोटे में कटौती ।

1515. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री हेमराज :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार का अप्रैल, 1967 महीने का चीनी का कोटा 14,000 टन से घटा कर 11,000 टन कर दिया गया है;

(ख) क्या अन्य राज्यों के चीनी के कोटे में भी इसी प्रकार कटौती की गई है;

(ग) क्या मई, 1967 में कटौती पूरी कर दी गई है और जून, 1967 में पूरी करने का विचार है; और

(घ) अप्रैल, 1967 के कोटे में राज्यवार कितनी कटौती की गई है तथा राज्यवार मई और जून, 1967 के बारे में क्या अनुमान हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) 23 मई, 1967 से बिहार का कोटा घटाकर 9,192 मीटरी टन कर दिया गया था । बिहार सरकार की सुविधानुसार माल भेजा जायेगा, किन्तु, कम उत्पादन होने के कारण कोटा बहाल करना सम्भव नहीं है ।

(घ) अप्रैल, मई और जून, 1967 में प्रत्येक राज्य का चीनी का मासिक कोटा बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 530/67]**

ROAD ACCIDENTS IN DELHI

1516. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of persons killed or injured in the road accidents in Delhi during the year 1966-67 as compared to 1965-66, and

(b) the steps taken to prevent such accidents ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) 356 persons were killed and 3162 injured in road accidents in Delhi during the period 1st April, 1966 to the 31st March, 1967 as compared to 317 persons killed and 3199 persons injured during the period 1st April, 1965 to the 31st March, 1966.

(b) The following steps have been, or are being, taken to prevent road accidents in Delhi :—

(i) Separate staff, under the supervision of a Sub—Inspector, has been detailed for road safety education since December, 1962.

(ii) Pamphlets and drawings on road safety have been distributed amongst children and other road users.

(iii) Films on road safety are shown in various schools.

(iv) Cautionary sign-boards have been fixed near almost all the schools situated on road sides for cautioning motorists.

(v) Pedestrian crossings have been marked on roads near schools at suitable places. Boards indicating pedestrian cross-walks have also been fixed at these places.

(vi) Speed restrictions have been imposed in congested areas, especially where schools are situated.

(vii) Lectures on road safety and instructions on traffic rules are given regularly in educational instituions. Practical demonstrations on roads have also been given for the benefit of students.

(viii) With the assistance of M/s Burmah Shell oil Storage and Distributing Co., a Traffic Training Park has been built on Irwin Road, New Delhi. It has been functioning since March, 1964. In the morning hours, school children are given training in this Park by Traffic Police, according to a fixed programme. In the evenings, the Park is open to all children of a specified age group.

(ix) Major roads are being widened and automatic traffic signals installed, wherever necessary. Cycle tracks have also been provided on some roads. Bus stops, stalls, vendors, taxi stands, etc. are being removed from the congested areas.

Stock-taking in Super Bazar, New Delhi

1517. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that proper stock accounts are not maintained in the Super Bazar, New Delhi ;

(b) if so, the improvements made therein; and

(c) the result of the last stock-taking in the Super Bazar ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) : It is not a fact that proper stock accounts are not being maintained in the Super Bazar. However, owing to its large daily turn over, there might have been some discrepancies. The Super Bazar is taking adequate precautions to set things right through a system of machine accounting.

(c) The last stock taking was done in December 1966 but the results, which showed an excess of physical stock over book balances, were not accepted by the Board of Management. A fresh stock taking is being done and will be completed by the 30th of June, 1967.

Purchase Officers in Super Bazar, New Delhi

1518. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Purchase Officers in the Super Bazar, New Delhi ;

(b) the scales of pay of the Purchase Officers and the number of Departments for which each of them make purchases ; and

(c) their previous experience regarding purchases and the mode of their recruitment ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) (a) and (b) : There are no separate purchase Officers. The Department Managers, who are 12 in number, make purchases of commodities sold in their departments under the guidance and supervision of the General Managers. Posts of Department Managers carry a pay scale of Rs. 650–50–1100.

(c) The Department Managers were recruited by a Selection Committee set up by the Board of Management of the Super Bazar, New Delhi on the basis of their previous experience and knowledge of merchandising.

मध्य प्रदेश में वन पर आधारित उद्योग

1519. श्री हुकमचन्द कछवाय : श्री नीतिराजसिंह चौधरी :
श्री रामसिंह आयरवाल : श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समझौते की शर्तों के अनुसार खाद्य तथा कृषि संगठन की मध्य प्रदेश पूर्व विनियोजन अध्ययन परियोजना में मध्य प्रदेश में, जिसमें बस्तर क्षेत्र भी शामिल है, वन पर आधारित उद्योगों के संशोधनों का सर्वेक्षण तथा उन्हें स्थापित करने की सम्भावना का अध्ययन करना भी शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्तावित अध्ययन में बस्तर क्षेत्र में कागज लुगदी उद्योग भी शामिल है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जी हां ।

देशी गेहूं का स्टाक

1520. श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री यशवन्तसिंह कुशवाह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 28 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस समय देशी गेहूँ स्टाक कर रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में देशी गेहूँ का वितरण कब किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) ये कहां कहां से प्राप्त किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : सरकार पंजाब से गेहूँ की अधिप्राप्ति कर दिल्ली में देशी गेहूँ का कुछ भंडार बनाना चाहती है। ज्योंही कुछ उपयुक्त स्टाक हो जायेगा त्योंही देशी गेहूँ का वितरण शुरू कर दिया जायेगा।

Loan to Farmers

1521. Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Onkar Singh : Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the details of the scheme under which Government propose to give a loan of Rupees one crore to the farmers ; and

(b) when this amount is likely to be distributed ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : There is no such scheme of giving loan of Rupees one crore to farmers. The question of giving details of the scheme and the time when the amount is likely to be distributed does not, therefore, arise.

कुमारकाम वेलचूर सड़क

1522. श्री श्रीकान्तन नायर : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमारकाम-वेलचूर सड़क को केन्द्रीय सड़क निधि योजना में सम्मिलित किया गया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने 10 नवम्बर, 1958 को दो निर्माण कार्यों के लिये मंजूरी दी थी, जिनमें से एक पूरा हो चुका है ;

(ग) क्या दूसरे निर्माण-कार्य के लिये सरकार ने पुनरीक्षित प्राक्कलन मांगा था, जो 9,44,000 रुपये बताया गया; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत उन दो स्कीमों से है जिनमें एक सड़क कार्य से और दूसरी पुलों से सम्बन्धित हैं और जो क्रमशः 19-11-1958 और

16–12–1960 को प्रत्येक 4 लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर अनुमोदित की गई थी। इन दोनों स्कीमों में से प्रत्येक में कुछ कार्य पूरा हो गया है। इनमें 3·07 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

अब राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दोनों स्कीमों को पूरा करने के लिये 9·42 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी और उन्होंने पुनरीक्षण के लिये अनुमोदन मांगा है। मामले पर राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

सघन कृषि जिला कार्यक्रम

***1523. श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में सघन कृषि कार्यक्रम वाले विभिन्न जिलों में अनाज के उत्पादन में हुई वृद्धि के कोई सही आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न जिलों में उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिलों में 1961–66 तक के पांच वर्षों में प्रायः खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। हां सूखे व प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कुछ कमी भी हुई है। विभिन्न जिलों में कार्यक्रम के शुरू होने से पहले की 3 वर्षों की अवधि में औसत खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह सलंग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 531/67**]

चीनी मिलों को राज सहायता

1524 **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में चीनी मिलों को कुल कितनी राज सहायता दी गई है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में चीनी मिलों से कुल कितना उपकर वसूल किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चीनी निर्यात की व्यवस्था भारत सरकार करती है और उसकी अधिप्राप्ति मिलों से की जाती है। मिलों से खरीदी गयी कच्ची चीनी का ठेका मूल्य दिया जाता है।

(ख) राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में कारखानों से उपकर (गन्ना) वसूल करती हैं जिसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

पारादीप पत्तन

1525 **श्री प्र० के० देव :** **श्री अ० दीपा :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री गु० च० नायक :**
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पारादीप पत्तन का हाल ही में निरीक्षण किया है और वहां पर माल गोदाम (कार्गो बर्थ) बनाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो माल गोदाम बनाने का कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली में जरूरी कार्य के कारण मुझे अप्रैल 1967 में पत्तन की यात्रा करने का अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा ।

(ख) यातायात अध्ययनों, जो अब हो रहे हैं, के पूरा होने के बाद इस पर विचार किया जायेगा ।

कोणार्क (उड़ीसा) में पर्यटन की सुविधाएं

1526. **श्री प्र० के० देव :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोणार्क में पर्यटन सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जी हां । कोणार्क को अनुमानतः 42·50 लाख की लागत से तटवर्ती पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना है । योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । इसको चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जायेगा ।

सूखा निरोधक अध्ययन बोर्ड

1527. **श्री शारदा नन्द :** **श्री भारत सिंह :**
श्री ज० ब० सिंह : **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निरन्तर सूखे को देखते हुए सरकार का विचार सूखा निरोधक अध्ययन बोर्ड स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बोर्ड के निर्देशपद तथा सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) यह बोर्ड कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। सूखे के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त मशीनरी की स्थापना का प्रश्न कुछ समय तक विचाराधीन रहा। यह निर्णय किया गया है कि यह कार्य खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग), सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय के एककों को सौंप दिया जाये। इस कार्य का समस्त समन्वय कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। अतः कृषि विभाग के एक विशेष सैल को यह कार्य सौंप दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में वन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

1528. श्री डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि की सहायता से पश्चिम बंगाल में वन शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) से (ग) भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से देश 4 खण्डों में लट्ठे बनाने के काम में प्रशिक्षण देने के 4 केन्द्रों की स्थापना करने के विषय में एक परियोजना पर कार्य कर रही है। पश्चिम बंगाल में सुकना नायक स्थान पर पूर्वी क्षेत्र के लिए लट्ठे तैयार करने के कार्य में प्रशिक्षण देने का एक केन्द्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र में राज्य स्थापित किया गया है। इस केन्द्र में राज्यों के वन विभागों तथा फारेस्ट लैसीज द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को लट्ठे बनाने के मूल कार्य में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मैरीन टैक्नोलाजीकल डिप्लोमा कोर्स

1529. श्री अ० क० गोपालन : **श्री नायनार :**
श्री राम मूर्ति : **श्री उमानाथ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में थवानूर रूरल इंस्टीच्यूट में मैरीन टैक्नोलाजीकल डिप्लोमा कोर्स आरम्भ करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त इंस्टीच्यूट के लिए इस वर्ष धन नियत करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

राजस्थान में आयातित खाद्यान्नों की सप्लाई

1530. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य को प्रति वर्ष कितनी मात्रा में आयातित खाद्यान्न दिया जाता है;

(ख) पिछले छः महीनों में उस राज्य को कितनी मात्रा में आयातित खाद्यान्न दिया गया; और

(ग) पिछले छः महीनों में राज्य सरकार ने कितने खाद्यान्न की मांग की थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) किसी भी राज्य के लिए आयातित खाद्यान्नों का कोई निर्धारित कोटा नहीं है। राजस्थान को गत तीन वर्षों में आयातित खाद्यान्नों की की गई सप्लाई की मात्रा इस प्रकार थी :—

		(हजार मीटरी टन में)
1964	—	493·5
1965	—	187·1
1966	—	543·2

(ख) दिसम्बर, 1966 से मई, 1967 तक 2 लाख मीटरी टन से थोड़ा अधिक।

(ग) 4 लाख मीटरी टन।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय के सचिव तथा महानिदेशक, पर्यटन

1531. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री श्रीधरन :
श्री मधु लिमये :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन के महा-निदेशक और उनके मन्त्रालय से सचिव के पद काफी दिनों से रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन पदों को भरने का है तथा यदि हां, तो कब ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। 1 जून, 1967 तक भारत सरकार के परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय के सचिव, पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्रालय के सचिव और पदेन पर्यटन के महानिदेशक भी थे।

(ग) पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्रालय के एक अलग सचिव ने 2 जून, 1967 को अपने पद का कार्यभार संभाला। एक पूर्णकालिक पर्यटन-महानिदेशक की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए मकान बनाना

1532. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान बनाने के ठेके देने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए 55 लाख रुपये की लागत के मकान बनाने का विचार है; और

(ग) क्या इस काम के लिये टेंडर मांगे गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वार्टर बनाने के ठेके देने की प्रक्रिया–प्रसिद्ध फर्मों टेंडर मांगना है।

(ख) 78.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से विभिन्न आकार (साइज) के लगभग 300 क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है।

(ग) जी, हां।

वनरोपण योजना

1533. **श्री दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष देश में वनरोपण योजना में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राज्यों व संघ क्षेत्रों से पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अकाल संहिता

1534. श्री राम मूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में अकाल संहिता लागू किए जाने के परिणामों के सम्बन्ध में विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो अकाल संहिता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : बिहार अकाल तथा बाढ़ सहायता संहिता, 1957 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी है और संकट की जब आशंका होती है तथा जब वह संकट गम्भीर हो जाता है, तब राज्य सरकार द्वारा जो उपाय किए जाते हैं वे इस संहिता में दिए गये हैं। अकाल की घोषणा से यह अभिप्राय नहीं है कि संकट का मुकाबला करने के लिए सरकार पर कोई नया दायित्व आ पड़ता है। यह तो इस बात की एक स्वीकारोक्ति है कि संकट काफी अधिक अनुपात में बढ़ गया है जिसके लिये सुधारात्मक उपाय बढ़ाने, और अधिक निधि की व्यवस्था करने और इसके फलस्वरूप स्थिति के बारे में अधिक व्यौरावार तथा निरन्तर रिपोर्ट मंगवाने की आवश्यकता होती है।

बिहार सरकार को इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए दी गयी सहायता बताने वाला एक विवरण अतारांकित प्रश्न संख्या 789 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में 30-5-67 को सभा के पटल पर रख दिया गया है। केन्द्रीय सरकार राज्य को सभी सम्भव सहायता बराबर सुलभ करती रहेगी।

कृषि विकास के लिए पश्चिम जर्मनी से सहायता

1535. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी कृषि को विकसित करने में अब तक पश्चिमी जर्मनी ने कितनी सहायता दी है; और

(ख) क्या मण्डी की भांति अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन-परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जहां तक मण्डी में कृषि विकास के लिए पश्चिम जर्मनी की सहायता का सम्बन्ध है, सहायता की कुल राशि 50.40 लाख रुपये है।

(ख) मण्डी परियोजना को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले तक विस्तृत कर दिया गया है और मद्रास राज्य के नीलगिरी जिले में हाल ही में एक नई परियोजना शुरू की गई है ।

बीज फार्म

1536. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से सिफारिश की है कि भारत में बीज फार्म स्थापित करने के लिए गैर–सरकारी फार्मों को ऋण दे; और

(ख) क्या सरकार ने उन शर्तों पर विचार किया है जिन पर यह ऋण दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जी नहीं । विश्व बैंक की ओर से गैर सरकारी फर्मों को बीज फार्मों की स्थापना के लिए ऋण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Air Accidents

1537. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri R. S. Vidyarthi :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the number of deaths due to air crashes during the last five years;
(b) the reasons therefor; and
(c) the steps taken to avoid recurrence in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) - Two statements giving requisite information in respect of fatal air crashes (1) which occurred in India and (2) which occurred to Indian registered aircraft outside India, are attached. [Placed in Library. See No. Lt. 532/67]

(c) Investigation as appropriate to the nature of the accident is carried out in each case and suitable remedial measures are taken on the basis of the recommendations of the investigating officer.

सुपर बाजार नई दिल्ली में सस्ती कीमत वाली वस्तुएं

1538. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार नई दिल्ली ने निकट भविष्य में प्रमुख व्यापार गृहों के सहयोग से सस्ती कीमत वाली उपभोक्ता वस्तुएं बनाने की एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जी नहीं । सुपर बाजार, नई दिल्ली ने कम कीमत वाली उपभोक्ता वस्तुएं बनाने के लिए किसी भी व्यापार गृह के सहयोग से कोई योजना नहीं बनाई है । इसने

केवल बम्बई की एक फर्म से मीडियम वेव ट्रांजिस्टर रेडियोंत तथा दिल्ली की एक अन्य फर्म से आई० एस० आई० स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार कम कीमत वाले प्रेशर कुकर्स की सप्लाई के लिए प्रबन्ध किया है ।

दिल्ली परिवहन का पुनर्गठन

1539. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन का पुनर्गठन करने के बारे में कोई योजना है जिससे वह अधिक लाभदायक तथा प्रभावी ढंग से काम कर सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : दिसम्बर, 1966 में निम्न सदस्यों का कार्य अध्ययन दल गठित किया गया था :—

(1) श्री आर० एस० कृष्णन, वित्तसचिव, दिल्ली प्रशासन दिल्ली—अध्यक्ष

(2) श्री यू० एस० श्रीवास्तव, परिवहन के निदेशक दिल्ली सदस्य

(3) श्री ए० एस० खान, अतिरिक्त महाप्रबन्धक दिल्ली परिवहन संस्थान सदस्य (संयोजक)

कार्य अध्यक्ष दल के विचारार्थ विषय निम्न है :—

1. यातायात में वृद्धि के कारण दिल्ली के केन्द्रीय क्षेत्र की सड़क परिवहन आवश्यकताओं का निर्धारण करना ।

2. ग्रामीण क्षेत्रों सहित क्षेत्र की सड़क परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रस्तावों का अध्ययन ।

3. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए दिल्ली परिवहन संस्थान द्वारा तैयार किए गए विस्तार कार्यक्रम की परीक्षा ।

4. मौजूदा चालन की लागत से वर्तमान भाड़ा संरचना के संबंध का अध्ययन और चालन के लागत में वृद्धि के कारण दिल्ली परिवहन संस्थान के बस भाड़ा संरचना को दोहराने की आवश्यकता है या नहीं इस पर सिफारिश करना ।

5. बगैर टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए प्रबन्ध को दोहराना और परीक्षण करना और संस्थान की आमदनी के लिए उपायों का सुझाव ।

6. संस्थान को दिए हुए ऋण की ठीक उपयोगिता के विशेष संदर्भ में संस्थान की वित्तीय स्थिति की परीक्षा यदि जरूरत हो तो दूर करने के उपायों का सुझाव देना ।

7. विचाराधीन विषयों पर लाभदायक कोई और सिफारिश करना ।

दल की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

दिल्ली परिवहन संस्थान की जगह एक संवैधानिक सड़क परिवहन निगम होने का निर्णय ले लिया गया है । यह निगम सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अधीन स्थापित किया जायेगा । सड़क परिवहन निगम (संशोधित) बिल 1966 लोकसभा में अगस्त, 1966 में पेश किया गया था और इसे फिर से संसद में पेश करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

तीसरी लोक सभा के भंग हो जाने के कारण बिल समाप्त हो गया है ।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन से वाईकाउंट विमानों को हटाया जाना

1540. श्री मोहन स्वरूप :	**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री यश पाल सिंह :	**श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :	**श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से वाईकाउंट विमान हटाने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब वह निर्णय बदल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णी सिंह) : (क) से (घ) : यह प्रश्न, कि क्या आई० ए० सी० के विमान बेड़े के वाईकाउंट विमानों को बदला जाना चाहिए और यदि हां तो उनकी जगह पर किस किस्म के विमान रखे जाने चाहिएं, विचाराधीन है ।

Prices for Rabi Crops

1541. Shri Mohan Swarup :	**Dr. Karni Singh :**
Shri D. C. Sharma :	**Shrimati Nirlep Kaur :**
Shri D. S. Patil :	**Shri Kikar Singh :**
Shrimati Sharda Mukerjee :	**Shri Barrow :**
Shri Jagannath Rao Joshi :	**Shri Kolai Birua :**
Shri Swell :	

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have made any recommendations to the wheat-growing States in regard to the fixation of prices for rabi crops;

(b) if so, the nature of recommendations made; and

(c) whether any final decision has been taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c) : The procurement prices of rabi crops for the season 1967-68 were discussed in the Chief Ministers Conference during April, 1967 in the light of the recommendations made by the Agriculture Prices Commission. In accordance with the recommendations of the Conference and in

consultation with the State Governments concerned, the procurement prices of wheat have been fixed in the main wheat producing States, which are higher than that of last year. The procurement prices of wheat agreed to for the major wheat producing States are noted below :

Punjab and Haryana		
	(average of)	Rs. 70·75 per quintal.
Madhya Pradesh		Rs. 65-77 ,, ,,
Rajasthan		Rs. 77-85 ,, ,,
Uttar Pradesh		Rs. 80-85 ,, ,,

For Gram, procurement/purchase will be made in Rajasthan Haryana and Punjab by the Food Corporation of India at suitable prices.

Sugarcane Price

1542. Shri Mohan Swarup :
Shri Mritunjaya Prasad :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the question of fixing the price of sugarcane per quintal for the ensuing crushing season of 1967-68 is under consideration; and

(b) if so, when the sugarcane price is likely to be fixed ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) : Government announced on the 2nd March, 1967 that the price of sugarcane for the season 1967-68 would be Rs. 5.68 per quintal linked to a recovery of 9.4 per cent or less with a permium for higher recovery. There have been representations for upward revision of this price. The matter is under consideration. A decision on these representaions will be taken soon.

Agricultural Research Centres

1543. Shri Mohan Swarup : Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Agricultural Research Centres working in the country at present;

(b) the steps being taken by his Ministry to ensure that the methods of cultivation evolved through research made there reach the farmers directly and as quickly as possible; and

(c) the contribution made by researches in making the cultivation more progressive ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) There are about 540 agricultural research centres in the country.

(b) In carrying the new agricultural technology developed at the research laboratories and experiment stations to the actual field, steps have been taken to

familiarise the extension workers and the farmers with the new methods and techniques, Scientists have associated themselves with the conduct of National Demonstrations which are being conducted throughout the country and through which the results of researches are being carried into the farmers, fields. Besides this, central research institutes and Agricultural Universities regularly organise "Farmers Day" and conduct short courses of training for the farmers. This programme is proving very effective.

(c) Indian Scientists have made outstanding contributions to crop production in the country especially in recent years. The development of high yielding hybrids of maize, jowar and bajra and dwarf. non-lodging varieties of wheat and rice are playing a dominant role in the country. It has now become possible to launch the High Yielding Varieties Programme, for achieving self-sufficiency, only with the advent of these new varieties and hybrids which have been the key factor in making our cultivators, and the cultivation, more progressive.

गिर के बब्बर शेर

*1544. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गिर के जंगलों में बब्बर शेरों की संख्या, जो विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण हैं, तेजी से कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गिर के बब्बर शेरों की संख्या बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) जी नहीं। यह कहना ठीक नहीं है कि गिर के बब्बर शेरों की संख्या में तेजी से कमी होती जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) गुजरात सरकार ने इस विषय में निम्न कदम उठाये हैं :—

(1) 18-9-1965 से गिर जंगलों का लगभग 1,26,501 हैक्टेयर (3,12,459.11 एकड़) क्षेत्र वन्य पशु आश्रयस्थल हैं।

(3) इस क्षेत्र में समस्त प्रकार का आखेट खेलना मना है।

(3) कभी कभी स्थानीय पशुपालक (जिनके पशुओं को शेर खा जाते हैं) शेरों को विष देने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने उन पशुपालकों को मुआवजा देने की व्यवस्था की है जिसके पशु शेरों द्वारा मार दिये जाते हैं।

गिरनार में रज्जुपथ

1545. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिरनार, जूनागढ़ में एक रज्जूपथ बनाने की कोई योजना सरकार को पेश की ाई थी;

(ख) यदि सरकार आवश्यक विदेशी मुद्रा मंजूर कर दे तो क्या कोई गैर-सरकार एजेन्सी इस परियोजना का समस्त व्यय वहन करने के लिए सहमत हो गई; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : हाल ही में कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन, गिरनार में स्थापित किए जाने के लिए रज्जुपथ मशीनरी के आयात के लिए आयात लाइसेंस जारी करने में उनकी सहायता के उद्देश्य से पोरबंदर के श्री नानजी कालीदास का एक आवेदन जून, 1962 में गुजरात सरकार के जरिये प्राप्त हुआ था।

(ग) चूंकि इस योजना पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि 12 लाख रुपये होती थी, इसलिये आयात लाईसेंस जारी करने के लिए श्री नानजी कालीदास के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया।

मूल अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

1546. **श्री स० मो० बनर्जी ;** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री ना० स्व० शर्मा : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री रामसिंह आयरवाल : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री शारदा नन्द : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बृज भूषण लाल : **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या विधि मन्त्री 21 मार्च 1967 के तारांकित प्रश्न संख्यांक 27 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री य० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय के निर्णय की विवधाओं पर अभी भी सरकार सक्रियरूपेण विचार कर रही है।

रूसी ट्रैक्टर के ऊंचे मूल्य

1547. श्री स० मो० बनर्जी : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये : **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी ट्रैक्टरों की ऊंचे मूल्यों पर सप्लाई करने के बारे में इण्डियन इंजीनियरिंग कमर्शियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निगम के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार ने कोई शिकायत की है; और ?

(ग) यदि हां, तो इन आरोपों के बारे में जांच करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : कुछ शिकायतें मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई हैं।

(ग) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन मामले की जांच कर रही है।

राजस्थान में बाजरा तथा ज्वार की किस्मों का विकास

***1548. डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजरा और ज्वार की किस्मों का, जिनकी खेती राजस्थान के खारे पानी वाले क्षेत्रों में भी होती है, विकास करने के निमित्त अनुसंधान करने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की क्रियान्विति कब तक हो जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ज्वार व बाजरे की उन किस्मों का, जिनकी खेती राजस्थान के खारे पानी वाले क्षेत्रों में भी होती है, अनुसन्धान करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेण्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर

1549. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीयूट, जोधपुर का विचार खारे पानी को पेय बनाने के लिए एक नया यूनिट स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वह यूनिट कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यह यूनिट किन क्षेत्रों में काम करेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यटक केन्द्रों के बारे में वृत्त चित्र

1550. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर, जैसलमेर और कोटा को पर्यटक केन्द्रों के रूप लोकप्रिय बनाने के लिए इन ऐतिहासिक नगरों के बारे में वृत-चित्र बनाने के सरकार के कोई प्रस्ताव हैं, जैसा कि जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर के मामले में किया गया है; और

(ख) इन क्षेत्रों में, जहां पर्यटकों के आकर्षण की बहुत सी चीजें हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । फिलहाल नहीं । हमारे साधन, देश में पर्यटक रुचि के प्रत्येक स्थान के बारे में वृत-चित्र बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ।

(ख) राजस्थान में पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए पर्यटन सम्बन्धी चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के भाग II के अन्तर्गत 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । इन योजनाओं पर होने वाला व्यय केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जायेगा । योजना की पूरी ब्यौरेवार तफसील की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है ।

Seizure of Sugar Bags in Delhi

1551. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Police seized 180 bags of Uttar Pradesh sugar worth Rs. 55,000 alongwith a truck in Naya Bazar, Delhi on the 1st April, 1967;

(b) if so, the place from where sugar was brought; and

(c) the action taken by Government against the persons responsible therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Ghaziabad (U. P.)

(c) Two cases FIR Nos. 168 and 169 dated 1-4-1967 under Section 7 of Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) have been registered at the Lahori Gate Police Station. Three persons have been arrested in this connection so far. These cases are under investigation.

मुख्य/गौण मार्गों पर इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा वाइकाउंट विमानों का हटाया जाना

1552. **श्री मधु लिमये :** **श्री मनीभाई जे० पटेल :**
श्री स० मो० बनर्जी : **डा० राममनोहर लोहिया :**
श्री जार्ज फरनेंडीज :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्य/गौण मार्गों पर वाइकाउंट विमान हटाये जाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शंकर दल और लाल समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों में मतभेद है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार दोनों प्रतिवेदनों की प्रतियां सभा-पटल पर रखेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : यह प्रश्न कि क्या आई० ए० सी० के विमान बेड़े के वाइकाउंट विमानों को बदला जाना चाहिए और यदि हां, तो उनकी जगह पर किस किस्म के विमान रखे जाने चाहिएं, विचाराधीन है।

(ग) और (घ) कुछ किस्म के विमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आई० ए० सी० से विशेषज्ञों का एक दल विदेश गया था। आई० ए० सी० ने इन अधिकारियों की रिपोर्टों पर आधारित अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जिनकी एतद्विषयक अन्य सम्बद्ध सामग्री के साथ-साथ जांच की जा रही है।

Abolition of Post of Block Development Officers in Madhya Pradesh

1553. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 428 on the 4th April, 1967 regarding abolition of posts of Block Development Officers in Madhya Pradesh and state :

(a) whether Government have since gathered information if the decision taken by the Madhya Pradesh Government to abolish the posts of Block Development Officers has been fully implemented; and

(b) if so, the benefits accrued as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Government of Madhya Pradesh

have only recently issued detailed instructions regarding the alternative arrangements for the Block organisation, consequent on the abolition of the posts of Block Development Officers.

(b) It is still early to assess the benefits of the new system.

विदेशी पर्यटक

1554. श्री बलराज मधोक :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) उनके देशवार अलग अलग आंकड़े क्या हैं: और

(ग) इसी अवधि में विदेशी पर्यटकों के आने से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) आने वाले पर्यटकों की संख्या के आंकड़े कैलेण्डर वर्ष के आधार पर इकट्ठे किये जाते हैं कैलेण्डर वर्ष 1966 में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या 159,603 थी।

(ख) 1966 के देशवार राष्ट्रीकता आंकड़ों के बारे में एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) 1966 में विदेशी पर्यटकों के आने से हुई विदेशी मुद्रा की आय अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 533/67]**

रूस के कृषि विशेषज्ञ

1555. श्री दत्तात्रेय कुंटे : श्री स० चं० सामन्त :
श्री हु० प० चटर्जी : श्री यश पाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के कृषि विशेषज्ञों का पांच सदस्यों का एक दल मार्च, 1967 में उनसे मिला था और उसने उनके साथ भारत की कृषि समस्याओं के बारे में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो भारत को निकट भविष्य में खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन सदस्यों ने क्या सुझाव दिये थे; और

(ग) क्या इन्हें इस देश की यात्रा के लिए आमन्त्रित किया गया था अथवा क्या वे अपनी इच्छा से यहां आये थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, परन्तु दल मे 4 कृषि वैज्ञानिक शामिल थे।

(ख) दल ने कोई विशेष सुझाव नहीं दिए हैं। उन्होंने भारत में कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्र में होने वाले उस अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य का अध्ययन किया है जो कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर हो रहा है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों के साथ विचार-विमर्श भी किया है।

(ग) इस दल के दौरे का सम्बन्ध भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्री व रूस के कृषि मंत्री के बीच दोनों देशों के कृषि वैज्ञानिकों के आदान प्रदान के बारे में हुई बातचीत से है। यह बातचीत खाद्य तथा कृषि मन्त्री जी ने अपनी जुलाई 1966 की मास्को की यात्रा के समय की थी।

गोवध पर प्रतिबन्ध

1556. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 8 और 9 अप्रैल, 1967 को गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए उपयुक्त विधान बनाने के प्रश्न पर सम्बन्धित राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

उड़ीसा द्वारा केन्द्र को चावल की सप्लाई

1557. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा 1967-68 की अवधि में केन्द्र को 75,000 टन चावल सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) क्या उड़ीसा ने केन्द्र से गेहूँ मांगा है ;

(ग) यदि हां, तो कितना और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उड़ीसा और अधिक गेहूँ के बदले में कितना और चावल देने के लिये सहमत हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मिलों के कोटे को छोड़ कर उड़ीसा को प्रतिमास 10,500 टन गेहूँ की मांग है। मिलों के कोटे को छोड़ कर उनको अप्रैल में 3,000 टन, मई में 5,500 टन तथा जून में 6300 टन गेहूँ दिया गया था।

(घ) राज्य सरकार ने मात्रा नहीं बताई है।

उड़ीसा में पर्यटन विकास निगम के कार्यकलाप

1558. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विकास निगम ने उड़ीसा में अब तक पर्यटकों के लिये होटल आवास व्यवस्था तथा सड़क परिवहन की सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में किये गये इन कार्यों का ब्यौरा क्या है, इन सुविधाओं की व्यवस्था किन-किन स्थानों पर की गई हैं और इन पर अनुमानतः कितना खर्च आया है : और

(ग) वर्ष 1967-68 में इस निगम का उड़ीसा में क्या क्या कार्य करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी तक कारपोरेशन द्वारा कोई योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं। लेकिन राज्य सरकार और पर्यटन मन्त्रालय के चालू वर्ष के बजट में बहुत सी पर्यटन विकास योजनायें हैं।

उड़ीसा में कृषि विकास योजना

1559. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की 1966-67 की कृषि विकास योजना के लिए मंजूर की गई 10 करोड़ रुपये की राशि का पूर्ण उपयोग किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसमें से कितनी राशि खर्च होने की सूचना मिली है;

(ग) 1967-68 के लिए उड़ीसा की कृषि विकास योजनाओं के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(घ) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना के लिए कितनी-कितनी राशि नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : उड़ीसा में कृषि विकास योजनाओं के लिए 1966-67 के लिए 10

करोड़ रुपये का व्यय स्वीकार किया गया था। उसमें से सरकार ने 9·10 करोड़ रुपये व्यय किये हैं, अर्थात् 90 लाख रुपये कम।

(ग) और (घ) : अभी तक 1967–68 के लिए नियतन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

1560. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री प० ला० बारुपाल :

क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके स्थापित होने की कब तक सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : पारादीप पत्तन अप्रैल 1966 में बड़ा पत्तन घोषित किया गया था और नवम्बर 1966 में सागर-गामी यातायात के लिये खोल दिया गया था। पत्तन के प्रशासन के लिये एक संवैधानिक पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना का प्रश्न उसके बाद ही लिया जा सकता था। इस विषय पर मार्च में प्रस्ताव प्राप्त हुये थे और वे विचाराधीन हैं।

काली मिर्च का मूल्य

1561. श्री अब्राहम : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काली मिर्च के भाव गिरने के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) जनवरी, 1965 से मई, 1967 की अवधि के दौरान केरल के दो चुने हुए बाजारों में काली मिर्च के जो मासिक थोक मूल्य रहे उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखी या, देखिए संख्या एल० टी० 534/67**] उसको देखने से मालूम होगा कि अप्रैल से जुलाई 1966 के दौरान काली मिर्च के जो मूल्य बढ़ गए थे वे बाद में गिर गए। फरवरी, 1967 से मूल्य फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं और अब उतने ही हो गए हैं जितने 1965 तथा 1966 में थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Per capita supply of sugar to States

1562. Shri S. C. Samanta :
Shri A. K. Kisku :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri S. N. Maiti :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture**, be pleased to state :

(a) the per capita quantity of sugar supplied to each State; and

(b) the reasons for supplying at different scales and not supplying the same at a uniform per capita basis ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statement showing per capita availability of sugar to each State is attached. **[Placed in Library, See No. Lt. 535/67]**

(b) Consumption of sugar does not depend on population alone. It varies from area to area depending on the habits of the people, industrialisation, urbanisation and availability of other sweetening agents like gur and khandsari etc.

हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन

1563. श्री हेमराज :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न की कमी है और पिछले तीन वर्षों से वर्षा न होने के कारण फसलें नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसने केन्द्र से कितने खाद्यान्न की मांग की है; और

(ग) एक राज्य खाद्य खण्ड स्थापित होने के बाद अप्रैल, 1967 से लेकर मई, 1967 के अन्त तक केन्द्र ने उसे कितना खाद्यान्न दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) क्या कोई राज्य खाद्यान्नों की दृष्टि से अधिशेष अथवा कमी वाला राज्य है, यह निर्धारित करने के लिये कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। इसीलिये यह कहना कठिन है कि हिमाचल प्रदेश खाद्यान्नों की दृष्टि से कमी वाला प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में गत दो वर्षों में वर्षा कम हुई है और खाद्यान्नों की पैदावार 1964-65 में हुई पैदावार से कम है।

(ख) अप्रैल, 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र को प्रति मास 13,771 मीटरी टन खाद्यान्न देने के लिये कहा था।

(ग) हिमाचल प्रदेश को अप्रैल में भेजी गई आयातित गेहूँ की मात्रा 2,000 मीटरी टन से थोड़ी कम थी और मई में यह मात्रा 4,000 मीटरी टन थी। इसके अतिरिक्त पंजाब ने हिमाचल प्रदेश को देशी गेहूँ तथा चावल प्रत्येक की दो दो हजार मीटरी टन मात्रा सप्लाई करने की पेशकश की है।

विदेशी पर्यटकों के लिए चार्टर उड़ान

1564. श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री सी० दास :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों के लिए चार्टर उड़ानें लोकप्रिय बन गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इनके बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) भारत आने वाले पर्यटक दलों के 'डेस्टीनेशन चार्टरों' का परिचालन उन पर लगी हुई पाबन्दियों में छूट दी जाने के बाद 1966 के अन्त से प्रारम्भ हुआ। क्योंकि यह उनके परिचालन का पहला ही वर्ष है, अतः चार्टर उड़ानों को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनने में अभी समय लगेगा।

(ख) उन्हें बन्द नहीं किया गया है।

वर्षा की सम्भावनाएं

1565. श्री नीतिराजसिंह चौधरी : **श्री किकरसिंह** :
श्री स्वैल : **श्री बैरो** :
डा० कर्णीसिह : **श्री कोलाई बिरुआ** :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अमरीका विशेषज्ञों को भारत में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में पुनः इस वर्ष अर्थात् तीसरी बार सूखा पड़ने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ने की संभावना है, वहां पर खाद्यान्न और पानी की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों से जीपों का वापस लिया जाना

1566. श्री क० लकप्पा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्री लालबहादुर शास्त्री का राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों से जीपें वापस लेने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : 11-12-1964 को तीसरी लोकसभा में एक सदस्य द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर होने वाली बहस तथा बाद में 9-3-1965 को उस समय के सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्री की संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के फलस्वरूप सामुदायिक विकास खण्डों से जीपों को पूर्णतः वापिस ले लेने का प्रस्ताव रद्द कर

दिया गया था। उसके स्थान पर राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गये थे कि चुनावों की अवधि में, नामांकन की तारीख से मतदान की तारीख तक, जीपों को खण्डों से पूर्णतः वापिस ले लिया जाए और सामान्य काल में जीपों के उपयोग के लिए एक नियमावली तैयार की जाए। राज्य सरकारों ने इन सुझावों को कार्य रूप दे दिया है।

पश्चिम बंगाल में कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

1567. श्री समर गुह : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में आलू, सरसों के तेल, दालों आदि की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यह चीजें अन्य राज्यों से पश्चिम बंगाल में मंगवाई जाती हैं और कुछ थोक व्यापारियों ने इन वस्तुओं की कृत्रिम कमी कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार को अन्य राज्यों से खाद्य पदार्थ उचित मूल्यों पर प्राप्त कराने में केन्द्रीय सरकार का क्या सहायता करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कलकत्ता की मण्डियों में सरसों के तेल के थोक मूल्यों में अप्रैल 1967 से तथा दालों व आलू के थोक मूल्यों में फरवरी 1967 से वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) इन तीनों जिन्सों की समस्यायें भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। इस वर्ष पश्चिम बंगाल में आलू की अच्छी फसल हुई है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश व पंजाब में (जहां से बंगाल भी आलू प्राप्त करता है) भी आलू की अच्छी उपज हुई है। जहां तक सरसों का सम्बन्ध है, बंगाल देश के विभिन्न भागों से काफी बड़ी मात्रा में इस जिन्स को खरीदता है। बंगाल अपने मिलिंग उद्योग के माध्यम से अनेक राज्यों के सरसों के व्यापार पर नियन्त्रण स्थापित रखता है। सरसों के उत्पादन के केन्द्रों व मिलिंग व्यापार के विषय में मूल्य का सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है। पश्चिम बंगाल दालों को बड़े पैमाने पर आयात करता है। इस वर्ष दालों की फसल अच्छी नहीं थी। इस समय इन तीनों जिन्सों में से किसी पर भी कोई नियन्त्रण नहीं है। हां बिहार से आलू के बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध मौजूद हैं क्योंकि वहां सूखे के कारण स्थिति ठीक नहीं है।

कृषि ऋण निगम

1568. श्री रणधीरसिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा मनीपुर एवं त्रिपुरा के

संघ क्षेत्रों के राज्यों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने के लिए विधान बनाने का निर्णय किया गया है ।

(ख) और (ग) : विधान का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और संसद में यथासम्भव एक बिल पेश किया जायेगा ।

केरल के छोटे पत्तनों का विकास

1569. **श्री नायनारे** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं की अवधि में केरल में छोटे पत्तनों के विकास की कौन-कौन सी योजनायें मंजूर की गईं, और

(ख) तीनों योजनाओं की अवधियों में केरल में छोटे पत्तनों के विकास की योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि व्यय की ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं में मंजूर हुई योजनायें अनुबंध में की गई हैं । [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 536/67**]

(ख) केरल सरकार को केन्द्रीय सरकार ने निम्न राशियां ऋण रूप में दी हैं—

पहली योजना	2·16 लाख रु०
दूसरी योजना	7·65 लाख रु०
तीसरी योजना	70·44 लाख रु०

चीनी के कारखानों द्वारा किसानों को देय धन

1570. **श्री राने** : **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री मृत्युंजय प्रसाद** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ना उगाने वालों को चीनी के बहुत से कारखानों ने 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में सप्लाई गन्ने के मूल्य नहीं दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों के लिये राज्यवार कितनी राशि देनी शेष है; और

(ग) गन्ना उगाने वालों को उनके द्वारा चीनी के कारखानों को सप्लाई गन्ने का मूल्य तुरन्त मिले, इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 1966–67, 1965–66 तथा 1964–65 के सीजनों में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की राज्यवार स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 537–67**]

(ग) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे चीनी कारखानों से गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करवाने के लिये उचित कदम उठायें।

इम्फाल के लिए फॉकर फ्रेंडशिप विमान सेवा

1571. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इम्फाल तक फॉकर फ्रेंडशिप विमान सेवा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इम्फाल हवाई अड्डे का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) : इस समय इम्फाल (तुलिहाल) का धावन-पथ केवल डकोटा विमानों के परिचालनों के लिए उपयुक्त है और आई० ए० सी० एक दैनिक डी० सी०—3 विमान सेवा चला रही है। हवाई अड्डे का अधिक बड़े विमानों के परिचालनों के लिए विकास किया जा रहा है और जब वह विकास कार्य पूरा हो जायेगा तो इम्फाल के लिए फ्रेंडशिप विमानों से विमान-सेवा चलाने के प्रश्न की जांच की जायेगी।

नेहरू लोक

1572. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री यशपालसिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में चामुंडी पहाड़ी की तलहटी में 'नेहरू लोक' नामक भारतीय डिजनेलैंड बनाने पर सरकार 25 लाख रुपये खर्च करने की योजना बना रही है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के कितने 'नेहरू लोक' बनाने की योजना है तथा वे किन किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इन 'नेहरू लोकों' के लिए कुल कितने धन की व्यवस्था की गई है;

(घ) विभिन्न 'नेहरू लोकों' के निर्माण के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(ङ) इनसे देश में जनसाधारण को क्या लाभ होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मैसूर में चामुंडी पहाड़ी की तलहटी में, केवल एक 'नेहरू लीक' बनाने की योजना है। इसकी अनुमानित लागत 25 लाख रुपये है।

(घ) चूंकि अभी ब्यौरे तैयार नहीं किये गये हैं, इसलिए इस पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) वहां पर दी जाने वाली सुविधायें शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक दोनों ही प्रकृति की होंगी।

गायों पर प्रति जीवाणु पदार्थों का प्रयोग

1573. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री लखन लाल गुप्त :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री रामसिंह अयरवाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु चिकित्सा विभाग थनैली की बीमारी से पीड़ित गायों के इलाज में प्रतिजीवाणु पदार्थों का प्रयोग करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या पूर्व सावधानी बरती जा रही है कि जब तक ऐसी गायों के दूध में प्रतिजीवाणु पदार्थ अथवा उसका असर रहता है, उनके दूध को बाजार में न बेचा जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कनाडा सरकार द्वारा दिये गये दुग्ध पाउडर का मार्ग में गुम हो जाना

1574. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कनाडा सरकार की इस शिकायत की जांच की है कि उनके द्वारा बिहार की सहायता के लिये दिया गया दुग्ध पाउडर मार्ग में ही गुम हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या कनाडा के अधिकारी भी स्वतन्त्र रूप से इसकी जांच कर रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) दुग्धचूर्ण के गुम होने के सम्बन्ध में कनाडा के कुछ पत्रों में छपे आरोपों की जांच की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुये कि बहुत से मामलों में बंदरगाहों से अन्त: गन्तव्य स्थान तक सामानों के ले जाने में बहुत खिंचाव पड़ता है तो इस मामले में मार्ग में

कुछ नगण्य हानि का हो जाना कोई असाधारण बात नहीं है। तथापि, मार्ग में हुई इस हानि का राज्य सरकार से पूर्ण विवरण मालूम किया जा रहा है।

(ग) सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

चीनी का निर्यात

1575. श्री कं० हाल्दर :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष चीनी का कम निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने चीनी के निर्यातकों को 20 करोड़ रुपये की सहायता दी है और 17·5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई है; और

(ग) इस वर्ष कितनी चीनी का निर्यात किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ग) जी हां। 1967 में चीनी का निर्यात, 1966 के 4.41 लाख मीटरी टन के मुकाबले में, लगभग 2.20 लाख मीटरी टन होगा।

(ख) 1966–67 के वित्तीय वर्ष में 1966 में निर्यात की गई 4·41 लाख मीटरी टन चीनी पर हुई हानि को पूरा करने के लिए 20 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। इन निर्यातों से लगभग 18 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

उड़ीसा में उद्यान-विज्ञान का विकास

1576. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 के दौरान राज्य उद्यान–विज्ञान के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को कोई सहायता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 1967–68 में उद्यान–विज्ञान के विकास के लिए 69.42 लाख रुपये की व्यवस्था की है। कार्यक्रम के लिये प्रस्तावित खर्च के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता किसी विशेष योजना के लिए स्वीकृत नहीं जाती बल्कि विकास के मुख्य शीर्षकों के लिए स्वीकृत की जाती है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि उद्यान–विज्ञान की योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है।

उड़ीसा में गन्ने की खेती

1577. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को राज्य में गन्ने की खेती का विकास करने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) जी हां।

(ख) राज्यों की गन्ना विकास योजनायें "कृषि उत्पादन" शीर्षक के अन्दर आती हैं जिसके लिए 1966–67 में उड़ीसा की राज्य सरकार को 72.31 लाख रुपये (3.97 लाख रुपये उधार तथा 68.34 लाख रुपये अनुदान के रूप में) की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई थी।

उड़ीसा को पशु पालन के लिए केन्द्रीय सहायता

1578. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा, राजस्थान तथा उ० प्र० को अलग अलग, इन राज्यों में (एक) पशुपालन (दो) डेरी तथा दुग्ध सप्लाई और (तीन) मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए वास्तव में कितना धन दिया; और

(ख) उक्त अवधि में इन राज्यों में उपरोक्त योजनाओं पर अब तक वास्तव में कितना धन खर्च किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) प्रत्येक विकास शीर्षक के लिए होने वाले प्रत्याशित व्यय के विषय में जानकारी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है और स्वीकृति भी विकास शीर्षकों के अनुसार दी जाती है। पशुपालन, डेरी उद्योग, दुग्ध संभरण कार्यक्रम एक ही विकास शीर्षक के अन्तर्गत आते हैं, अतः अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय वित्तीय सहायता पहली 3 तिमाहियों के वास्तविक व्यय के विभागीय आंकड़ों के आधार व प्रत्याशित व्यय चौथी तिमाही के आधार पर स्वीकार की जाती है। वास्तविक व्यय के अन्तिम आंकड़े केन्द्रीय सहायता के समंजन के बारे में लेखा परीक्षा के अन्तिम आंकड़ों की प्राप्ति के बाद

ही जाने जा सकेंगे। 1966–67 के लिए स्वीकृत केन्द्रीय सहायता तथा 1966–67 के प्रत्याशित व्यय के उपलब्ध आंकड़े निम्न प्रकार है;–

(आंकड़े लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1966–67 के लिए स्वीकृत हुई केन्द्रीय सहायता		राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1966–67 के लिए प्रत्याशित व्यय	
	पशुपालन, डेरी तथा दुग्ध सम्भरण	मत्स्यापालन	पशुपालन, डेरी तथा दुग्ध सम्भरण	मत्स्यापालन
उड़ीसा	55.59	10.32	88.71	52.00
राजस्थान	46.98	1.38	98.84	11.75
उत्तर प्रदेश	105.09	4.29	203.04	24.93

राज्यों में भाण्डागार

1579. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस समय कितने भण्डागार हैं;

(ख) वे किन-किन स्थानों पर हैं: और

(ग) वर्ष 1967–68 में वहां कितने भाण्डागार खोलने का विचार है और उन्हें कहाँ-कहां बनाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिण्डे) : (क) उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य भांडागार निगमों के निम्नलिखित भाण्डागार हैं :

राज्य	केन्द्र	राज्य	कुल
उड़ीसा	6	13	19
राजस्थान	3	33	36
उत्तर प्रदेश	3	59	62

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य भाण्डागार निगमों के भाण्डागारों के स्थान संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल. टी. 538/67]

(ग) 1967–68 में उड़ीसा में तीन तथा उत्तर प्रदेश में आठ भाण्डागार खोलने का प्रस्ताव है। इस वर्ष के दौरान राजस्थान में कोई भाण्डागार खोलने की सम्भावना नहीं है।

निम्नलिखित केन्द्रों में भाण्डागार स्थापित किये जायेंगे:-

खोले जाने वाले भाण्डागार

राज्य	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	राज्य भाण्डागार निगम
		संख्या
उड़ीसा	--	1 वीराप्रानाप्पुर
		1 रामपुर
		1 तीमापारा
उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर (एक)	1 तातेरी (मेरठ)
		1 सरधना (मेरठ)
		1 बगारायन (उन्नाव)
		1 कायमगंज (फरुखाबाद)
		1 सिंदोती (सीतापुर)
		1 कलभाभो (हरदोई)

उड़ीसा में कृषि अनुसंधान परियोजनाएं

1580. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों में इस समय कितनी कृषि अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं, और

(ख) वर्ष 1966-67 में अब तक इन परियोजनाओं पर कुल कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के लिए उड़ीसा को अनुदान

1581. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के लिए उड़ीसा और राजस्थान को वास्तव में कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) 1967–68 में इस प्रयोजन के लिए इन राज्यों को कितनी राशि देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्यों को 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान के लिए निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है : विकास शीर्षक (1) कृषि उत्पादन (भूमि विकास सहित) तथा (2) लघु सिंचाई। उड़ीसा तथा राजस्थान सरकारों के लिए 1966–67 की अवधि के वास्ते उपरोक्त विकास शीर्षकों के अन्तर्गत योजनाओं की क्रियान्वित हेतु 95.49 लाख तथा 125. 18 लाख रुपये का अनुदान स्वीकार किया गया है।

(ख) अभी तक 1967–68 के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम

1582. श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम के लिए विदेशी मुद्रा का नियतन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है और किस उद्देश्य के लिये इसका नियतन किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिह) : (क) और (ख) 1967–68 के के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के लिए 38 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का नियतन किया गया है। नियतन के औपचारिक आदेश सरकार द्वारा तद्विषयक प्रस्ताव के स्वीकार किये जा चुकने के बाद जारी किये जायेंगे। इसका निम्न प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है:–

1. सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत बनाये जाने वाले होटलों के निर्माण के लिए आवश्यक वातानुकूलन यूनिटें, किचनतथा लौंड्री उपस्कर, लिफ्ट, इत्यादि जैसे विदेशी उपकरण (कम्पोनेण्ट्स)	20 लाख रुपये
2. पर्यटन साहित्य का उत्पादन-आर्ट कागज, फिल्मों, फोटो उपस्कर का आयात, पिक्चर पोस्टकार्डों की छपाई	8 लाख रुपये
3. सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटक परिवहन का परिचालन-वातानुकूलन यूनिटों का आयात	4 लाख रुपये
4. 'सान-एट्-लूमिअर' प्रदर्शनों का आयोजन–दो प्रदर्शनों के लिए उपस्कर का आयात	6 लाख रुपये
योग :	38 लाख रुपये

फलों के बागों की भूमि

1583. **श्री राने :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त भारत में कुल कितनी भूमि में फलों के बाग हैं; और

(ख) फलों का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) विभिन्न फल-फसलों के बारें में कोई नियमित अखिल भारतीय अनुमान तैयार नहीं किये जाते। फिर भी 1963–64 वर्ष के नवीनतम भूमि उपयोगिता के अनुसार 1305 हजार हैक्टेयर्स भूमि में फल फसलें उगाई गई थीं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र और केला, पपैया तथा काजू के उत्पादन सम्वन्धी तदर्थ वार्षिक अनुमान राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं। इन तीनों फलों के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना 1964–65 वर्ष के लिए है। यह निम्न प्रकार है:–

	क्षेत्र (हैक्टेयर्स हजारों में)	उत्पादन (टोन्ज हजारों में)
1. केला	195	2670
2. पपैया	7	240
3'. काजू	157	142

लक्कदीव में धान की खेती

1584. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लक्कदीव में धान की खेती के बारे में प्रयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा किसानों को इस बारे में क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) अभी सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान को चीनी तथा गेहूं की सप्लाई

1585. **श्री घुलेश्वर मीना :** **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में राजस्थान के लिए गेहूं और चीनी की कितनी मात्रा का नियतन किया गया तथा वास्तव में कितनी मात्रा दी गई, और

(ख) 1967–68 के पहले तीन महीनों के लिए राजस्थान को कितने गेहूं और चीनी का नियतन किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राजस्थान को 1966–67 (अप्रैल-मार्च) में, आयातित गेहूं और चीनी की आवंटित तथा वास्तव में भेजी या दी गई मात्रा इस प्रकार थीः–

(हजार मीटरी टन में)

	आवंटित मात्रा	भेजी या दी गई मात्रा
गेहूं	355.0	352.8
चीनी	110.0	107.8

(ख) 1967–68 (अप्रैल-जून) की पहली तिमाही में, राजस्थान की आगे की संभावित मात्रा सहित आयातित गेहूं और चीनी की आवंटित मात्रा इस प्रकार हैः–

(हजार मीटरी टन में)

अनाज	आवंटन
गेहूं	71.5 मीटरी टन
चीनी	18.7 ,,

कृषि प्रधान शिक्षा

1586. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 4 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 480 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यकारी दल के निष्कर्ष इस बीच मिल चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कार्यकारी दल के निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः उनकी अन्तिम सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

1587. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार करने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है जिससे उस कारखाने की निर्माण क्षमता चार जहाज प्रतिवर्ष से बढ़ाकर छः जहाज प्रतिवर्ष की जा सके, और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव) : (क) जी नहीं। अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व उसमें और जाँच-पड़ताल करना जरूरी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सड़क बोर्ड

1588. श्री ख० प्रधानी : **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री 4 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 482 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय सड़क बोर्ड बनाने के प्रस्ताव के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां तो क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री **(डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) और (ख) : जी नहीं। मामला अभी भी विचाराधीन है।

ट्रैक्टरों का आयात

1589. श्री ख० प्रधानी : **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 4 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 489 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से शेष 8,000 ट्रैक्टरों का आयात करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) 8000 ट्रैक्टरों के आयात का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राथमिक क्रय-विक्रय समितियां

1590. श्री घुलेश्वर मीना **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका **श्री हीरजी भाई :**

क्या **खाद्य, तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में देश में कितनी प्राथमिक क्रय-विक्रय समितियाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उसका व्यौरा क्या है ?

खाद्य. कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) 36

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 539/67**]

जापान से चावल मिल मशीनों का आयात

1591. श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान से चावल मिल मशीनें आयात करने के क्या कारण हैं जबकि वे इस देश में उपलब्ध हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी मशीनों का आयात करने में सरकार को एक करोड़ और 65 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे आयात को बन्द करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जापान से आयात किये गये चावल मिलिंग के आधुनिक प्रकार के उपकरण इस समय देश में उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं । खरीदारी न्यूनतम दर पर की गई थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता

1592. श्री रा० कृ० सिंह :

श्रीमती शारदा मुकर्जी :

श्री य० अ० प्रसाद :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने बिहार की सहायता के लिये पर्याप्त राशि दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस सहायता की मात्रा कितनी है तथा वह सहायता किस तरीके से दी जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) "यूनीसेफ" द्वारा बिहार को दी गई सहायता इस प्रकार है:–

वस्तु	मात्रा/मूल्य	कैफियत
1. स्किम दुग्धचूर्ण	3019 मीटरी टन	
2. कार्न सोया दुग्ध	3445 ,,	
3. इनके बनाने के लिए कच्चा माल– (क) हैजे के 151 लाख टीके (ख) टी. ए. बी. के 66 लाख टीके		
4. दवाइयां तथा औषध निर्माण तत्व	मूल्य 2.57 लाख रुपये	
5. दवाइयां तथा खुराक सप्लीमेंट स्टेट्स	संख्या 1063	
6. मोटर गाड़ियां	,, 48	
7. मोटर साइकल	,, 327	
8. ड्रिलिंग उपकरण		
हालको टाइगर रिग्स	,, 2	
हालको माइनर रिग्स	,, 5	
क्लोरीनेटिंग युनिट	,, 5	
पानी विश्लेषण किट्स	,, 10	
हैन्ड पम्प पुर्जों सहित	,, 132	
9. मल्टी विटामिन की गोलियां, विटामिन 'ए' तथा 'डी' कैपसूल, बेबी फूड तथा होल दुग्ध चूर्ण आदि के रूप में दान	मूल्य 35.21 लाख रुपये ।	

उड़ीसा के असका में कोआपरेटिव शूगर मिल्स

1593. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा में कोआपरेटिव शूगर मिल्स, असका के बन्द होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है;

(ग) मिलों के बन्द हो जाने के खतरे के क्या कारण हैं; और

(घ) उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार असका कोआपरेटिव शूगर इण्डस्ट्रीज लि० के बन्द होने का खतरा नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Import of Russian Tractors

1594. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of DT. 14B Russian Tractors imported for agriculture in the country so far :

(b) the States to which such tractors were supplied and the number thereof, separately ;

(c) the number of tractors, which have gone out of order ; and

(d) the arrangements made by Government to make their parts available within the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 7106 DT-14B tractors were imported during the period from 1958 to 1966.

(b) The State-wise distribution of the tractors is not available. However, the region-wise distribution is as under :—

Rajasthan, Punjab, U. P., Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh	2460
Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Mysore and Goa.	2099
Andhra Pradesh, Assam, Orissa, West Bengal, Bihar, Tripura & Manipur	2160
Madras, Pondicherry & Kerala	387
	7106

(c) The exact number is not known ; besides, the number would not remain constant on account of some tractors being restored to working order and some others going out of order.

(d) (i) Spare parts equal to 15% of the c. i. f. value of tractors are required to be imported along with the tractors.

(ii) Ad-hoc licences are also given to the importers of tractors to meet the requirements of their customers.

(iii) Actual users' licences are also issued to the individual owners of tractors if the required parts are not available with the importers.

Requirement of Tractors

1595. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri C. C. Desai :
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of tractors imported into India during the last year country-wise;

(b) the number of tractors required to be manufactured indigenously every year to fulfil the requirements of the country ;and

(c) the steps taken to manufacture tractors in the country with a view to achieve self-sufficiency ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

(b) The requirement of agricultural tractors during the remaining four years of the 4th Five Year Plan period is estimated as follows :

1967–68	...	25,000 Nos
1968–69	...	30,000 ,,
1969–70	...	35,000 ,,
1970–71	...	40,000 ,,

(c) The total licensed capacity is 30,000 tractors per year. To enable the existing manufacturing units to maximise production of tractors, the industry has been included in the list of priority industries and foreign exchange to the full extent of the current manufacturing capacity of the units has been allocated. A proposal to establish a public sector project with an annual capacity of 12,000 tractors is under consideration.

दिल्ली-शिवपुरी नेशनल पार्क विमान सेवा

1596. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई प्रार्थना की है कि पर्यटक यातायात बढ़ाने के लिए बरास्ता ग्वालियर दिल्ली से शिवपुरी नेशनल पार्क के लिए सप्ताह में दो बार एक विमान सेवा आरम्भ की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) ग्वालियर से होकर दिल्ली से शिवपुरी नेशनल पार्क को सप्ताह में दो बार की विमान-सेवा चालू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार को कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु उक्त राज्य सरकार की ओर से जबलपुर से होकर काहना नेशनल पार्क के लिये एक विमान-सेवा परिचालित करने के लिये प्रस्ताव अवश्य प्राप्त हुआ है, तथा आई० ए० सी० द्वारा इस सम्बन्ध में यातायात की सम्भावनाओं का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

फसलों को क्षति

1598. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च और अप्रैल 1967 में हुई भारी और असामयिक वर्षा के परिणाम स्वरूप समस्त उत्तर भारत में फसलों को बड़ी क्षति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो भारी और असामयिक वर्षा के परिणामस्वरूप फसलों को कितनी क्षति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि मार्च तथा अप्रैल, 1967 में असामयिक तथा अधिक वर्षा के कारण समस्त उत्तरी भारत में भारी नुकसान हुआ। केवल पंजाब, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सरकारों से आंशिक हानि की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों की रिपोर्टों के अनुसार नुकसान का अनुमान निम्न प्रकार है:—

पंजाब : कुल नुकसान का अनुमाम रुपए 69,29,817

राजस्थान : 1,50,000 मीटरी टन का नुकसान हुआ है।

उत्तर प्रदेश : 13 मार्च से 20 मार्च तक ओलों से 264,141 से भी अधिक एकड़ भूमि के क्षेत्र को हानि पहुँची तथा 22 से 31 मार्च 1967 तक की अवधि में 1,84,834 एकड़ भूमि के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा।

Growth of Hybrid Oilseeds

1599 Shri **Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture be** pleased to state:

(a) whether Government have made any attempt to grow hybrid oilseeds on the lines of hybrid sorgham (Bajra) and hybrid maize;

(b) if so, the result thereof;

(c) whether any high-yielding variety of oilseeds has also been evolved;

(d) whether Government have made experiments to grow foreign oilseed crops such as Soyabeen, Surajmukhi, etc. which are not ordinarily grown in India; and

(e) if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes. This is being done in the case of caster on an experimental basis.

(b) Among the major oilseed crops, caster is satisfactory from the point of view of economic large scale production of hybrid seeds-an important point which is to be taken into consideration for exploitation of hybrid vigour.

The Central Government through the Indian Council of Agricultural Research and the former Indian Central Oilseeds Committee have sponsored research projects specifically for the development of hybrid castor in the States of Madras, Uttar Pradesh and Mysore since 1959. Besides, Departments of Agriculture, Central Institutions like the I. A. R. I. are also engaged in this work. As a result of these research activities promising hybrids have been developed. For instance, in Madras, hybrids between locally improved varieties and Russian types have yielded 14 to 29% more seeds than the parents. The yields range between 1000 to 1300 kgs. per hectare.

Similarly in the Uttar Pradesh hybrid combinations that yield 1400 to 2000 kgs. per hectare have been evolved. To facilitate eeonomic large scale production of hybrid seeds, plant types tyat are 100 ./· 'pistillate' (all female flowers) have been evolved by the Regional Research Centre of the I. A. R. I. at Hyderabad and also by other State departmental laboratories, This finding will render the cheap production of hybrid seeds possible and it is hoped that large scale cultivation of hybrid castor will be made feasible in the near future.

Researches for the production of hybrid seeds in linseed are also in progress.

In the case of rape seed synthetic varieties comparable to the composites in maize are being develiped at the I. A. R. I. In a restricted sense these also would constitute 'hybrid' seeds.

(c) Yes. Several high yielding varieties of different oilseed crops have been evolved by the scientists working in Central and State Departments of Agriculture. So far there are about 43 improved varieties of groundnut, 27 of linseed, 21 of Castor, 17 of Sesamum, 25 of rape seed and mustard, 3 each of safflower and niger. These improved varieties are in great demand with the cultivators.

(d) and (e) : Experiments have been in progress to grow sunflower and soyabean in India and attempts have been made to introduce varieties from foreign countries through the Plant Introduction Division of the I. A. R. I.

In the case of soyabean, certain improved varieties have been recommended for cultivation in the plains and the hills. Recently a Coordinated Project bas been sanctioned for undertaking researches on soyabean at different centres in the country. With regard to sunflower, the stage of commercial cultivation has not yet been reached.

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिये मकान

1600. **श्री मङ्गलाथुमाडोम श्री विश्वम्भरन :**
श्री श्रीधरण : श्री कामेश्वर सिंह :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को रिहायशी मकान देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना कब चालू हो जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख), इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों की व्यवस्था करने की योजना है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इस प्रयोजन के लिए भूमि पहले से ली जा चुकी है और क्वार्टरों के निर्माण की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। कलकत्ता में 56 क्वार्टरों का निर्माण-कार्य पहले ही आरम्भ हो गया है।

दिल्ली में रामकृष्णपुरम् के दक्षिण में स्थित अविकसित भूमि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 24-5-67 को सौंप दी गयी। इस प्रयोजन के लिए प्लान तैयार की जा रही है।

कृषि संस्थायें

1601. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कृषि संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थानों का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) तथा राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल (हरियाणा) को राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इनमें से प्रत्येक संस्थान को अधिक स्वायत्त मान्यता देने व अधिक प्रशासनीय व वित्तीय अधिकार देने का प्रस्ताव है और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली समन्वय परिषद् के रूप में कार्य करेगी।

बिहार को उपहार में दिया गया खराब दुग्ध पाउडर

1602. **श्री काशीनाथ पाण्डे :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभावग्रस्त लोगों में वितरण के लिए बिहार सरकार को उपहार में दिया गया पांच प्रतिशत दुग्ध पाउडर खराब है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त भण्डार को हटा दिया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में **राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे)** : (क) और (ख) बिहार के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कोई भी खराब दुग्धचूर्ण मुफ्त वितरण के लिए नहीं भेजा गया है। तथापि, यह सम्भव है कि कुछ पात्र मार्ग में अथवा संचयन में खराब हो गये हों। राज्य सरकार को कहा गया है कि ऐसे पात्रों में पड़े दुग्धचूर्ण को रखा लिया जाय और प्रत्येक पात्र की सावधानी से जांच करने के बाद जब यह समझा जाय कि यह मनुष्य के खाने के योग्य है, तभी प्रयोग में लाया जाय।

आसाम में भारतीय खाद्य निगम का कार्य

1603. श्री एस्थोस : **श्री अनिरुधन :**
श्री उमानाथ : **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अब्राहम

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में भारतीय खाद्य निगम के काम की कोई जांच करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जांच के कब तक पूरा होने की आशा है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

स्वीडन द्वारा उर्वरक का दान

1604. श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :
श्री पार्थ सारथी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वीडन सरकार ने बिहार तथा उत्तर प्रदेश के अभावग्रस्त क्षेत्रों के प्रयोग के लिए 14,000 टन उर्वरक दान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके वितरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार प्रत्येक को 7000 टोन्ज अलाट किया गया है। इन राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अभावग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए आदेश जारी करें।

Shipping Corporation of India

1605. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Ram Chandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Heerji Bhai:
Shri K. Pradhani :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 814 on the 7th April, 1967 and state :

(a) the decision since taken by Government in connection with allocation of funds to the Shipping Corporation of India for the expansion of tonnage during the Fourth Plan period; and

(b) whether this amount would be utilised for the import of spare parts or the same would be manufactured indigenously ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) Proposals for the acquisition by the Shipping Corporation of India of 46 vessels aggregating 7 lakhs GRT at an estimated outlay of Rs. 146.8 crores during the Fourth Five-Year Plan period are under examination.

Part of this amount would be spent for the purchase of spare parts which are normally obtained along with the foreign vessels purchased. Spare parts for Indian vessels purchased would be obtained from the indigenous suppliers. The question of indigenous manufacture of spare parts for all the vessels purchased is proposed to be examined.

एपीजे शिपिंग लाइन्स

1606. श्री एस० एम० जोशी :
श्री मधु लिमये :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्मा से चावल के आयात के बारे में एपीजे शिपिंग कम्पनी द्वारा किये गये धोखाधड़ी के प्रयास के सम्बन्ध में खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा श्री एस० के० पाटिल को पेश किये गये टिप्पण की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उस अधिकारी ने श्री पाटिल को यह टिप्पण कब पेश किया था,

(ग) क्या यह टिप्पण प्राधिकृति टिप्पण था,

(घ) क्या यह टिप्पण उस अधिकारी ने दिया था, जिसने रंगून दूतावास द्वारा भेजी गई सूचना/पत्र के आधार पर "कार्यवाही" की थी,

(ङ) क्या टिप्पण देने के समय वह अधिकारी सरकारी नौकरी में था अथवा रिटायर हो गया था,

(च) यदि वह रिटायर हो चुका था, तो ये फाइलें उनको किसके द्वारा मिलीं और क्यों मिली, और

(छ) क्या सरकार इस टिप्पण की प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को यह मालूम नहीं है कि खाद्य मन्त्रालय के एक अधिकारी ने श्री एस० के० पाटिल को ऐसा कोई नोट प्रस्तुत किया है।

(ख) से (छ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज की सप्लाई

1607. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वर्तमान कठिन स्थितियों पर काबू पाने के लिये पी० एल० 480 के अन्तर्गत अतिरिक्त अनाज देने के बारे में अमरीका सरकार के साथ कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) संशोधित पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमेरिका से 20 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के आयात के लिये 20 फरवरी, 1967 को एक करार हुआ था। तब से दूसरा कोई करार अभी तक नहीं किया गया है।

(ख) 20 फरवरी, 1967 को हुये करार में 12 लाख मीटरी टन गेहूँ और 8 लाख मीटरी टन माइलो के आयात की व्यवस्था है।

Import of Tractors

1608. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri D. N. Patodia :
Shri C. C. Desai :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of small size Russian Tractors imported last year ;

(b) whether only one Company has been given the licence for their import ; and

(c) whether Government supervise the distribution work of this Company ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 1335 Russian DT-14B tractors were imported last year.

(b) Licences had been given to four Companies who are the Agents.

(c) These tractors are meant for agricultural purposes only. Where, however, a tractor is required for non-agricultural purposes, release is sanctioned on merits of the case. That the distribution of tractors in different regions is governed by the demand is ensured by fixing, for each agent, a quota considered reasonable and that agent is allowed to import only the specified number of tractors. The agents submit sales returns to the State Trading Corporation. General Supervision is exercised by that Corporation.

अण्डमान के मुख्य वन संरक्षक द्वारा की गई खरीद

1609. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री देवकी नन्दन पटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान के मुख्य वन संरक्षक ने हाल में जो रेलें, सवारी-डिब्बे, घिरनी आदि खरीदे हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या माल आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में खरीदा गया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) रेलों, बोगियों, पुले आदि के बारे में मुख्य वन संरक्षक अण्डेमान द्वारा हाल में कोई खरीददारी नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अण्डमान की इमारती लकड़ी की जहाज से ढुलाई

1610. श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री देवकी नन्दन पटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 25,000 टन से अधिक अण्डमान की इमारती लकड़ी भारत की मुख्य भूमि को भेजने के लिए जहाज उपलब्ध नहीं हुए हैं और वह पिछले कई महीनों से वहीं पड़ी हुई है और सरकार परिवहन की व्यवस्था नहीं कर सकी है जिसके फलस्वरूप इमारती लकड़ी खराब हो रही है और उसका अच्छा दाम नहीं मिलेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अण्डमान की इमारती लकड़ी (टिम्बर)

1611. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री देवकीनन्दन पटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान की इमारती लकड़ी की बिक्री की जिम्मेदारी हावड़ा और मद्रास टिम्बर डिपू पर है;

(ख) क्या इमारती लकड़ी की बिक्री से अण्डमान वन विभाग को कुछ लाभ हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) टिम्बर डिपुओं के खोलने के पश्चात प्रत्येक डिपू को, वर्ष-वार कुल कितनी हानि हुई; और

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बर्मा से चावल

1612. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम में पत्तन कर्मचारियों की हड़ताल तथा बर्मा से चावल का लदान जहाज में विलम्ब से होने के कारण सरकार मजबूर हो गई है कि कई राज्यों को उतना चावल न दे जितना उसने देने का वायदा किया था; और

(ख) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, अन्य राज्य तथा केरल ।

अविकसित क्षेत्रों में चीनी मिलें

1613. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का विचार चौथी योजना में अविकसित क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) चौथी योजना में महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, मद्रास, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और राजस्थान राज्यों में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में 20 नये चीनी कारखाने (18 सहकारी कारखाने) स्थापित करने के लिये पार्टियों को आशय पत्र/लाइसेंस जारी किये गये हैं। ये मिलें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी ।

मद्रास को दिये गये खाद्यान्न के लिए राज-सहायता

1614. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने खाद्यान्न के लिए राज–सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या किसी राज्य को खाद्यान्न के लिए राज–सहायता दी जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को अधिकांश खाद्यान्न उपदान दर पर अपने भण्डार से देती है। इस प्रकार केन्द्रीय उपदान निर्गम मूल्य में सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी राज्य को खाद्यान्नों पर अन्य कोई उपदान नहीं दिया जा रहा है ।

चीनी उद्योग विकास परिषद्

1615. श्री काशीनाथ पाण्डेय :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मई, 1967 को चीनी उद्योग विकास बैठक की परिषद् हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय किये गये थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) चीनी उद्योग की विकास परिषद् ने अपनी पिछली सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही की समीक्षा की, वार्षिक रिपोर्ट स्वीकृत की और चीनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के

लिये लाइसेंस देने की प्रगति देखी। परिषद् ने 1966-67 के लिये चीनी मानक भी स्वीकृत किये और परिषद् की सिफारिश पर चलायी गयी अनुसन्धान योजनाओं की प्रगति रिपोर्टों पर विचार किया।

परिषद् ने चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये उपायों पर भी चर्चा की। इन सुझावों में चीनी पर से पूरा या आंशिक नियन्त्रण उठाना, गुड़ और खंडसारी पर नियामक उपाय, चीनी और खंडसारी के बीच उत्पादन शुल्क में अन्तर दूर करना शामिल हैं। गन्ने के लिये उर्वरक का विशेष कोटा आवंटित करने का सुझाव दिया था बशर्ते कि जो किसान इस आवंटित कोटे से उर्वरक लेंमे वे कम से कम अपनी पैदावार का 75 प्रतिशत चीनी कारखानों को सप्लाई करें। जहां तक गन्ने के विकास का सम्बन्ध है, यह सुझाव दिया गया कि मिल मालिक ऐसी योजनाएं शुरू करें जिसके अन्तर्गत कारखाने, गन्ना उत्पादक और राज्य सरकार मिलकर विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की पैदावार और किस्म के मामले में ठोस परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करें।

आगरा–बम्बई राजपथ पर मोटल

1616. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर मोटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ये मोटल कहां-कहां बनाये जायेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की, जो कि सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत व्यवसाय है, आगरा-बम्बई सड़क पर मोटलों के बनाने की योजनाएं हैं। ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

D. M. S. Milk Depots beyond Jamuna

1617. Shri N. S. Sharma :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no milk depots of Delhi Milk Scheme in the area beyond Jamuna ;

(b) whether it is also a fact that there was a scheme to open milk depots in the area beyond Jamuna during 1965 ; and

(c) if so, the reasons for not opening these depots so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Delhi Milk Scheme is at present unable to extend service to the entire city due to limited procurement. Extension of services of the Scheme to new areas including areas across Jamuna can be taken up only if more milk is available.

कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों की उपरि-सीमा

1618. श्री अमरसे : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानूनी मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत किन कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों की उपरि-सीमा निर्धारित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

टूरिस्ट बसें

1619. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट और श्रीनगर के बीच चलाई जाने वाली टूरिस्ट बसों की तरह ही देश के अन्य पर्यटन केन्द्रों में भी टूरिस्ट बसें चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था किन-किन स्थानों में की जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उडड्यन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पठानकोट श्रीनगर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा पर्यटक बसों की व्यवस्था नहीं की जाती। इस मार्ग पर बसों की व्यवस्था जम्मू और काश्मीर सरकार एवं अन्य प्राधिकृत निजी (प्राइवेट) परिचालकों द्वारा की जाती है।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

1620. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के हेतु सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजनायें तैयार की हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उडड्यन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन संबंधी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में काश्मीर से दार्जिलिंग तक हिमालय प्रदेश में तथा नीलगिरि में चुने हुए क्षेत्रों का विकास सम्मिलित है। संबधित राज्य सरकारों से परामर्श करके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र में होटलों का निर्माण

1621. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू और मनाली जैसे स्थानों में होटल बनाने के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है : और

(ख) यदि हां, तो कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार की इस समय धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू और मनाली में होटल बनाने की कोई योजना नहीं है । लेकिन, कुल्लू में एक पर्यटक बंगला है और मनाली में एक पर्यटक बंगला खोलने के लिए प्रबन्ध पूरे हो चुके हैं ।

मनीपुर को खाद्यान्न की सहायता

1622. **श्री मेघचन्द्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर के संघ राज्यक्षेत्र को वर्ष 1967–68 के लिये वायदा किये गये खाद्यान्न की सप्लाई देना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) अब तक कितनी मात्रा में अनाज की सप्लाई की गई है;

(ग) मनीपुर को सप्लाई किये गये खाद्यान्न में कितना चावल है तथा कितना गेहूँ; और

(घ) क्या मनीपुर सरकार ने अनाज की उक्त सहायता बढ़ाने के लिए सरकार से पुनः प्रार्थना की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों तथा मणिपुर सहित सभी केन्द्र शासित प्रदेशों को दिये जाने वाले खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में ही सम्मिलित उपदान को छोड़कर न तो मणिपुर को अन्य उपदान के लिए वायदा किया गया है और न ही दिया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) जी नहीं ।

Loans taken by Cooperative Societies in Bihar.

1623. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the amount of loan taken by the Cooperative Societies in Bihar as compared to the other States during the year 1966–67 ;

(b) whether Government propose to give more funds as compared to the previous years through Cooperative Societies in view of the famine prevailing in Bihar ; and

(c) if so, the amount of loan being given by the Central Government to Co-operative Societies in Bihar for 1967-68 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde). : (a) For the cooperative year ending 30th June, 1967 the Reserve Bank of India sanctioned a short-term credit limit of Rs. 428 lakhs to the Bihar State Cooperative Bank on behalf of the central cooperative banks

for financing agricultural operations. The actual amount availed of and outstanding will be known after 30th June, 1967.

(b) and (c) Central Government do not provide any funds directly to cooperatives for disbursement as loans. The State Government has been advised to send the applications of the cooperative banks for credit limit for the cooperative year 1967-68 to the Reserve Bank taking into account the requirements of credit for agricultural production in respect of members of cooperatives. As regards the non-members, the State Government may provide taccavi loans for which partial reimbursement from the Central Government will be available. The Central Government has also given an assistance of Rs. 50 lakhs (Rs. 12.5 lakhs loan, Rs. 37.5 lakhs grant) to the State Government for strengthening the Agricultural Credit Stabilisation Fund of the Bihar State Cooperative Bank to enable cooperatives to convert overdue short-term loans of cultivators in areas of scarcity into medium-term loans so that the member-cultivators would become eligible for fresh finance in the coming season.

Development of Lakes in Bihar

1624. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether there are some lakes and beautiful spots of tourist importance in the Champaran District of Bihar ;

(b) if so, whether Government have made any survey for the development of these spots ;

(c) if so, the nature thereof ; and

(d) if not, the reasons for not taking any steps so far in this direction ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b): No survey has so far been made to assess the tourist potential of Champaran District in Bihar.

(c) Does not arise.

(d) There are a large number of places in the country which have the potential of being developed into tourist centres. In view of the limited resources, however, it is not possible to undertake the development or even survey of all these places at the same time, schemes for development of tourist places are selected on the basis of their immediate tourist appeal and in consultation with the State Governments.

पशुओं को टीके लगाने की दवा

1625. **श्री नाथूराम अहिरवार** :
श्री गं० चं० दीक्षित :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह
श्री भा० सुन्दरलाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पशुओं को पशुप्लेग के रोग से बचाने के हेतु एफ० डी० आर० डी० टीके की दवा (वैक्सीन) तैयार करने के लिए और अधिक मशीनें प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है तथा ये मशीनें कहाँ लगाई जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकारों की माँग को पूरा करने के लिए 5 नई फ्रीज ड्राइंग मशीनों को प्राप्त किया जा रहा है। 4.40 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा (जो वर्तमान मशीनों के फालतू पुर्जों के लिए भी होगी) दे दी गई है और संबंधित राज्य सरकारों को इस विषय में सूचना दे दी गई है।

आयात के पश्चात मशीनें निम्न वैक्सीन उत्पादक केन्द्रों में स्थापित की जायेंगी :-

(1) रानीपेट (मद्रास)
(2) लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
(3) महौ (मध्य प्रदेश)
(4) हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) तथा
(5) भुभनेश्वर (उड़ीसा)

Flying Hours Required for Pilot Licence

1626. Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri S. M. Joshi :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total 'flying hours' experience required for pilots holding commercial licence to enable them to be recognized as full-fledged pilots ;

(b) the number of years required to gain the experience of these flying hours ;

(c) whether Government propose to reduce the amount of grant being given to the pilots under training ; and

(d) if so, the extent of reduction and the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) There are three categories of professional pilot's licences, viz. Commercial Pilot's Licence, Senior Commercial Pilot's Licence and Airline Transport Pilot's Licence. Flying experience and other requirements for issue of these licences are contained in Sections D, E and F of Schedule II to the Aircraft Rules, 1937. For the highest category viz. the Airline Transport Pilot's Licence, an applicant has to produce evidence of having satisfactorily completed, as pilot of an aeroplane within a period of five years immediately preceding the date of application for licence, not less than 1,500 hours of flight time.

(c) No grant-in-aid is given by Central Government to the Pilots under training. However, trainees who are Matriculates and below 28 years of age, can do flying at the concessional rate of Rs. 10/- per hour at subsidised flying clubs upto 100 hours during the first year and 50 hours in each subsequent year, as against the non-subsidised rate of Rs. 75/- per hour. In the case of others i. e. non-Matriculates and those above 28 years of age, flying fees payable are Rs. 25/- per hour.

(d) At present it is not proposed to make any reduction in the quantum of flying admissible at subsidised rates.

मध्य प्रदेश में आर्थिक और अन्तर्राज्यिक महत्व की सड़कें

1627, **श्री नाथूराम अहिरवार :** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री गं० चं० दीक्षित : **श्री भा० सुन्दर लाल :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक और अन्तर्राज्यिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा वित्त की व्यवस्था किये जाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव भेजे गये हैं ।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बीच में वे प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं तथा वित्तीय मंजूरी दे दी गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्तावों के कब तक स्वीकार किये जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) चतुर्थ योजना आवंटन को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है ।

मध्य प्रदेश में सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना

1628. **श्री नाथूराम अहिरवार :** **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री गं० चं० दीक्षित : **श्री भा० सुन्दरलाल :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ ।

(ख) चतुर्थ योजना काल में मौजूदा राष्ट्रीय „मुख्यमार्ग स्कीम में जोड़े जाने के लिये प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय योजना आवंटन को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही लिया जा सकता है । इस बीच प्रस्तावों की परीक्षा करने के लिये, संबद्ध राज्य सरकारों से आवश्यक तकनीकी दित्ता भेजने के लिए कहा गया है ।

Expenditure on General Elections

1629. **Shri Rama Chandra Veerappa :** Will the Minister of Law be pleased to state the expenses incurred in the Mysore State during the First, Second, Third and Fourth General Elections ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : So far as the expenses incurred in the Mysore State during the First, Second and Third General Elections are concerned, these are mentioned in the respective Reports of the Election Commission on these General Elections. On page 202, Vol. I of the Report on the First General Elections in India 1951-52, it is stated inter alia that the overall expenditure of the elections incurred from 1948 till the completion of the elections in 1952 in relation to the State of Mysore was Rs. 24,11,079-15-6p.

The expenditure incurred in the Second General Elections of 1956-57 in relation to the State of Mysore excluding routine recurring expenditure on the annual revision of electoral rolls from 1953 onwards is stated on page 223 of Vol. I of the Report on the Second General Elections in India, 1957 as Rs. 34,59,625.

The expenditure incurred in relation to the State of Mysore in connection with the Third General Elections, including the preparation and printing of electoral rolls is stated on page 120 of Vol. I of the Report on the Third General Elections in India, 1962 as Rs. 45.36 lakhs.

The expenditure incurred in relation to Mysore in connection with the Fourth General Elections of 1967 has been stated by the Election Commis ion as Rs. 40,25,000

पर्यटक होटल

1630 श्री कामेश्वर सिंह : **श्री शिव पूजन शास्त्री :**
श्री श्रीधरन : **श्री ज० ब० सिंह :**
श्री निहाल सिंह : **श्री रामकिशन गुप्त :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने पर्यटक होटलों का निर्माण आरम्भ किया गया है;

(ख) चालू अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष में इनमें से कितने होटल बन कर तैयार हो जायेंगे; और

(ग) प्रत्येक होटल के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह): (क) पहले दौर में 8 होटलों का निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने का विचार है । दूसरे दौर में होटल-निर्माण के यथार्थ कार्य-क्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । इन होटलों का निर्माण भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा जो कि एक सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत व्यवसाय है ।

(ख) क्योंकि 8 होटलों का निर्माण 1968 के पिछले भाग में पूरा होना है, इसलिये उनमें से किसी की भी अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के दौरान, जो कि 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हो रहा है, पूरा होने की संभावना नहीं है ।

(ग) आठ होटलों के निर्माण-कार्य की प्रगति इस प्रकार है:-

सान्ताक्रुज और दमदम हवाई अड्डे : (2 होटल)

इन होटलों में से प्रत्येक के लिए 5 एकड़ का स्थान अलग कर दिया गया है तथा प्रारम्भिक प्लानों की जाँच की जा रही है ।

पानाजी (गोम्रा), कोवालम समुद्रतट (केरल) और बंगलौर (मैसूर) (3 होटल)

इन प्रायोजनाओं के लिए भूमि राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी है तथा प्रारम्भिक प्लानों की जाँच की जा रही है।

वाराणसी : (1 होटल)

इस प्रायोजना के लिए भूमि महाराजा बनारस द्वारा प्रस्तुत की गयी है तथा प्रारम्भिक प्लानों की जाँच की जा रही है ।

जुहू समुद्रतट : (1 होटल)

इस प्रायोजना के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में बातचीत चल रही है ।

श्रीनगर (काश्मीर) : (1 होटल)

इस होटल के लिए स्थान निर्धारण को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

मुजफ्फरपुर-भोवाड़ा विमान सेवा

1631. श्री शिवचन्द्र झा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुजफ्फरपुर और भोवाड़ा (मधुबनी के निकट) दोनों स्थानों पर हवाई अड्डे तो हैं परन्तु वहां नियमित विमान सेवा नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो नियमित विमान सेवा से इन दोनों स्थानों को मिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन पटना और मुजफ्फरपुर के बीच में दो बार की एक अनुसूचित विमान सेवा परिचालित कर रही है। भोवाड़ा की अच्छे मौसम की हवाई पट्टी फिलहाल विमान सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है ।

मध्य प्रदेश में फ्लाइंग क्लब

1632. श्री आत्म दास : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश में कुल कितने फ्लाइंग क्लब हैं;

(ख) 'ए' श्रेणी 'बी' श्रेणी तथा 'सी' श्रेणी के विमान चालकों के लिये कितने क्लब हैं; और

(ग) क्या सरकार मध्य प्रदेश में और अधिक फ्लाइंग क्लब खोलने का विचार कर रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मध्य प्रदेश में एक फ्लाइंग क्लब है, जिसका मुख्य कार्यालय इन्दौर में और शाखा भोपाल में है ।

(ख) न तो फ्लाइंग क्लबों का और न विमान चालकों का ही 'ए' श्रेणी, 'बी' श्रेणी, तथा 'सी' श्रेणी के रूप में वर्गीकरण किया जाता है ।

फ्लाइंग क्लब निम्न वर्गों की प्रशैक्षिणिक उड़ानों के लिए सहायता अनुदान ले सकते हैं:–

(i) विद्यार्थी विमान चालक के लाइसेंस और निजी विमान चालक के लाइसेंस को जारी करने तथा उनके नवीकरण के लिए उड़ान प्रशिक्षण :

(ii) सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित योजना के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए उड़ान प्रशिक्षण :

(iii) हांबी फ्लाइंग ।

(ग) फ्लाइंग क्लबें निजी (प्राइवेट) संस्थाएं हैं और या तो भारतीय कम्पनी अधिनियम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की जा सकती हैं । फ्लाइंग क्लब की स्थापना अधिकांशतः स्थानीय व्यक्तियों के उत्साह एवं उपक्रम-शीलता पर निर्भर करती है । जैसे ही कोई क्लब पात्रता निर्धारित शर्तों को पूरा कर लेता है, वैसे ही उसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सहायता अनुदान मंजूर कर दिया जाता है । केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी होने के लिए किसी क्लब को एक वर्ष में अनिवार्यतः न्यूनतम 800 घण्टों की प्रशैक्षणिक उड़ान कर लेनी होती है ।

खजुराहो में चन्द्रा होटल

1633. श्री नाथूराम अहिरवार : क्या परिवहन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खजूराहो (मध्य प्रदेश) में चन्द्रा होटल बनाने के लिए कितना धन मंजूर किया गया है ;

(ख) होटल का निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि विलम्ब के कोई कारण हैं; तो वे क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार का निकट भविष्य में खजुराहो में एक होटल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । भारत पर्यटन विकास निगम का, जोकि एक सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत व्यवसाय है, खजुराहो में एक पर्यटक बंगला है और पर्यटकों के हित के लिए राज्य सरकार का भी अपना पर्यटन बंगला है ।

कृषि शिक्षा

1634. श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० की० अमीन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि की उत्पादन शीलता को बढ़ाने की दृष्टि से कृषि शिक्षा की पद्धति तथा ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां । अनुसन्धान तथा शिक्षा की उत्पादनशीलता की पद्धति को चलाने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का उद्देश्य है ।

शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1964-66) में कृषि शिक्षा पर विभिन्न सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) कृषि विश्वविद्यालय जिनमें से आठ पहले ही खुल चुके हैं, के विशेष रूप संलग्न विवरण में दिए गए हैं। कृषि शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा आयोग (1964–66) की मुख्य सिफारिशें दूसरे विबरण में दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 540/67]**

तृतीय श्रेणी के गेहूं का आयात

1635 श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० की० अमीन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के गेहूं अथवा घुन लगे गेहूँ का जो जानवरों के खाने के उपयुक्त है आयात किया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) इस कार्य के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) यह सच है कि पी० एल० 480 के अधीन तृतीय श्रेणी के गेहूं की कुछ मात्रा का आयात देश में उस गेहूं की मानव उपभोग के उपयुक्त होने की जांच करने के बाद किया गया है । तथापि, यह कहना ठीक नहीं है कि तृतीय श्रेणी गेहूं घुना हुआ है और वह केवल पशुओं के खाने के उपयुक्त है । वस्तुतः भारत में आयातित तृतीय श्रेणी गेहूं की उपभोक्ता तरजीह पायी गयी थी ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

चने की दाल के अत्यधिक मूल्य

1636. श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० की० अमीन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966 में पंजाब द्वारा 54 रुपये से लेकर 58 रुपये प्रति क्विंटल तक की दर पर दी गई चने की दाल कमी वाले राज्यों में यथा गुजरात, महाराष्ट्र तथा मद्रास में क्रमशः 80 रुपये, 100 रुपये तथा 128 रुपये प्रति क्विंटल की बहुत ऊंची दर पर बेची गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो चने की दाल के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के ही इस प्रकार शोषण को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्यान्नों के मूल्य

1637. श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० की० अमीन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 के दौरान तथा 1967 के आरम्भ में देश के महत्वपूर्ण अत्यावश्यक भिन्न भिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्यों में कितना अन्तर था; और

(ख) दो समीपवर्ती राज्यों में जैसे (क) गुजरात और महाराष्ट्र (ख) गुजरात और राजस्थान (ग) पंजाब और दिल्ली (घ) राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इनके मूल्यों में कितना अन्तर है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) वर्ष 1966 में विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के बाज़ार भाव बताने वाला एक विवरण संलग्न है । (अनुबन्ध 1) **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल टी० 541/67]**

जनवरी से अप्रैल, 1967 में इन खाद्यान्नों के बाजार भाव बताने वाला एक अन्य विवरण संलग्न है । (अनुबन्ध 2) **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 541/67]**

(ख) वर्ष 1966 और 1967 के शुरू में विभिन्न राज्यों में जिनमें अधिकांश राज्यों के समीपवर्ती राज्य भी शामिल हैं, महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के भावों में घट-बढ़ अनुबन्ध 1 और 2 पर दिये गये विवरणों में दिखायी गयी है ।

मई, 1967 के महीने में समीपवर्ती राज्यों के ग्रुप में महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के भावों की तुलना बताने वाला एक विवरण (अनुबन्ध 3) संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 541/67]**

उड़ीसा में सूखे की स्थिति

1638. श्री अ० दीपा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कुछ जिलों में विशेषतया फूलबनी जिले के बोद्ध तथा फूलबनी सब-डिविजन में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति है; और

(ख) यदि हां, तो वहां की जनता के दुखों को दूर करने के लिये केन्द्रीय तथा उड़ीसा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जैसा कि सदन में 30-5-1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 829 के उत्तर में बताया गया है, 1966-67 में उड़ीसा में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1964-65 के उच्चतम उत्पादन से 14.1 प्रतिशत कम रहा है। 1966-67 में धान की फसलों की मध्यम और फोती किस्मों की पैदावार में बौध में 36 प्रतिशत और फूलबनी उप-डिवीजन में 29 प्रतिशत की कमी हुई थी।

(ख) उड़ीसा सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के संकट को दूर करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :–

(1) जिन क्षेत्रों में हानि 75 प्रतिशत से अधिक हुई है वहां भूराजस्व माफ कर दिया गया है और जिन क्षेत्रों में हानि 50 प्रतिशत से ज्यादा और 75 प्रतिशत से कम है वहां भूराजस्व की वसूली रोक दी गयी है।

(2) प्रभावित क्षेत्रों में टैस्ट सहायता कार्य शुरू किये गये हैं। 1966-67 में किये गये सभी अधूरे कार्यों को जारी रखा जा रहा है।

(3) बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त सहायता कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। जरूरतमन्द खेतिहरों को तकावी ऋण भी दिये जा रहे हैं।

(4) प्रभावित क्षेत्रों में कम गहरे तालाब तथा सतही कुओं आदि का निर्माण करने जैसी पीने के पानी की प्रायोजनाएं भी शुरू की गयी हैं।

Bridge over Ganga at Mirzapur.

1639. **Shri Ram Swarup :**
Shri V. N. Singh :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether a survey for the construction of a bridge over Ganga in Mirzapur District is being made by the Central Government and if so, where ; and

(b) the time by which the said survey is likely to be completed and the estimated expenditure involved ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir. This bridge, when constructed, would fall on a State road in Uttar Pradesh. The Government of Uttar Pradesh are, therefore, primarily concerned with all matters pertaining to this project.

(b) Does not arise.

राज्य सभा के एक सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार के बारे में

RE: MOTION OF PRIVILEGE AGAINST A MEMBER OF RAJYA SABHA

अध्यक्ष महोदय : मुझे विशेषाधिकार सम्बन्धी दो प्रस्ताव मिले हैं। यद्यपि मैंने उन्हें उठाने की अनुमति नहीं दी है, फिर भी मैं यहां उनका जिक्र करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में श्री सन्त बक्स सिंह ने एक प्रस्ताव की सूचना दी है तथा दूसरी सूचना डा० लोहिया और श्री रविराय द्वारा दी गई है। उक्त दोनों प्रस्ताव राज्यसभा में उस सदन के एक सदस्य द्वारा लोकसभा के सदस्य डा. लोहिया के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों से सम्बन्धित है। यह दुर्भाग्य की बात है कि संसद सदस्य परस्पर ऐसे निराधार आरोप लगायें। मैंने इस बारे में श्री जोशी और श्री रविराय के साथ विचार-विमर्श किया है। इस संसद तथा अन्य संसदों के प्रक्रिया के नियमों को देखने से यह मालूम होता है कि दोनों सभाएं समान रूप से प्रभुत्व सम्पन्न है, इसलिये हमारे लिये यह उचित नहीं है कि हम इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपे। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि राज्यसभा में लोकसभा के सदस्यों पर या लोकसभा में राज्यसभा के सदस्यों पर निराधार आरोप लगाना शोभनीय नहीं है। इस वजह से मैंने विशेषाधिकार के प्रस्तावों को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिये जाने की अनुमति नहीं दी है।

एक माननीय सदस्य : इसका और क्या उपाय हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आत्मसंयम इसके लिये सबसे अच्छा उपाय है।

श्री श्रीचंद गोयल (चंडीगढ़) : उन टिप्पणियों से सम्बन्धित इस सभा की भावनाओं को राज्य सभा के सभापति तक पहुँचा दिया जाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mine has been admitted.

अध्यक्ष महोदय : वह कल लिया जायेगा। अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मंहगाई भत्ता आयोग का प्रतिवेतन

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं मंहगाई भत्ता आयोग के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भविष्य में मंहगाई भत्ता दिये जाने के प्रश्न से सम्बन्धित प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये, संख्या एल० टी० 525/67]**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : गजेन्द्रगड़कर आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन 30 मई को दिया था। क्या सरकार ने इस बीच प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है। क्या सरकार प्रतिवेदन से सम्बन्धित अपनी सिफारिशें भी सभा पटल पर रखेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : इस प्रतिवेदन को छपवाने में समय लगा है। मैंने आज इसको सभा पटल पर इसलिये रखा है ताकि वह आपके पास शीघ्रातिशीघ्र पहुंच सके। चूंकि मंत्रियों को भी इस प्रतिवेदन की प्रतियां आज से पहले नहीं मिल सकी थी, इसलिये इस पर मंत्रि-मंडल कैसे विचार कर सकता था।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन की प्रतियां प्राप्त हो गई हैं और वे माननीय सदस्यों को बांट दी जायेंगी।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रतियों के बांटने मात्र से क्या लाभ होगा। सरकारी कर्मचारियों को पिछले एक वर्ष से धोखा दिया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार मंहगाई भत्ते के प्रश्न पर कब तक निर्णय करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है। सरकार इस सम्बन्ध में बाद में निर्णय करेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I request that the House should be informed and an opportunity should be given to the House to discuss this question while taking decision thereon.

श्री मोरारजी देसाई : कुछ दिन पहले यह चर्चा हुई थी कि सदस्यों को प्रतियां नहीं बांटी गई हैं। इसलिये मैंने यह प्रति सभा पटल पर रखी है।

बड़े पत्तन न्यास अधिनियम की धारा 103 के अधीन पत्र

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बम्बई पत्तन न्यास के 1965-66 के वार्षिक लेखे की एक प्रति, तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 521/67**]

नौसेना (अनुशासन तथा विविध उपबन्ध) (संशोधन) विनियम

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से, नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (अनुशासन तथा विविध उपबन्ध) (संशोधन) विनियम, 1967 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 22 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. 15/ई में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 522/67**]

विलायक-निस्सारित तेल (सौल्वेंट-एक्सट्रेक्टेड आयल) डि-आयल्ड मील तथा खाद्य आटा (नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री डा० एरिंग) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत विलायक-निस्सारित तेल (सौल्वेंट-एक्सट्रेक्टेड आयल), डी- आयल्ड मील तथा खाद्य आटा (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1967 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 12 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 536 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 523/67]**

अधिवक्ता अधिनियम समीक्षा समिति का प्रतिवेदन

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : मैं अधिवक्ता अधिनियम समीक्षा समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 524/67]**

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE-CALL ATTENTION NOTICES (QUERY)

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : हमने पश्चिमी एशिया की गतिविधियों की ओर ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी। हमें ऐसा पता चला है कि प्रधान मन्त्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगी। वे किस समय वक्तव्य देंगी ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : दोपहर बाद।

श्री प्र० के० देव : ठीक समय बताया जाये।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजी कोड) : मैंने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की एक सूचना दी थी, जिसका विषय गाजा में 5 भारतीय सिपाहियों का मारा जाना था।

श्री म० ला० सौंधी (नई दिल्ली) : मेरा यह सुझाव है कि मृत सैनिकों को दो मिनट के लिये मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। कोई अन्य सदस्य कोई दूसरा सुझाव देगा।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मेरे ध्यान दिलाने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रतिदिन 40–50 ध्यान दिलाने सम्बन्धी प्रस्तावों की सूचनाएं मिलती हैं। यदि प्रत्येक सूचना देने वाला सदस्य इस प्रकार उठकर अपनी अपनी सूचना के बारे में पूछेगा, तो सभा में कार्यवाही का आगे बढ़ना मुश्किल हो जायेगा। यदि श्री सेट अपने प्रस्ताव के बारे में गम्भीर हैं तो वह मेरे कक्ष में आकर इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सकते हैं। यदि मामला वास्तव में महत्वपूर्ण होगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

सामान्य आय व्ययक 1967–68 सामान्य चर्चा–जारी

GENBRAL BUDGET 1967–68 GENERAL DISCUSSION (CONTD)

Shri Hardyal Devgun (East Delhi) : Budget proposals do not fufil the aims which have been detailed in the budget speech. It is essential for the development and advancement of the country that there should be a plenty of eatables and essential commodities, sound economy and strong defence arrangements.

In the begining of his budget speech the Finance Minister has drawn the attention of the House towards the drought and the difficult food situation. But I am sorry to say that the agriculture has not been given as much attention as it requires, in order to step up the agricultural production and to get rid of the starvation. Unfortunately the Govt. have withdrawn the subsidy worth Rs. 50 crores, which was being given in respect of fertilizers. No arrangements have been made for providing tractors on hire-purchase basis or seeds of better qualities to farmers. No steps have been taken to start small irrigation projects to face the drought in future. The Govt. have failed to adopt the new agricaltural strategy in view of the present food situation.

{ **श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए**
Shri Bal Raj Madhok *in the Chair* }

The Minister has referred to the rising prices of all the commodities. He said that there has been 46 ./· rise during last 3 years. But the prices of foodgrains only have gone up by 119 percent during that period. Nothing has been done to check the rising prices, on the contrary excise duty on certain items has been increased ; which will help the prices to rise further instead of falling down. If the Minister is serious about restricting the rising trend in prices, he has to withdraw this additional burden of excise duties. Here I would like to emphasize that if Govt. can stop the evasion of some taxes like income-tax and custom and excise duties etc.. they need not impose new taxes every year. If the amount of taxes is realized, they will yield a sum of Rs. 5500 crores, while last year it was Rs. 2700 crores. It is possible only if the tax collecting machinery is honest and industricus. It has been proved so in an experiment conducted by Municipal Corporation of Delhi, which is in the hands of Jan Sangh party. If the excise duty is reduced there will be some relief in the prices of vegitable oil, cloth, match box, Kerosene oil etc., which are the commodities of daily use for two masses.

It hes been stated that the public expenditure would be reduced to the minimum. But practically Govt. do not intend to do so. They invested Rs. 1400 crores in Public Sector Undertakings during last two years. This huge amount returned only 1/2 per cent dividend ; which is for less than the rate of interest which this amount has otherwise earned. Unproductive expenditure is on increase even now. Though they boast for not having resorted to deficit financing, yet the measures they have taken would surely result in inflaction. If they want, the public expenditure can be reduced without resorting the retrenchment. I think, there is no need of having 53 members in the council of Minister at the Centre.

The Government is financing so many institution just to accomodate congressman who could not be absorbed in the Central or State Ministries. There is no need of these institutions in the present state of economy of our country.

The expenditure of all the Government departments is extravagant. There would have been no need of additional taxation had ten percent economy have affected. It can be done easily and it would have checked inflatory tendencies. The Community Development Organisation is nothing except an election machinery of the Government. There is no need of the Planning Commission as well. Government should run the Public Sector Undertakings and projects more efficiently. It is quite clear that corruption, dis-honesty and inefficiency prevails in the Government departments because these projects have earned only two percent profit. If the departments Like Public Works Departments are cleared of the corruption the durability of the roads and buildings constructed by this department. Import of the movie films from abroad should be stopped. This will save lot of foreign exchange.

It is not correct to think that by increasing the excise duty on tea and coffee their internal consumption can be reduced. Therefore the increase in excise duty of these two commodities of daily use is unjustified and should be removed.

श्री राणे (बुलडाना) : मैं उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वित्त मन्त्री बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने यह बजट प्रस्तुत कर घाटे की अर्थव्यवस्था की प्रथा को समाप्त किया है। मुद्रा स्फिति का मुख्य कारण घाटे की अर्थ-व्यवस्था ही था। उस समय जबकि आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी उन्होंने संतुलित बजट पेश कर सराहनीय कार्य किया है। आशा है कि इससे स्थिति में सुधार होगा।

श्री पालकीवाल ने कहा है कि श्री मोरारजी के कार्य भार संभालने के थोड़े समय पश्चात ही धन लगाने वालों में विश्वास उत्पन्न हुआ है तथा स्थिति में परिवर्तन तथा गतिशीलता आई है। सरकार के कटु आलोचक श्री तारपोरवाल ने भी बजट को वास्तविकता पर आधारित, संतुलित तथा मुद्रास्फीति को रोकने वाला बताया है। सूखाग्रस्त लोगों की सहायता के लिये 13 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 38 करोड़ रुपये रखे गये हैं राज सहायता को जारी रखने के लिये भी 180 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि यह बजट विपत्ति का घोषणापत्र है। इस सब के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के स्थिति में सुधार के लिये भी बजट में व्यवस्था की गई है।

मैं अपने माननीय मित्र श्री मसानी तथा देवगुण से इस बात में सहमत नहीं हूँ कि इस बजट से मुद्रास्फीति को रोकने में सहायता नहीं मिलेगी। प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्रियों का मत है कि मुद्रास्फीति का मुख्य कारण घाटे की अर्थ-व्यवस्था है। उस बजट में इसको समाप्त कर दिया गया है तथा औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि उत्पादन के लिये कुछ प्रोत्साहन भी दिया गया है। चौथी योजना के व्यय की सीमा को कम करने का भी प्रस्ताव है।

समाचार पत्रों में ऐसे बहुत से अग्रलेख छपे थे जिनमें यह प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी कि भारी कराधान होगा क्योंकि मोरारजी ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार सम्भाल लिया है। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। बहुत कम कर लगाये गये हैं।

मुद्रास्फीति को रोकने के बारे में प्रो० वकील ने कई एक सुझाव दिये थे जिनमें एक सुझाव यह है कि मांग को कम कर सप्लाई को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि सरकार से फालतू कर्मचारियों की छंटनी की जानी चाहिए,।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha Then Adjourned for Lunch Till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुन: समवेत हुई

The Lok Sabha Reassembled After Lunch at Fourteen of the Clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*

सामान्य आय व्ययक 1967-68 सामान्य चर्चा-जारी

GENERAL BUDGET 1967-68 GENERAL DISCUSSION (CONTD)

श्री राने : तीसरा सुझाव यह दिया है कि अवांछनीय व्यय को रोका जाना चाहिए तथा घाटे की अर्थ-व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। यदि माननीय वित्त मंत्री के भाषण को सावधानी से पढ़ा जाये तो मालूम होगा कि इन सभी सुझावों को कार्यान्वित किया गया है। एक अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री शिहनाथ ने भी घाटे की अर्थ-व्यवस्था को समाप्त करने पर जोर दिया है।

इस बजट में योजना के परित्याग में भी वृद्धि नहीं की गई है। रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को जमा से अधिक रुपया देना भी लगभग समाप्त कर दिया गया है। इस बजट से औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। अतः यह बजट मुद्रास्फीति को रोकने वाला है।

उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को और अधिक उपाय सुझाने चाहिए उर्वरक पर दी जाने वाली राज सहायता बन्द नहीं की जानी चाहिए। इस बारे में वित्त मन्त्री को एक बार फिर विचार करना चाहिये। डीजल तथा बिजली पर सुझाये गये उत्पादन शुल्क में कमी की जानी चाहिए। पाकिस्तान तथा चीन की ओर से हमारी सीमाओं को बराबर खतरा बना हुआ है। इसलिए प्रतिरक्षा व्यय में कटौती का सुझाव व्यवहार्य नहीं है। श्री मसानी ने रक्षा व्यय में जो 50 करोड़ रुपये की कटौती का सुझाव दिया है। उक्त खतरे के देखते हुए वह बुद्धिमता पूर्ण नहीं है। परन्तु जहां कहीं सम्भव हो सरकार को असैनिक व्यय में कमी करनी चाहिए।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : कुछ सदस्यों ने वर्तमान स्थिति के वास्तविक मूल्यांकन के लिए उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री की प्रशंसा की है परन्तु सभी जानते हैं कि खाद्य स्थिति खराब है, मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, उद्योग में गतिरोध है तथा विदेशी मुद्रा का संकट विद्यमान है। वित्तमन्त्री ने अपने भाषण में यही कुछ बताया है। परन्तु इसमें कोई नई बात नहीं है। वास्तव में प्रश्न यह है कि क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री यह जानने में सफल हो गये हैं कि इस सब का कारण है। किस कारण हमें आज इस गम्भीर स्थिति का सामना है। यह ठीक है कि मानसून के न होने से अथवा सूखा पड़ने से गत दो वर्षों से हमारी अर्थ व्यवस्था गम्भीर हो गई है परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था में गतिरोध चीन के आक्रमण से पूर्व अर्थात 1962 से पूर्व ही आरम्भ हो गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कारखाने बन्द हो रहे हैं तथा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लोगों की वास्तविक आय में कमी होती जा रही है। किसानों पर सूदखोरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। एकाधिकार बढ़ता जा रहा है, देश में केवल 75 परिवारों ने समस्त अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर रखा है तथा वे राजनीति में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। कालाबाजार तथा चोर बाजार तथा भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, स्वदेशी शोषकों के अतिरिक्त विदेशी भी यहां आकर साधारण लोगों का शोषण कर रहे हैं। यह एक अनोखी प्रकार का समाजवाद है जिसका श्रेय कांग्रेसपार्टी को ही जाना चाहिए।

हमारे आर्थिक जीवन के बारे में तथ्य यह है कि हम पूर्ण रूप से विदेशी सहायता पर निर्भर है। हम प्रत्येक वस्तु अर्थात कपड़ा, खाद्य तथा उद्योगों के लिए विदेशों पर निर्भर है। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां हम विदेशी सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकते इसी कारण हमें रुपये का अवमूल्यन भी करना पड़ा क्योंकि हमारे ऊपर विदेशों का प्रभाव था। यह प्रभाव इसी कारण है क्योंकि हम पूरी तरह उन पर आश्रित हैं। बताया यह गया था कि अवमूल्यन से हमें विदेशी मुद्रा की अधिक प्राप्ति होगी। परन्तु हुआ इसके विपरीत है। वास्तव में विदेशी मुद्रा की आय में पन्द्रह प्रतिशत की कमी हुई है, अन्तिम परिणाम यह निकला है कि पश्चिमी शक्तियों ने स्थायी विषय विनिमय हमारे ऊपर लाद दिया है। हमें अपने निर्यात में वृद्धि करने के लिए विदेशी सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि बिना विदेशी सहायता के आगे नहीं बढ़ सकते।

योजना मंत्री ने सभा में कहा था कि तीन वर्ष के अन्दर अन्दर हम उवरंक के कारखाना में लगने वाली सभी मशीनरी भारत में ही बनाने में समर्थ हो जायेंगे। परन्तु वित्तमंत्री ने उवरंक के कारखाने स्थापित करने के लिये विदेशी फर्मों को उदार शर्तों की पेशकश की है।

इस विवरण के अनुसार हम उन्हें जो ब्याज, लाभांश तथा अन्य शुल्क हम दे रहे थे, वे प्रति वर्ष 12 प्रतिशत से बढ़ कर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में 22 प्रतिशत हो गये हैं। 1966–67 के पहले छ: मास में यह बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया है, इसका अर्थ यह है कि हमारे विदेशी निर्यातों का 27 प्रतिशत इन ऋणों पर लाभांश, परिशोधन तथा ब्याज का भुगतान करने के लिए बन्धक रखा जाना है, विदेशी नियंत्रण, विदेशी सहायता तथा विदेशी सहयोग बढ़ने के परिणामस्वरूप यह बढ़ता ही चला जायेगा।

देश में पूंजी निर्माण के बड़े साधन अर्थात कृषि के सूख जाने का कारण कृषकों की ऋण-ग्रस्त है। कृषक कृषि पर धन नहीं लगा सकता। पूंजी प्राप्त करने का एकमात्र साधन पूंजीपतियों के हित में जनता का शोषण करके धन प्राप्त करना है। कांग्रेस सरकार का 1947 के आरम्भ से उद्देश्य यही रहा है। दूसरी सभी नीतियां इस प्रकार है कि पूंजीपति धन प्राप्त करने में सफल हुए। हमारे एकाधिकारी वर्ग विश्व में सब से अधिक शोषण करते हैं।

मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही हैं परन्तु सरकार इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रही है कि जमाखोरी को बढ़ावा मिले। फसल के मौसम में बैंकों द्वारा ऋण का विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। रिजर्व बैंक उन बैंकों पर उचित नियंत्रण नहीं रखवा रहा है।

एक दिन पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि "यदि राज्य सरकारें मंहगाई भत्ता बढ़ाना चाहती हैं तो बढ़ालें। इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं।" परन्तु केन्द्रीय सरकार मूल्यों में वृद्धि के उत्तरदायित्व से कैसे बच सकती है। राज्य सरकारें ऋण विस्तार, रुपये के अवमूल्यन तथा ऐसी सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इसके विपरीत केन्द्र द्वारा ऐसे तरीके अपनाये गये हैं जिनके कारण राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के प्रयासों में रुकावट पड़ी है। उर्वरक के लिए सहायता न देना एक ऐसा ही तरीका है।

स्थिति का सामना करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि कुछ भी क्यों न हो, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करेंगे परन्तु अपने आदर तथा प्रतिष्ठा का सौदा नहीं करेंगे। इस आधार पर हमें यह निश्चय करना चाहिये कि आगामी पांच वर्षों में पी० एल० 480 खाद्य सहायता समाप्त कर देंगे। सरकार को धनी लोगों से विक्रययोग्य फालतू खाद्यान्न वसूल कर लेना चाहिये और उसका उचित रूप में वितरण किया जाना चाहिये। इसी प्रकार विदेशी सहायता भी तुरन्त समाप्त कर देनी चाहिये। हमें यह एक तरफ घोषणा कर देनी चाहिये कि हम आगामी दस वर्षों तक परिशोधन और ब्याज की राशि का भुगतान नहीं करेंगे क्योंकि देश कठिन परिस्थितियों में जा रहा है। विश्व के बहुत से देशों ने ऐसा किया है। विदेशी उपक्रमों से लाभांश भेजने पर भी हमें विलम्बकाल की घोषणा कर सकते हैं। 10 वर्ष की अवधि के लिए पूंजी की वापसी पर भी विलम्बकाल लगाया जाना चाहिये। इन सभी उपायों से हमें 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है।

सब से पहले हमें देश में एकाधिकारियों की शक्ति समाप्त करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये। भ्रष्टाचार तभी समाप्त हो सकता है। इसी प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी मूल्य वृद्धि नहीं रुक सकेगी क्योंकि पिछले 15-20 वर्षों में 3,000 से 4,000 करोड़ तक का काला धन सरकार द्वारा परिचालित कराया गया है। जब तक यह धन परिचालन से वापिस नहीं लिया जाता तब तक किसी भी वित्तीय उपाय यहां तक कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए, इस प्रकार का विमुद्रीकरण आवश्यक है। इसी प्रकार हमें ऐसे उपाय करने चाहियें जिन से भूमि के स्टाक, वस्तुओं के स्टाक तथा शेयरों में सट्टेबाजी समाप्त हो। यह सारा धन अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रतिरक्षा पर व्यय में अधिक कमी करना सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान तथा चीन के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने तथा तनाव करने के सभी सम्भव प्रयत्न करने के लिए तैयार हैं। यह बहुत प्रसन्नता की बात है।

यदि काम करने की इच्छा हो बहुत से काम किये जा सकते हैं। परन्तु हमारे मंत्री कुछ काम नहीं करना चाहते क्योंकि देश के पूंजीपति उनके अपने लोग है। इसलिए देश के लोग एक दिन उठेंगे और ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : श्री राममूर्ति ने कहा है कि कांग्रेस आज कानपुर के उन्हीं करोड़पतियों के साथ घुल मिल रही है जिनके द्वारा बनाये गये कपड़े का समर्थन करने से पंडित मोतीलाल नेहरू ने इनकार कर दिया था परन्तु मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि 1942 में जबकि सारा देश स्वतन्त्रता के लिए युद्ध लड़ रहा था तब श्री राममूर्ति यह कहकर कि यह युद्ध जनता का युद्ध है, अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे।

{ **श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए**
Shri Balraj Madhok *in the Chair* }

उन्होंने वित्त मंत्री के उस वक्तव्य का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि अपने विरोधी पड़ौसी देशों के साथ हमें बातचीत करनी चाहिये। मैं उन्हें साम्यवादी दल के महा-सचिव का वह वक्तव्य याद कराता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि अक्साई चिन तथा अन्य क्षेत्र चीन को दे देने चाहियें। दूसरों को उपदेश देने से पूर्व हमारे साम्यवादी मित्रों को राष्ट्रवादी तथा देश-भक्ति के तरीके अपनाने चाहियें। भारत के साम्यवादी दल के रवैये से देश की क्रमबद्ध प्रगति में बाधा उत्पन्न हो गई है।

मेरा वित्त मंत्री से सुझाव है कि उन्हें पी० एल० 480 सम्बन्धी श्री राममूर्ति के विचार मानकर खाद्यान्न का आयात बन्द कर देना चाहिये और खाद्य स्थिति में आत्म निर्भरता लानी चाहिये। परन्तु इसके साथ ही आयातित खाद्यान्न पर मिलने वाली सहायता भी बन्द कर दी जानी चाहिये।

यद्यपि श्री मोरारजी देसाई ने इस आयव्ययक को क्रान्तिकारी रूप नहीं दिया है, तथापि यह कहना गलत है कि यह आयव्ययक पहले की भांति है। देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह एक वास्तवादी आयव्ययक है।

देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कुछ प्रयत्न किये हैं। उन्होंने आयव्ययक में राज्यों का आवंटन कोटा बढ़ा दिया है। परन्तु इससे उन्हें अपनी योजनायें क्रिया-न्वित करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। अधिक साधन जुटाने में राज्य सरकारों की सुविधा के लिए उन्हें कुछ वास्तविक कार्यवाही करनी चाहिये तथा केन्द्रीय सरकार पर अधिक आश्रित नहीं रहना चाहिये।

माननीय वित्त मंत्री ने मुद्रास्फीति की भावना को समाप्त करने, मुद्रास्फीति के बिना ही केन्द्रीय सरकार के व्यय को जुटाये गये संसाधनों के अनुसार कड़ाई के साथ सीमित करने और यह सुनिश्चित करने कीं आवश्यकता को, कि गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को ऋण सीमित करने के कारण उत्पादन बढ़ाने से न रोका जाये, अधिक महत्व देकर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। हमारी आर्थिक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने कुछ आवश्यक पग उठाये हैं।

कृषि उपज पर माननीय वित्त मंत्री ने बहुत बल दिया है। इस बात के बावजूद, कि हम लगभग 2 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता पैदा करने में सफल हुए हैं, हम बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का केवल 80 प्रतिशत ही उपयोग में ला सके हैं। हमने छोटी सिंचाई परियोजनाओं के मामले में अधिक प्रगति नहीं की है। वित्त मंत्री इस मामले में विशेष पग उठा सकते हैं। उन्होंने भूमि बन्धक बैंकों के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है परन्तु उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया है। मालूम नहीं इसका क्या कारण है। सहकारिता क्षेत्र हमारे सुस्थापित क्षेत्रों में से है। केवल उसी क्षेत्र द्वारा लाखों किसानों के पास पहुंचा जा सकता है और उन्हें कृषि के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

एक ओर बात जिस पर मंत्री महोदय ने बल नहीं दिया है, देश में कृषि मशीनरी का उपलब्ध न होना है। उन्हें यह भी देखना चाहिये कि कृषकों को कृषि के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध कराये जायें ताकि वे अपना कार्य चालू रख सकें। केन्द्रीय सरकार को पौधा संरक्षण उपायों के लिए राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता देनी चाहिये। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने कृषकों के लिए फसल का बीमा करने के सम्बन्ध में संकल्प कई बार पारित किया है। इस सम्बन्ध में एक या दो राज्यों ने कार्य आरम्भ कर दिया है। इसे निष्ठापूर्वक क्रियान्वित कर देना चाहिये ताकि इसका लाभ कृषकों को हो सके।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

माननीय वित्त मन्त्री ने केवल उन्हीं वस्तुओं पर कर लगाये हैं या वृद्धि की है जिन मूल्यों में वृद्धि न होने पाये। चाय तथा काफी पर कर से जनसाधारण पर कुछ बोझ पड़ेगा। माननीय मन्त्री को चाहिये था कि कुछ ऐसे उपाय सुझाव जिनसे काफी आदि के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता। हमें देश की आन्तरिक खपत पर भी कुछ नियन्त्रण लगाना चाहिये।

जूतों पर कर लगाना उचित नहीं है। क्योंकि इससे आम लोगों के लिये मुश्किल हो जायेगी। मुझे बताया गया है कि यह कर बड़े बड़े कारखानों पर लगाया जायेगा परन्तु हमारे देश में कठिनता यह है कि एक वस्तु के मूल्य बढ़ने से अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ जाते हैं और जनता कुछ नहीं कर सकती। पैट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल पर कर से देश के किसानों को अन्ततः अधिक मूल्य देने पड़ेंगे। सरकार को किसानों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। यदि यह बजट मुद्रा स्फीति पर रोक लगाने में सफल होता है तो यह एक आदर्श बजट होगा। हमें आशा है कि श्री मोरारजी का बजट जनसाधारण में उत्साह उत्पन्न करेगा। अगले साल एक और भी अच्छा बजट लाया जायेगा।

हमारे देश के आर्थिक विकास के कार्य में विभिन्न क्षेत्रों में विषमता आ गई है। कुछ एक लोगों के हाथों में एकाधिकार हो गया है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिये। देश के सभी क्षेत्रों तथा राज्यों के विकास तथा प्रगति पर एक समान ध्यान देने की आवश्यकता है।

आन्ध्र प्रदेश अन्य राज्यों को अनाज सप्लाई करता है परन्तु फिर भी उस राज्य का कोई आभार नहीं मानता है। आन्ध्र के प्रति केन्द्रीय सरकार का रवैया बहुत खेद जनक रहा

है। यहां की सरकार से अपेक्षित सहायता नहीं मिली है। नागार्जुनसागर परियोजना के मामले में आन्ध्र प्रदेश से बहुत भेद-भाव बरता गया है। आन्ध्र प्रदेश को परियोजना के पूरे होने से पहले ही ऋण पर ब्याज की वसूली आरम्भ कर दी गई है। यदि आन्ध्र प्रदेश अपेक्षित सहायता मिल जाये तो प्रतिवर्ष 16 लाख टन चावल इस राज्य में उत्पन्न हो सकता है। इस परियोजना पर 1955 में काम आरम्भ किया गया था। परन्तु बाँध के बन जाने के बाद भी नहरों आदि के निर्माण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आन्ध्र प्रदेश ने दो वर्षों में इस काम के लिये 30 करोड़ रुपये की मांग की है। यह माँग पूरी होनी चाहिये। आन्ध्र प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो अपने कुल खर्चे का 14 प्रतिशत व्यय सिंचाई कार्य पर कर रहा है जबकि अन्य राज्य अधिकाधिक 7 प्रतिशत इस कार्य पर व्यय करते हैं। आन्ध्र प्रदेश को बिजली की कमी को पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सहायता करनी चाहिये। मद्रास राज्य इस बारे में बड़ी अच्छी स्थिति में है। वहाँ पर दो बड़ी बड़ी विद्युत योजनाएं हैं। मेरा सुझाव है एक राज्य को दूसरे राज्य की सहायता करनी चाहिये।

श्री नम्बियार (तिरुचिनापल्ली) : केरल राज्य की स्थिति भी अधिक अच्छी नहीं है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में अकाल फैला हुआ है। वहाँ सहायता कार्य अधिक तेज करने की आवश्यकता है।

श्री पे वेंकटासुब्बया : सभी अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता में तेजी आनी चाहिये। आन्ध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। केन्द्रीय सरकार को इसमें सहायता देनी चाहिये। तुंगभद्रा एक ऐसी परियोजना है जिससे मद्रास, मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश सभी राज्यों को लाभ होगा। इससे न केवल पानी मिलेगा बल्कि अकाल की स्थिति कभी भी खड़ी नहीं होगी।

बैंकों की राष्ट्रीयकरण के बारे में कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प पारित किया है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण का श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही है। हम देश में समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं। अब सरकार को बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय भी करना चाहिये।

भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े महाराजाओं को अपनी थैलियों में स्वेच्छा से कटौती कर देनी चाहिये। हाँ छोटे राजाओं को निजी थैली का धन मिलता रहना चाहिये। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। हमें कोशिश करनी चाहिये कि जनसाधारण की मुश्किलें और न बढ़ें। मुझे आशा है, कि मूल्यों की बढ़ने की प्रवृत्ति को रोका जायेगा और मुद्रा स्फीति भी रुकेगी। खेद की बात है कि हमारे देश में इस समय बड़ी संख्या में जाली मुद्रा चल रही है। इस पर रोक लगनी चाहिये क्योंकि इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है।

श्री श्री अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : इस बजट से चाय, काफी, जूतों तथा सिग्रेटों पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया जा रहा है। शक्तिचालित करघों को सप्लाई होने वाले सूत पर कर में भी वृद्धि की जा रही है। इससे जनसाधारण पर बोझ और बढ़ जायेगा। मैं ऐसे बजट की प्रशंसा नहीं कर सकता। सरकार के हाथ में सत्ता है और जैसा वह चाहे बजट बना सकती है। सरकार को करों में वृद्धि करके बजट को सन्तुलित नहीं बनाना चाहिए।

यह बड़ी विचित्र बात है कि सरकार पहले तो करों में वृद्धि कर देती है और फिर कहती है कि मूल्यों में वृद्धि नहीं होने दी जायेगी। रेलवे मन्त्री ने जैसे किया है कि पहले तो किरायों में 7 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा कर दी और बाद में इस वृद्धि को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। क्या वित्त मन्त्री भी ऐसा ही करेंगे ? हमारे देश में कीमतों के बढ़ने के क्या कारण हैं ? इसका उत्पादन लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है या इसका मंहगाई भत्ते से कोई संबंध नहीं है। यह कहा जाता है कि हमारे देश में इस्पात का मूल्य बहुत अधिक है । परन्तु हमें देखना चाहिये कि हमारे देश में मजूरी अन्य देशों से बहुत कम है । इससे यह पता चलता है कि मूल्यों में वृद्धि मजूरी अधिक होने अथवा मंहगाई भत्ता अधिक होने के कारण नहीं है । वास्तव में मूल्यों में वृद्धि बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में एकाधिकार के कारण है। जब तक एकाधिकार समाप्त नहीं किये जाते मूल्यों में कमी नहीं होगी। हजारी रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है। कृषि उत्पादन की केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। जब कृषि में अधिक उत्पादन हुआ तब भी मूल्य बढ़े ही थे क्योंकि कृषि के उत्पादन पर बड़े जोतदार; बड़े भूमिदार तथा अमीर किसानों का नियन्त्रण है । दूसरे बैंकों द्वारा धन देने का भी इस पर प्रभाव पड़ रहा है। बैंक व्यापार तथा ऋण के नाम धन पेशगी देते हैं और अन्त में वह धन सट्टेदारों के पास चला जाता है जो अन्न के भण्डार जमा कर लेते हैं और उस समय बाजार में वह अन्न पटकते हैं जब उसका मूल्य अधिक होता है । इसलिए यदि आप कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा भी दें तो भी मूल्यों के कम करने में आप सफल नहीं हो सकते । इसलिए जब तक आप बेंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे आप मूल्यों को नीचे नहीं ला सकेंगे ।

वित्त मन्त्री तथा उनके मित्र यह सोचेंगे कि मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे पड़ा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है । आप मुझे मूल्यों को कम करने का कोई और तरीका बता दें ? आप गत 15 वर्षों से अर्थात जब से 1951–52 में योजना आरम्भ की तब से यह प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु असफल हो गये हैं । फिर आप अपनी असफलता मानते क्यों नहीं हो ? इसलिए कांग्रेस नेतागण एकाधिपत्यों को सुरक्षित किये हुए हैं । वह कांग्रेसी भी जो मूल्यों को कम कराना चाहते हैं इस कार्य में तब तक सफल नहीं होंगे जब तक बैंक निजी क्षेत्र में रहेंगे ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बजट में मूल्यों के कम करने का कोई ठोस सुझाव नहीं आया है । उनका कहना है कि मुद्रास्फीति को भावना को ही वह समाप्त करना चाहते हैं। उत्पादन शुल्क के कारण मूल्यों के बढ़ने से वह मुद्रास्फीति की भावना को कैसे समाप्त करेंगे, यह मेरी समझ से बाहर है।

इसलिए वित्त मन्त्री ने जो यह कहा कि वह इस समस्या का निवारण करेंगे, वह वास्तव में इसका निवारण नहीं कर सकेंगे और मूल्य और अधिक बढ़ जायेंगे तथा फिर मंहगाई भत्ता बढ़ाने की मांग होगी और सरकार उसे मानेगी नहीं और फिर और संघर्ष होगा ।

यह कहना कि यह संतुलित बजट है एक भ्रम है क्योंकि एक उपभोक्ता के रूप में मैंने 115 करोड़ रुपया अपनी जेब से खोये हैं । आप उसे दूसरी ओर रख देते हैं और कहते हैं कि यह संतुलित बजट है । इसलिए यह संतुलन एक भ्रम है और इसका प्रभाव जन साधारण पर पड़ रहा है ।

वह एकाधिपतियों के प्रति एक सेवा कर रहे हैं । कर मुक्ति की अवधि 6 वर्ष से बढ़ा कर 8 वर्ष कर दी है। इसका प्रभाव भी साधारण व्यक्तियों पर पड़ रहा है ।

फिर वह कहते हैं कि वर्तमान बजट से मुद्रास्फीति कम होगी । परन्तु मुरारजी देसाई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति समाप्त हो जायेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि मुद्रास्फीति की स्थिति केवल समाप्त होगी, मुद्रास्फीति स्वयं को समाप्त नहीं किया जायगा। श्री शिनौय जो कि एक माने हुए अर्थशास्त्री हैं ने 31 मई को कहा है कि बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। वह तो साम्यवादी नहीं है न ही वह अमरीका विरोधी हैं । उनका कहना है कि अमरीकी पी० एल० 480 के धन से उतनी ही मुद्रास्फीति होगी जितनी दूसरे प्रकार से उत्पन्न किये धन से होती है । 1964–65 में अमरीकी दूतावास द्वारा 80 करोड़ रुपया व्यय किया गया। उन्होंने कहा है कि पी० एल० 480 का पूरा कार्यव्यवहार छानना चाहिए ।

वह उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं । मैं उनसे सहमत हूँ कि देश में मन्दा नहीं है, कुछ उत्पादन में कमी होगई है । इसका कारण यह है कि एकाधिपतियों ने उत्पादन के स्रोतों पर काबू किया हुआ है तथा माँग को कम कर दिया है। जब तक मूल्यों को नीचे नहीं लाया जाता, उत्पादन बढ़ नहीं सकता। अभी कोयला खान मालिकों के प्रधान ने कहा कि वहां पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। वह कहते हैं कि पूरा उपयोग होना चाहिए। मैं उनसे सहमत हूँ। अवमूल्यन के बाद आत्म निर्भरता का नारा लगाया गया था परन्तु बाद में इसे छोड़ दिया गया। हमारे यहाँ मशीनों के पुर्जे तथा मशीनरी बनाने की क्षमता है परन्तु हम विश्व बैंक के आदेशों के कारण उसका उपयोग नहीं कर सकते और वह बेकार पड़ी रहती है । इसी प्रकार यहां रेलवे की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा परन्तु हम रेलवे के लिए कनाडा तथा अमरीका में मांग भेज रहे हैं । इंजीनियरिंग उद्योग में छटनी हो रही है । जिन वस्तुओं का उत्पादन यहां हो सकता है उनका आयात बन्द कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा न करना ही उत्पादन के रास्ते में बड़ी रुकावट है। काँग्रेस के नेताओं को भी इस बात का पता है, फिर वह इसके बारे में कार्यवाही क्यों नहीं करते ? क्योंकि आपकी नीति ही ऐसी है । आप विदेशी सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकते। मैं विदेशी सहायता के विरुद्ध नहीं हूँ । मेरा कहना है कि आप उन मामलों में विदेशी जानकारी प्राप्त करते हैं जहाँ हमारी अपनी जानकारी काम में आ सकती है तथा जहाँ कि हमारे वैज्ञानिक और तकनीशियन अपने आविष्कार कर सकते हैं। हम गत दो तीन योजनाओं में लगभग 15,000 करोड़ रुपये की राशि लगा चुके हैं परन्तु बहुत से कारखाने बिना उपयोग के पड़े हुए हैं या उनका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है और कुछ में तो तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां भी हो रही हैं । रांची के इस्पात कारखाने में भी तोड़ फोड़ हुई है। क्या योजना आयोग में इन बातों की कोई जाँच हो रही है।

किसी ने कहा कि स्टालिन ने योजना बनाने वालों को गोली मार दी थी। परन्तु हमारे देश में यदि योजना आयोग में कोई असफल हो जाये तो उसे मन्त्री बना दिया जाता है और यदि मन्त्री के कार्य में असफल हो जावे तो उसे राज्यपाल बना दिया जाता है और वहाँ भी असफल हो तो उसे राजदूत बना कर बाहर भेज दिया जाता है। इस प्रकार पीछा छुड़ाने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु वे फिर यहाँ वापिस आ जाते हैं। इसलिए मैं यह तो नहीं कहता कि स्टालिन के तरीके को अपनाओ या न अपनाओ परन्तु असफलता को इस प्रकार पारितोषिक तो मत दो। और इसके बाद कारखानों की जाँच पड़ताल करो।

सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत से कारखाने तथा प्रबन्धक अच्छे हैं और मैं समझता हूँ कि वह निजी क्षेत्र पर काबू पा जायगा। वहाँ भ्रष्टाचार भी है परन्तु क्या निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं है। वहाँ तेजा है तथा मुन्धरा है और कपड़े के मिल है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि भ्रष्टाचार केवल सरकारी क्षेत्र में ही है। यह निजी क्षेत्र में भी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबन्धक गुणों तथा तकनीकी ज्ञान के आधार पर नियुक्त करना चाहिए। वहां के प्रबन्धकों को उनके वेतनों के अतिरिक्त उत्पादन की किस्म पर कमीशन मिलना चाहिए। यदि आप ऐसा कर दें तो प्रबन्धकों के रवैये में परिवर्तन आ जायेगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार आ जावेगा। इससे चोरी समाप्त होगी और कार्यकुशलता बढ़ेगी।

उत्पादन शुल्क का अधिक लागू करना गलत है तथा इससे निर्वाह व्यय देशनीक अधिक हो जावेगा। एकाधिपत्यों की आलोचना न करने की पद्धति गलत है। यदि आप बैंकों को निजी लोगों के हाथ में रहने देंगे तो आप देश की समस्या नहीं सुलझा सकेंगे।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

सरकार विदेशी मुद्रा के चोरों के प्रति नम्र क्यों है? बर्ड हेल्जर्स ने विदेशी मुद्रा की चोरी की तथा उन पर 1.55 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया। राजस्व बोर्ड ने इसे घटाकर 48 लाख रुपया कर दिया और इस प्रकार उन्हें 1 करोड़ रुपया ले जाने की अनुमति दे दी। यह नम्रता मेरी समझ से बाहर हैं। बर्ड हेल्जर्स का सम्बन्ध बिरला औद्योगिक साम्राज्य से है तथा वे अब यूरोपीय नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री महोदय का वक्तव्य होगा। आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं।

पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DEVELOPMENT IN WEST ASIA

प्रधानमंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) लगभग दो सप्ताह हुए मेरे सहयोगी वैदेशिक-कार्य मंत्री ने सदन में वक्तव्य दिया और पश्चिमी एशिया की भयंकर स्थिति के बारे में सरकार का मत व्यक्त किया।

उसके बाद से सुरक्षा परिषद् तथा उससे बाहर हमारा प्रयत्न वहां तनाव को कम करने तथा शान्ति बनाये रखने में रहा है। हमारे प्रतिनिधि के प्रयत्नों की अच्छी प्रतिक्रिया हुई और यह आशा हुई कि सुरक्षा परिषद् की अगली बैठक में इस मामले में काफी प्रगति हो जावेगी।

अभी उक्त प्रयत्न जारी थे कि कल इसराइल तथा संयुक्त अरब गण राज्य और अन्य अरब देशों के बीच संघर्ष के समाचार प्राप्त हुए।

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने सुरक्षा परिषद् की आपात कालीन बैठक में सारा ब्यौरा दिया और यह भी बताया कि इसराइली वायुयानों ने संयुक्त अरब गणराज्य तथा सीरिया के क्षेत्रों पर आक्रमण किया।

मैं कठोर शब्द नहीं प्रयोग करना चाहती परन्तु जो सूचना मिली है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि इसराइल ने इस सशस्त्र झगड़े को पूरी लड़ाई में परिवर्तन कर दिया है।

ससार को पश्चिमी एशिया में एक भयानक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है जहां इसराइल तथा अरब सेना एक दूसरे के विरुद्ध हैं और यदि यह लड़ाई रोकी नहीं गई तो एक बड़ी लड़ाई बन जायेगी। हमारे अपने राष्ट्रीय हित भी पश्चिमी एशिया की मजबूती से सम्बन्धित है। हमारा सबका कर्तव्य है कि इस खतरनाक स्थिति में पुनः शान्ति स्थापित की जाये।

सुरक्षा परिषद् में हमारा यह पूरा प्रयत्न हो रहा है कि सब सशस्त्र सेना 4 जून के स्थानों पर आ जावें।

सदस्यों ने इसराइली तोपखाने द्वारा अकारण गाजा स्थित संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के भारतीय सैनिकों की मृत्यु के समाचार पढ़े होंगे। यह आक्रमण जान बूझकर किया गया तथा बिना उत्तेजना के किया क्योंकि हमारे दल पर संयुक्त राष्ट्र संघ के निशान थे।

इस सम्बन्ध में मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को एक पत्र भेजा है जिसमें इन घटनाओं पर अपना दुःख तथा रोष प्रकट किया है और कहा है कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा तथा लड़ाई क्षेत्र से शीघ्र निकालने के बारे में कारगर कदम उठाये जायें।

सरकार इन पांच सिपाहियों के परिवारों को पर्याप्त मात्रा में मुआवजा देगी जिन्होंने वहां अपना जीवन बलिदान किया। यह रकम उससे कम नहीं होगी जो उनके परिवारों को उस समय मिलती यदि यह युद्ध में मारे जाते। इसी बीच मैं प्रत्येक परिवार को 5000 रु० तात्कालीक सहायता के रूप में प्रधान मन्त्री के राष्ट्रीय सहायता निधि से भेज रही हूं।

मुझे विश्वास है कि यह सदन इन शान्ति के सिपाहियों पर जो आक्रमण किये गये उसकी भर्त्सना करेगा। महासचिव ने इसराइल सरकार से कड़ा विरोध किया है। सारे सदन की ओर से मैं इन दुःखी परिवारों को सदन की ओर से सहानुभूति के संदेश भेजना चाहती हूँ कि उन बहादुरों ने मानवता तथा शान्ति के लिए अपना जीवन बलिदान दिया।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हमें दो मिनट के लिए अपनी श्रद्धांजली देने के लिए खड़े हो जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन चाहता है तो हम खड़े हो जायेंगे।

(इसके पश्चात् सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे)

(The members then stood in Silenne for a short while)

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव यह कि बहुत से सदस्यों की बजाय प्रत्येक दल से एक एक सदस्य ही बोलें।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : हमें इन पाँच जवानों की मृत्यु का दु:ख है। वह वहां अपनी इच्छा से नहीं थे बल्कि वे शान्ति स्थापना का कार्य कर रहे थे। वहां एशिया के लिए एक और दु:ख की घटना हो रही है। ऐसे मामले में हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा कार्य करेगी जिससे सारे राष्ट्र की भावना प्रतिबिम्बित हों। परन्तु दुःख से कहना पड़ता है कि वह संतोषजनक नीति नहीं अपना रहे। इसके बारे में सरकार को इस सदन में हमने चेतावनी भी दे दी थी। कल हमने प्रधान मंत्री को एक पत्र भी लिखा है और सुझाव दिया है कि कम से कम अब तो वह सरकार को परामर्श दे कि एक रचनात्मक रवैया अपनाये।

श्री मु० यू० सलीम (नलगोंडा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रधान मंत्री ने नियम संख्या 197 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया है तथा उस पर चर्चा नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा नहीं है। कुछ स्पष्टीकरण हो रहा है और इस सदन में इस प्रकार के स्पष्टीकरण की प्रथा है। इसलिए कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रंगा : महोदय प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है वहां शीघ्र युद्धविराम होना चाहिए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने प्रतिनिधि से कहा है कि वह इसका प्रयत्न करे। फिर क्या कारण है कि इसके लिए किसी को दोषी ठहरा रहे हैं? आज प्रातः बताया गया कि उनके पास सूचना है परन्तु जब हमने उसके बारे में पूछा तो बताया गया कि वह समाचार पत्रों में आ गई है। अब हम भी दूसरों के साथ मिल गये हैं। हमें शान्ति के लिए प्रबल करना चाहिए क्योंकि हमारे देश के लिए अनाज भी उसी रास्ते से आ रहा है और लड़ाई के कारण उसमें देर हो गई है। इसलिए सरकार यदि वास्तव में तटस्थ रहना चाहती है तो फिर किसी की हिमायती नहीं करनी चाहिए।

Shri A.B.Vajpayee (Balrampur): Sir, the Prime Minister has lost the opportunity of having a national policy on the question of West Asia. I want to make it clear that we want to be friends with Arab countries.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : महोदय जब भी प्रधान मंत्री कोई वक्तव्य देती हैं तो विरोधी पक्ष के नेताओं को न केवल स्पष्टीकरण के बारे में प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है बल्कि अपने विचार प्रकट करने का भी। मैं उस ओर के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह बे सबरी न दिखाये और व्यवधान न करे। यह एक खतरनाक कार्य है।

अध्यक्ष महोदय : गत पांच छः दिन से उसके बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के नोटिस मेरे पास आ रहे हैं तथा सारे देश की इसमें रुचि है। इसलिए यदि कुछ सदस्य इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो बेसबरी नहीं दिखानी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। दलों के नेताओं को भी अपनी बात कहने में अधिक समय नही लेना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : My party wants friendship with the Arab nations but not on the condition of annihilation of the Israel State. If they insist on the destruction of Israel we cannot accept their friendship.

The hon. Prime Minister should have made it clear in the House that India will not be a party in any efforts made to erase Israel from the map of the world and anybody who will attemp it will lose our sympathy. There are some countries among the Arabs, who are the instigator of the imperialist powers openly support Pakistan during the Indo-Pak conflict. I would, therefore say that we should formulate our foreign policy keeping in view all this and also the help and support given to us by the United Arab Republic at the time of Indo-Pak conflict. The help and support was not so as was expected.

Whereas in the United Nations we have adopted a moderate approach here in New Delhi we have acted in a hurry in branding the Israel as an agressor. I would request the hon. Prime Minister to place the relative data, information and its source on the Table of the House.

I would also like to know who is responsible for the death of our Jawans posted in the Gaza strip. Why they were not evacuated earlier? Whether the arrangements are being made for eviction of the armymen who are still there.

श्री अंबाज्रासन (तिरूवेगोड) : हम भी उन भारतीय सिपाहियों के प्रति श्रृद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने शान्ति के लिए विदेशी भूमि में अपने जीवन का बलिदान दिया है।

ऐसे गम्भीर संकट में प्रधान मंत्री को यथासम्भव सभा की सहमति प्राप्त करनी चाहिये ताकि इस बारे में हमारी नीति में कोई दो मत न हों। हमें सामान्य दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस बारे में भी हमें गुटों से अलग रहने की नीति पर चलना चाहिए था। इसी नीति पर हम एक लम्बी अवधि से चल रहे हैं और यह शान्ति बनाये रखने में सहायक सिद्ध हुई है।

इस समय जब कि पश्चिमी एशिया में युद्ध भड़क उठा है और इसके अन्य भागों तक फैलने का भय है हमें अपने राष्ट्र की ओर से सावधानी से काम लेकर कोई वक्तव्य देना चाहिए था। विदेश नीति में सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अत्यावश्यक है। अतः प्रधान मंत्री को कोई व्यक्तव्य देने से पूर्व किसी अधिक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण) : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पांच सिपाही जिनको श्रृद्धांजलि देने के हेतु हम खड़े हुए इजराइल के आक्रमण से ही मारे गये हैं।

अरब लोगों के स्वतन्त्रता अन्दोलन में गड़बड़ करने के लिए ब्रिटिश तथा अमरीकन साम्राज्यवादियों के इशारे पर इजरायल बनाया गया है। पश्चिमी जर्मनी इजरायल को हथियारों से लैस कर रहा है जब कि हिटलर के हाथों यहूदियों को बहुत दुख उठाना पड़ा था।

यदि भारत साम्राज्यवाद में सम्मिलित न होकर गुटों से अलग रहने की नीति पर दृढ़ रहना चाहता है तो उसको साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों का समर्थन करना चाहिए

अर्थात् वर्तमान मामले में इजरायल नेतृत्व के विरुद्ध अरब लोगों का साथ देना चाहिए। सरकार को युद्ध-विराम कराने तथा युद्ध को फैलाने से रोकने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार अरबों के समर्थन की नीति पर अग्रसर रहे और इसी कारण हम सरकार की नीति का समर्थन करते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : The Government is pursuing two different policies one in the U.N.O. and other in Delhi as regards the crisis of the West Asia is concerned. I have every appreciation for the work done in the Security Council by the Indian representative. The Government should adopt a positive policy of self respect whereby the countries partitioned by the imperialists could be united. Here I would say that Russians have the as much hand in the creation of the Israel as the Britishers and the American hand. Not only Israel but Jordon, Iraq and Saudi Arabia are all the creations of the imperialists.

The Pope has appealed that the jereusalam may be declared an open city. I would say that it would be better if the Government of India expresses its wrllingness in their favour.

We should not brand any body aggressor. Efforts should be made to bring cease-fire in this region.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : साम्राज्यवादी शक्तियां अपने तेल के हितों के कारण ही इजरायल और अरबों को लड़ाती रहती हैं। यही कारण है कि वह इनमें सुलह नहीं होने देते। आजकल अरब में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध लहर उठ रही है। इस लहर को जागरूक करने में राष्ट्रपति नासिर सब से आगे हैं। साम्राज्यवादियों को भय है कि यदि अब नहीं तो भविष्य में किसी समय उनके तेल सम्बन्धी खतरे में पड़ सकते हैं।

जिसमें संयुक्त अरब गणराज्य के उपराष्ट्रपति तथा मंत्री अमरीका में बातचीत करने के लिए जा रहे थे उसी समय आक्रमण शुरू हो गया। युद्ध के आरम्भ होने से कुछ दिन पूर्व ही अमरीका तथा ब्रिटेन ने अकाबा खाड़ी को खोलने पर जोर दिया था। उसी समय इस छोटे से देश ने संयुक्त अरब गणराज्य पर आक्रमण कर दिया। इससे स्पष्ट है कि उसके पीछे किसी का हाथ था। इसलिए हमें अरबों की सहायता करनी चाहिए। मैं प्रसन्न हूं कि सरकार ने यही नीति अपनाई है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपने दल के विचार व्यक्त करने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे देश जिसने सदा देश के अन्दर तथा बाहर शान्ति के लिए कार्य किया है के नागरिक के नाते कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम सब की संसार के इस क्षेत्र में दिलचस्पी है क्योंकि यदि यह संघर्ष लम्बी अवधि के लिए जारी रहता है तो हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें सर्व प्रथम अपने देश के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमें किसी दल का पक्ष न लेकर यथासम्भव शान्ति स्थापित कराने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

श्री ग्रा० ना० मुल्ला (लखनऊ) : यह सच है कि सर्वप्रथम हमें शान्ति स्थापित करने के लिए ही प्रयत्न करने चाहिए परन्तु उसी समय हमें यह भी देखना है कि किस दल का

दावा कितना उचित है। इस संसार में हम पड़ोसियों की तरह रहते हैं इसलिए जो कुछ हो रहा है उस बारे में हमें अपनी आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए।

पाकिस्तान-विरोधी धारणा के कारण ही कुछ लोग इस संकल्प का विरोध कर रहे हैं। यदि हम इस बात की अनुमति देते हैं तो मुझे डर है कि चीन के विरुद्ध हमें फारमोसा को भी समर्थन देना पड़ेगा। इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): At this Juncture, the Prime Minister should have used restraint in her speech. She was expected to work for peace in the present circumstances but, unfortunately, her speech has been quite differently. Only time will tell the price India will have to pay for the same,

India does not have diplomatic relations with Israel. In these circumstances, how can Government of India blame her for having accelerated the war. I would like to know whether those, who thereatened to wipe out Israel from the map within four days, are not responsible for accelerating the war. The Government of India wants Israel to go back to June 4 position but what about the blockade of gulf of Agba, which is the real cause of war. The Prime Minister should explain her stand on this matter.

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : समूचा सदन किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति के पक्ष में है परन्तु उसका अर्थ यह है कि हम किसी विषय के गुणावगुणों के आधार पर उस बारे में निर्णय करने में स्वतन्त्र हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार उस निष्कर्ष पर पहुँची है कि इसके लिए एक पक्ष जिम्मेदार है, मेरे विचार में हमारी सरकार ने ठीक ही किया है।

हमें अपने उन वीरों की मृत्यु पर खेद है जो शान्ति स्थापित करने के लिए वहां गये और जिनकी मृत्यु होगई। इस मामले में केवल विरोध करना ही पर्याप्त नहीं है। इस मामले को हमें स्वतन्त्र तथा साहसी देशों की भांति उठाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : प्रधान मन्त्री के उत्तर देने से पहले मैं सभा को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, प्रधान मन्त्री को भी सभी बातों की जानकारी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी एक घण्टा पहले समाचार मिला है कि.........

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा (अन्तर्बाधायें)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : **

श्री जे० बी० कृपलानी (गुना) : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि हम इस समय किसी को दोष दे सकें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सभी सदस्यों ने राष्ट्रसंघ में हमारे द्वारा अपनाये गये पक्ष का समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो इससे उस क्षेत्र में शान्ति की स्थापना में बहुत सहायता मिलेगी।

**कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि हमें इस विषय में अधिक सावधान रवैया अपनाना चाहिए। भारत की स्वतन्त्रता को लगभग 20 वर्ष हो चुके है। हमने सावधान रहकर विश्व पर कोई प्रभाव नहीं डाला है । न्याय तथा शान्ति के सम्बन्ध में दृढ़ रवैया अपना कर हमने विश्व पर अपना प्रभाव डाला है । गुटों से अलग रहने की नीति का अभिप्राय यह नहीं है कि हमें तटस्थ रहना चाहिये । कोई विचारशील व्यक्ति घटनाओं को देखकर निस्प्रभावित नहीं रह सकता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने पूछा है कि क्या अकाबा की खाड़ी में संयुक्त अरब गणराज्य की कार्यवाही ही युद्ध का कारण है । मैं नहीं समझती कि इस प्रश्न में पड़ने से कोई लाभ होगा। हम जिस विदेश नीति का अनुसरण कर रहे हैं वह उस नीति का अंग है जिसका राष्ट्र ने पिछले वर्ष अनुसरण किया है । राष्ट्र ने भारत सरकार की नीति का पूरा समर्थन किया है।

श्री समर गुह : यह नीति राष्ट्र के हित में नहीं है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक भारत में अनाज लाने का सम्बन्ध है, स्वेज नहर बन्द होने से विलम्ब तथा कठिनाई होगी । परन्तु इससे चावल के सम्भरण पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझती कि इसके परिणाम गम्भीर होंगे। संयुक्त अरब गणराज्य तथा स्पेन से कुछ मात्रा लानी बकाया है । इसमें विलम्ब हो जायेगा, क्योंकि स्पेन के जहाजों को विशेषतया उत्तम आशा अन्तरीप से घूमकर आना पड़ता है। गेहूँ तथा मक्के पर भी प्रभाव पड़ेगा।

इसराइल की तबाही का उल्लेख किया गया है। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम किसी राष्ट्र के विनाश के पक्ष में नहीं हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia Excepting our own nation.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारे देश पर हुए आक्रमण के समय संयुक्त अरब गणराज्य के रवैये का उल्लेख किया गया है। चीन के आक्रमण के दौरान संयुक्त अरब गणराज्य की राष्ट्रपति परिषद ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था जिसमें युद्ध विराम का प्रस्ताव किया गया था और चीनी सेना के 4 सितम्बर वाली स्थिति में वापिस जाने की बात कही गई थी। (अन्तर्बाधायें) ।

श्री जी० मी० कृपलानी : प्रधान मन्त्री राष्ट्र के दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं कर रही हैं............(अन्तर्बाधाय)

अध्यक्ष महोदय : इससे इस गम्भीर मामले पर विचार ठीक प्रकार नहीं हो सकेगा ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : The position regarding CIA's part in the elections should be clarified.

Shri M.I.S ndhi (New Delhi): Why the question of CIA is being brought when such an important matter is being discussed here.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसमें भाग लेने वाले सात देशों में हुए समझौते के अनुसार गाजा में तैनात किये गये भारतीय सैनिकों की वापिसी का उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्रसंघ पर था । महासचिव के साथ यह तय हुआ था कि वहाँ से हटाये गये सैनिकों को वापिस लाने के लिए एक विमान 8 जून को भेजा जावेगा । भारत अपने सैनिकों को पहले ही वापिस बुलाने के लिए उत्सुक था परन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उन्हें विमान द्वारा वापिस बुलाने में सहमत होने में असमर्थता व्यक्त की । मैंने एक बार फिर महासचिव को भेजे गये अपने संदेश में भारतीय सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से दूर हटाने का अनुरोध किया है, यदि वे भारत में नहीं आ सकते हैं तो उन्हें युद्ध क्षेत्र से यथासम्भव शीघ्र हटाया जा सकता है ।

मुझे आशा है कि हम अपना प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा पारित कराने में सफल होंगे । हम किसी भी ऐसे प्रयत्न का समर्थन करेंगे जिससे युद्ध बन्द हो सके और शान्ति स्थापित हो सके ।

सामान्य आय व्ययक 1967-68 सामान्य चर्चा-जारी

GENERAL BUDGET 1967-68 – GENNRAL DISCUSSION

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker *in the Chair*

श्री श्री० ज० डांगे : मैं सरकार से एक बार फिर इस बात का आग्रह करूंगा कि उसे कम से कम चाय, काफी तथा जूतों पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाना चाहिये । पैट्रोल पर उत्पादन शुल्क लगाने का कारण भी समझ में नहीं आता ।

एकाधिकारों पर, विशेषतया उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में; नियंत्रण होना चाहिए और अन्त में एकाधिकार समाप्त कर दिये जाने चाहिये । जब तक मुख्य मुख्य उपभोक्ता वस्तुओं पर राज्य का नियन्त्रण नहीं होता अथवा राज्य उन्हें अपने हाथ में नहीं ले लेता, तब तक मूल्यों के मामले में कोई राहत नहीं मिलेगी । उदाहरण के लिए जब तक चीनी पर एकाधिकार समाप्त नहीं होता और सरकार चीनी मिलों को अपने हाथ में नहीं ले लेती तब तक चीनी मिलों में, गन्ने के कृषकों में तथा उपभोक्ताओं में झगड़े बने रहेंगे । मेरा सुझाव है कि कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जावे ।

जिस प्रकार की वस्तुओं का आयात हो रहा है, वह बन्द होना चाहिए । आयात की वस्तुओं के लिए स्थानापन्न वस्तुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए न कि वर्तमान कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात में ढील दी जाये । मुख्य मुख्य वस्तुओं के आयात-निर्यात व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाना चाहिए और व्यापारियों को इस क्षेत्र से निकाल दिया जाना चाहिये क्योंकि वे अब भी अधिक बीजक बनाने तथा अन्य कदाचारों में लगे हुए हैं ।

विदेशी पूंजी ने, विशेषतया अमरीकी पूंजी से क्या लाभ हुआ है, इसके बारे में सभी जानते हैं, होटल उद्योग अथवा अन्य उद्योगों को जो रियायतें दी जा रही हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है ।

जब तक कृषकों को आत्म-निर्भर नहीं बनाया जाता और जब तक उसे बड़े भूमिस्वामियों के बोझ से नहीं छुड़ाया जाता, तब तक कृषि को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता और कृषक उपज में वृद्धि के लिये उतना अंश नहीं डालेगा जितना कि उसे डालना चाहिए । जब तक ऐसा नहीं किया जावेगा तब तक खाद्य तथा कृषि की समस्या हल नहीं होगी ।

जमींदारी उन्मूलन का लाभ किसानों या काश्तकारों को नहीं मिला क्योंकि अधिकतर काश्तकारों से भूमि जमींदारों ने छीन ली थी । अतः जब तक भूमि सम्बन्धी सुधार नहीं किये जायेंगे तब तक खाद्य समस्या भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी ।

सरकारी कर्मचारियों को दक्षतापूर्वक काम करने, भ्रष्टाचार या रिश्वत पर उपदेश देने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि शासन तन्त्र में जो अवांछनीय तत्व हैं, उन्हें हटाकर ऊंचे स्तर पर अच्छे लोगों को काम करने का अवसर देने से प्रशासन में दक्षतापूर्वक और ईमानदारी से काम करने की समस्या स्वयं ही सुलझ जायेगी ।

एक अन्य बात जिस पर मैं बल देना चाहता हूँ कि लोकतन्त्रात्मक संरचना में और समाजवाद की छाया में किसी भी व्यक्ति को विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा, विशेषाधिकार और असाधारण दर्जा देना उचित नहीं है । इसके विपरीत समाजवादी समाज का अनुसरण करने वाले भारत में भूतपूर्व राजा और महाराजाओं को सरकार द्वारा विशेषाधिकार विशेष दर्जा और निजी थैलियां (प्रिविपर्स) आदि विशेष सुविधायें दी जा रही हैं । वे अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि भूतपूर्व नरेशों को दिये जाने वाले विशेषाधिकार और निजी कोषों की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये जिससे वे सामान्य नागरिक की श्रेणी में आ जायें ।

जहां तक सरकारी खर्च कम करने का सवाल है, मैं यह सुझाव देता हूं कि भारत सेवक समाज जैसी अनेक् बेकार तथा कल्पित संस्थाओं को सरकार की ओर से अनुदान न दिया जाये । इससे लगभग 10 से 15 करोड़ रुपये तक की बचत होगी । साथ ही मैं यह चाहता हूँ कि हमारी आर्थिक नीति विदेशी प्रभाव से प्रभावित न हो । केन्द्रीय कांग्रेसी सरकार की इस नीति का भी मैं विरोध करता हुँ कि गैर कांग्रेसी लोकतन्त्रीय सरकारों का आर्थिक रूप से गला घोटा जाये । यदि उन्हें आर्थिक सहायता न दी जायेगी या उनकी नीतियों के क्रियान्वयन में केन्द्र बाधक होगा तो वे सरकारें असफल हो जायेंगी । केन्द्र सरकार की शायद यही मन्शा है । परन्तु इससे न केवल गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें धराशायी होंगी बल्कि केन्द्रीय सरकार का महल भी ढह जायेगा । अतः मैं केन्द्र से अपील करता हूँ कि वह राज्यों को यथोचित आर्थिक सहायता दें जिससे राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा सके, भू राजस्व समाप्त कर सके ओर सिंचाई आदि की अन्य योजनाओं को पूरा कर सकें ।

यदि मध्य एशिया में युद्ध जारी रहता है तो केन्द्र को अपना बजट दुबारा तैयार करना होगा । परन्तु ऐसा करना वर्तमान सरकार के वश की बात नहीं है यह कार्य भी एक नई सरकार ही कर सकती है । यदि देश को हर प्रकार से मजबूत बनाना है तो सरकार को आत्म निर्भर होना पड़ेगा और आत्म सम्मान के मूल्य को समझना होगा । उसे साम्राज्यवाद विरोधी नीति अपनानी होगी ।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : यह बात वास्तव में सत्य है कि मैनेजर और कार्यकारी अधिकारी के स्तर के कर्मचारियों के वेतन का सम्बन्ध उत्पादन से होना चाहिये। परन्तु साथ ही श्रमिकों पर भी यही नियम लागू होना चाहिये। आजकल श्रमिकों को उनके अधिकारों का तो बराबर ज्ञान कराया जाता है परन्तु उनके कर्त्तव्यों की ओर उनका ध्यान नहीं दिलाया जाता। वस्तुतः उत्पादन का घटना और बढ़ना श्रमिकों की ईमानदारी, देशभक्ति और उनके कठिन परिश्रम पर निर्भर होता है।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : There in no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी जाये। अब सभा में गणपूर्ति है।

श्री हनुमन्तय्या : उत्पादन तभी बढ़ेगा जबकि श्रमिक वर्ग पर भी यथोचित ध्यान दिया जायेगा। हमारा उत्पादन घटने और मुद्रास्फीति बढ़ने का एक मात्र कारण यह है कि हमारे यही कागजी कार्यवाही अधिक होती है। अर्थव्यवस्था को ठीक बनाये रखने का केवल एक उपाय है और वह है उत्पादन को बढ़ाना। उत्पादन घटने का एक कारण यह है कि श्रमिक वर्ग में अनुशासनहीनता स्वार्थीपन की भावना घर कर गई है। यदि श्रमिकों को अधिक अधिकार और सुविधाओं की बात की जाती है, तो उनसे अधिक से अधिक उत्पादन लेने की बात भी की जानी चाहिये। जब सभी स्तरों पर मंजूरी का सम्बन्ध उत्पादन से जोड़ दिया जायेगा तो आर्थिक समस्याएं स्वतः ही हल हो जायेंगी। अब हमें मौलिक अधिकारों की बजाय मौलिक कर्त्तव्यों पर अधिक बल देना चाहिये। मैं किसी भी वर्ग का पक्ष नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि हो। हमारे देश में एक श्रमिक को या एक कार्यालय के चपरासी को भारत में प्रति व्यक्ति आय से अधिक मिलता है, जबकि कुछ आदमी ऐसे भी हैं जिन्हें इनसे भी कम मिलता है। मैं तो सामाजिक न्याय में विश्वास रखता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि मंजूरी तथा वेतनों का सम्बन्ध राष्ट्रीय आय से होना चाहिये।

जहां तक मंहगाई भत्ते का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिक वेतन और मंहगाई भत्ता मिलता है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को कम मिलता है। सब से पहले राज्य सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों की मदद की जानी चाहिये। सामाजिक न्याय तो यही है। यदि वेतन मानों और विभिन्न आय-स्तरों में विद्यमान विषमता समाप्त हो जाये तो सामाजिक न्याय की स्थापना हो जायेगी।

केवल एकाधिकार को समाप्त करने से आर्थिक समस्या हल हो जायेगी या मूल्य कम हो जायेंगे, यह बात कुछ हद तक ठीक है। परन्तु रेलवे, बीमा और अनेक सरकारी उपक्रमों में आज सरकार की एकाधिकार चल रहा है। गैर सरकारी एकाधिकार समाप्त करके सरकारी ऐकाधिकार स्थापित करना भी हितकर नहीं है। इन एकाधिकारवादी सरकारी उपक्रमों के बन जाने से मजूरी का ढांचा बढ़ता जा रहा है। इनमें परस्पर प्रतियोगिता नहीं होती, इसलिये वे उनकी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाते जितनी क्षमता उनमें होती है। इसी कारण उनमें उत्पादन कम होता है। साथ ही कराध्यन में वृद्धि होती जाती है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि सरकारी उपक्रमों में भी परस्पर प्रतियोगिता होनी चाहिये, इससे उनमें कार्य

कुशलता बढ़ेगी। खाद्य के सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि खाद्य पर दी जाने वाली 118 करोड़ रुपये की राज्यों को दी जाने वाली सहायता को समाप्त किया जाना चाहिये जिससे राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य कल पुनः शुरू कर सकते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 7 जून 1967।17 ज्येष्ठ 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 7th June 1967/Jyaistha 17, 1889 (Saka)